भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ओड़िशा राज्य कमेटी का मुखपत्र

जनसंग्राम

अंक 4 - जुलाई 2014 - सहयोग राशि 15रु.

21 सितंबर 2014

भाकपा (माओवादी)
और भाकपा (माले) (नक्सलबाड़ी)
का विलय जिंदाबाद !

संपादकीय...

माओवादी जनयुध्द के ओड़िशा-छत्तीसगढ़ बार्डर में बढ़ते कदम... आईये जनयुध्द को हर तरह की मदद देते हुए जनता के पक्ष में खड़े हों!

21 सितंबर 2014 से महीने भर माओवादी पार्टी की दसवीं बरसगांठ को जोरशोर के साथ मनाओ!

बारस 2004, दिनांक 21 सितंबर, भारत की क्रांति में एक ऐतिहासिक दिन. इस बरस उस दिन को पूरे दस साल हो रहे हैं. एक ऐसा दिन जिसने देश की उत्पीड़ित क्रांतिकारी जनता, क्रांतिकारी ताकतों, प्रगतिशील, जनवाद पसंद बुध्दिजीवियों, भारतीय जनता के सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन कर रही अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी माओवादी ताकतों के दिलों को खुशियों से भर दिया था. और एक ऐसा दिन जिसने भारत के दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों, बड़े-बड़े सामंतों, और उनके मालिक विभिन्न साम्राज्यवादी देशों व खासकर अमेरीकी साम्राज्यवाद के दिलों में हड़कंप मचा दिया था. एक ऐसा दिन जिस दिन के बाद देश के प्रधानमंत्री ने कहा - माओवादी देश की आंतरीक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है! वह दिन था दोस्तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (पीपूल्सवार) और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया (एमसीसीआई) के विलय का दिन! अलग-अलग धाराओं के रुप में आंदोलन चला रही ताकतों की एकजुटता का दिन!

संपादकीय - पार्टी का दसवें स्थापने दिवस पेज 01
साक्षात्कार - कामरेड संग्राम, (ओड़िशा प्रभारी, सीसी सदस्य भाकपा (माओवादी) पेज 05
पुलिस दमन और जन प्रतिरोध पेज 11
श्रधांजली - कामरेड बरुण दा पेज 16
प्रैस विज्ञप्तियां पेज 23
सैध्दांतिक लेख - पध्दति स्तालिन पेज 28
श्रृंखला - भगतसिंग की बात सुनो माओवाद की राह चुनो
लेख - अछूत समस्या पेज 30
हिंदू फासीवाद का खतरा... 33

दरअसल खतरा देश की आंतरीक सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि माओवादी पार्टी के नेतृत्व में चल रहा जनयुध्द दलाल बड़े पूंजीपतियों, विदेशी कंपनियों और जमींदारों द्वारा जारी लूट को था. देश के शोसक-शासकों को पता था कि दो बड़ी माओवादी पार्टियों के विलय से माओवादी आंदोलन न केवल अखिल भारतीय स्वरुप का आंदोलन बन जायेगा बल्कि उसकी सैनिक ताकत भी बढ़ जायेगी. यही हुआ! माओवादी पार्टी ने अपनी पीएलजीए की मदद से भारतीय क्रांति को ऐतिहासिक रुप से आगे बढ़ाया है. न केवल सैनिक रुप से बल्कि राजनैतिक रुप से भी माओवादी पार्टी भारत की शोषित-उत्पीड़ित जनता के लिए एक विकल्प बनकर उभरी है. दुनिया भर की माओवादी, क्रांतिकारी ताकते, विश्व समाजवादी क्रांति में भाकपा (माओवादी) के बढ़ते योगदान की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है. माओवादी पार्टी खासतौर से देश के सबसे उत्पीड़ित, पिछड़े, सरकारों द्वारा सदियों से उपेक्षित आदिवासी इलाकों में काफी हद तक लूटेरी, विदेशी व बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लूट के सामने एक चुनौती पेश कर रही है, एक हद तक उनकी लूट पर अंकुश लगा पाई है. वन विभाग द्वारा किये जाने वाले शोषण-उत्पीड़िन, लूट, महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़, बेगारी आदि पर रोक लगा पाई है, उसने आदिवासी जनता का सम्मान और इज्जत के साथ जीना सीखाया है, अपने अधिकारों के लिए सशस्त्र होकर लड़ने के लिए प्रेरित किया है, आज देश के आदिवासी अपने जल-जंगल व जमीन के लिए जी-जान से लड़ रहे हैं. आज वह नारा लगा रहे हैं कि जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे!

पार्टी विलय के एक साल बाद यानि 2005 में यूएपीए सरकार ने एक तरह से देश की जनता के खिलाफ अघोषित युध्द छेड़ दिया. माओवादी पार्टी के निर्मूलन के लिए केंद्रीय स्तर पर अभूतपूर्व रुप से प्रयास तेज हो गए. 5 जून 2005 को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला ग्राम कुटरु से सलवा जुडूम की शुरुआत हुई. हालांकि राज्य में भाजपा की सरकार थी, लेकिन सलवा जुडूम की अगुवाई छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के विपक्ष नेता महेंद्र कर्मा ने की. इस से साफ पता चलता है कि कंग्रेस व भाजपा दोनों मिलकर माओवादी पार्टी के निर्मूलन के लिए एकजुट थीं. आखिर सत्तापक्ष व विपक्ष एक हुआ

कैसे! इसके पीछे साजिश गहरी थी. जिसका पर्दाफास होने में कुछ समय लगा. पहले तो सलवा जुडूम को एक स्वत:स्फूर्त आंदोलन बताया गया, लेकिन जब पता यह चला कि एस्सार और टाटा जैसी कंपनियां इस को धन उपलब्ध करवा रही हैं, जनता के लिए बनाए गए दमन शिविरों को चला रही हैं तो मसला साफ हो गया. इनके पीछे विदेशी कंपनियां व देश के बड़े कॉरपोरेट समूह हैं. दरअसल 2005 जून में ही लोहंडीगुड़ा में 19 हजार 500 करोड़ का निवेश टाटा ने किया था. एस्सार समूह को भी किरंदूल से विशाखपटनम तक पाईपलाईन बिछाने की मंजूरी मिली थी. सलवा जूडुम फासीवादी अभियान ने 600 से ज्यादा गांवों को जला कर राख कर दिया, सैकड़ों महिलाओं के साथ सरकारी सशस्त्र बलों, विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) ने सामूहिक बलात्कार किये, फसलों को तबाह कर दिया, और हजार से ज्यादा लोगों को मार डाला. लेकिन बस्तर की आदिवासी जनता ने, हमारी पार्टी के नेतृत्व में, और प्रगतिशील, जनवादी बुध्दिजीवियों, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के समर्थन से इस फासीवादी दमन अभियान को नाकों चने चबवाए. विश्वस्तर पर माओवादी जनयुध्द को समर्थन प्राप्त हुआ. पीएलजीए ने लड़ते हुए युध्द को सीखा और दुश्मन के फासीवादी बलों को करारे सबक सिखाए. हजारों की संख्या में जन मिलिशिया का गठन हुआ, सैकड़ों मिलिशिया सदस्य पीएलजीए में भर्ती हुए और देश की मुक्ति की लड़ाई में कूद पड़े. दंडकारण्य में इस क्रूर दमन का सामना करते हुए जनता ने ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक अपनी जनताना सरकारों का निर्माण किया. आज जोन स्तरीय जनताना सरकार बनाने की तरफ दंडकारण्य की जनता आगे बढ़ रही है.

क्रांतिकारी जन कमेटी (जनताना सरकार) अपने कृषि विभाग के जरिये हजारों एकड़ जमीन को खेती योग्य बनाने में कामयाब हुई है. लाखों महिला-पुरुषों, बच्चों, बुर्जुगों और जनमिलिशिया, पीएलजीए की मदद से यह संभव हो सका है. उसने अपने शिक्षा विभाग के तहत स्कूलों का संचालन शुरु किया है जिसमें सैकड़ों बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. जनताना सरकार के अपने स्वास्थ्य विभाग है जिसके जन डॉक्टर हजारों जनता तक निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रहे हैं. जनताना सरकारों के नेतृत्व में सहकारी आंदोलन आगे बढ़ रहा है. न्यायीक विभाग बिना देरी किये, जनता से ही न्यायधिश चुन कर फैसले सुना रहा है, बिना देरी व बिना खर्च जनवादी फैसले जनता को मिल रहे हैं. इन जनताना सरकारों के संचालन में उनकी सुरक्षा करते हुए जन मिलिशिया अहम योगदान निभा रहा है. जनताना सरकारों का सुरक्षा विभाग इसका संचालन करता है.

सलवा जुडूम की करारी हार के बाद तिलमिलाए शोषक-शासक वर्गों ने कोबरा फोर्स का गठन करके और भी क्रूर और फासीवादी ऑपरेशन ग्रीनहंट अभियान की शुरुआत की. यह क्रूर अभियान आज भी जारी है. लेकिन हमारी पीएलजीए और क्रांतिकारी जनता इसका डटकर मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रही है.

इस दौरान जनता का दमन करने वाले फासीवादी बलों का पीएलजीए ने जनता की मदद से बहादुरी पूर्ण मुकाबला किया और उस पर कई ऐतिहासिक हमले किये. दंडकारण्य में रानीबोदली, उरपलमेट्टा, लाहेरी, टव्वेटोला, मदनवेड़ा, कोंगेरा, ताड़मेटला, मुकरम, ओड़िशा में नयागढ़, बालिमेला, कलिमेला, बिहार-झारखंड में लखिसराय, सारंडा, गिरडिह, पश्चिम बंगाल में सिलदा रेड आदि प्रमुख है. सैकड़ों दुश्मनों का सफाया कर सैकड़ो हथियार पीएलजीए ने जब्त किये हैं. वहीं जहानबाद, लखिसराय, दंतेवाड़ा आदि जेल ब्रेक कर कई वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं व सैकड़ो निर्दोष जनता को छुड़वाने में हमारी पार्टी कामयाब हुई है.

इन दस सालों में हमारी पार्टी ने कई ऐतिहासिक जन आंदोलनों को खड़ा किया है, उनमें भागीदारी की है. जनता के हर जायज आंदोलन के साथ हमारी पार्टी खड़ी रही है.

1967 में पश्चिम बंगाल ने नक्सलबाड़ी विद्रोह खड़ा कर देश की क्रांति को नई राह दिखाई थी. एक बार फिर माओवादी पार्टी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की जनता विस्थापन के खिलाफ उठ खड़ी हुई और पूरे भारत के विस्थापन विरोधी आंदोलनों को राह दिखाई. पश्चिम बंगाल के सिंगुर में टाटा कंपनी को भागना पड़ा, नंदीग्राम से इंडोनेशिया के सलेम ग्रुप को अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा और लालगढ़ इलाके से बड़े व दलाल पूंजीपति जिंदाल को उलटे पांव लौटना पड़ा. इतना ही नहीं 35 सालों से जड़ जमा कर बैठे सामाजिक फासीवादी नकली मार्क्सवादियों के शासन को भी जनता ने उखाड़ फैंका. अमर शहीद, भारतीय क्रांति के प्यारे नेता कामरेड किशनजी की रहनुमाई में लालगढ़ की जनता ने नक्सलबाड़ी विद्रोह की याद ताजा कर दी. इस ऐतिहासिक विद्रोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनता का समर्थन प्राप्त हुआ. केंद्र व राज्य सरकारों की नींद हराम कर दी गयी.

ओड़िशा में पीछले दस सालों में माओवादी आंदोलन बालको, नालको, वेदांता, पोस्को, टाटा, मित्तल, जिंदल आदि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए लाल भूत बनकर खड़ा हुआ है. खदान माफियाओं के लिए सिरदर्द बन गया है. माओवादी पार्टी के समर्थन व नेतृत्व में ओड़िशा की जनता खासकर आदिवासी जनता विस्थापन व शोषण के खिलाफ उठ खड़ी हुई है. खासतौर से बॉक्साईट के अंतर्राष्ट्रीय माफियाओं से

जनता टक्कर ले रही है. कहा जाता है कि बॉक्साईट की खदान खोलने वाली कंपनियों दुनिया के किसी भी कौने में नहीं हारी, शाम-दाम-दंड-भेद से खदाने खोल लेती हैं, चाहे उसके लिए देशों का तख्तापल्ट क्यों न करवाना पड़े लेकिन ओड़िशा की जनता ने उनकी लूट को चैलेंज किया है. नियमगिरी, गंदमर्दान पहाड़ों को अपना देवता मानकर जनता उनकी रक्षा के लिए जीवन मरण का संघर्ष कर रही है. जनता के संघर्ष की बदौलत नियमगिरी में तो खुद सुर्पीम कोर्ट में फैसला सुनाना पड़ा की जनता से अनुमति लिए बिना कोई खदान कार्रवाई शुरु नहीं होगी. यह बात अलग है कि चुनावों के समय फिर सरकार ने पिछले दरवाजे से खनन की अनुमति दे दी. कलिंगनगर में टाटा, जगतसिंगपुर में पोस्को, लांजीगढ़-नियमगिरी में वेदांता के खिलाफ जनता निर्णायक लड़ाई लड़ रही है.

नारायणपटना के आदिवासियों की लड़ाई ने फिर एक बार जमीन जोतने वाले व सामंती शोषण को भारतीय राजनीति के पटल पर रखा. संशोधनवादी पार्टियों के अवसरवादी नेतृत्व से मुक्ति पाकर जनता ने साहूकारों, जमींदारों, सूदखोरों व शराब माफियाओं के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन छेड़ा और विजय हासिल की.

दो महाधाराओं के विलय के बाद 2007 में संपन्न ही एकता कांग्रेस-नौवीं कांग्रेस के दिशा-निर्देशों के अनुसार माओवादी पार्टी ने अपने आंदोलन का विस्तार किया. देश के दो प्रधान जोन दंडकारण्य और बिहार-झारखंड के बीच के इलाके यानि ओड़िशा को इस विस्तार के लिए महत्वपूर्ण माना गया. आज हमारी ओड़िशा राज्य कमेटी इस महत्वर्पूण कार्यभार को लेकर आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है.

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला के नगरी-सिहावा व रायपुर जिला के गरियाबंद, मैनपुर ब्लॉक से इस विस्तार की शुरुआत हुई. अब वह इलाका गरियाबंद जिला में आता है. सबसे पहले मैनपुर डिवीजन का गठन हुआ. डीकेएसजेडसी के नेतृत्व में यहां आंदोलन के विस्तार की शुरुआत हुई थी. 2007 में एक प्लाटुन की संख्या हमारी पार्टी धमतरी जिला के नगरी-सिहावा, सीतानदी एरिया में कदम रखी. उसके बाद रायपुर जिला के गरियाबंद, मैनपुर, उदंती एरिया में आगे बढ़ी. जनता ने दिल खोल कर स्वागत किया जैसे वह बरसों से हमारे आंदोलन का इंतजार कर रही हो. जहां भी दस्ता जाता लोग स्वागत के लिए खड़े होते, लाल सलाम करते और अपनी समस्याएं सामने रखते. जनता जंगल-पहाड़ों में पार्टी को देखने के लिए आती थी. क्योंकि यह इलाका सितानदी-उदंती वन अभ्यारण्य में आता था. वहीं ओड़िशा के नुआपाड़ा जिला का सोनाबेड़ा इलाका भी एक वन अभ्यारण्य है. ये दोनों सटे हुए हैं. इस प्रकार सीतानदी, उदंती, सोनाबेड़ा की आदिवासी जनता सालों से इन वन अभ्यारण्यों के खिलाफ लड़ रही थी. वन विभाग इनका मनमाना शोषण करता था. वनों से लकड़ी लाना, तेंदुपत्ता तोड़ना, गाय-भैंस चराना, वनोपजों का संग्रहण करना आदि सब मना था. कोई खेती के लिए जमीन नहीं काट सकता था. अगर ऐसा कोई करता तो वन विभाग केस लगा कर जेल भेज देता था. जनता कोर्ट की तारीख पर तारीख के चक्कर में पड़ कर कंगाल बन जाती थी. मजबूरीवश वन विभाग के गार्ड से लेकर डीएफओ तक को रिश्वत देनी पड़ती थी. जनता इन सब से बहुत तरस्त थी. जैसे ही पार्टी ने कदम रखे फारेस्ट डिर्पाटमेंट अपनी वर्दियों को लगाना छोड़ दिया और अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया. बरसों से संघर्ष कर रहे और लूट रहे लोगों को बहुत चैन मिला. उनका सबसे बड़ा दुख दूर हो गया. इस प्रकार पार्टी को जनता 'भगवान' की तरह देखती व दूर दूर से अपने गांव में आने का न्यौता भेजती थी. आज यह आंदोलन ओड़िशा और छत्तीसगढ़ कई जिलों में फैल गया है.

वन विभाग के भागने से हजारों भूमिहीन किसानों, बड़ी संख्या में गरीब किसानों को भी जमीने मिलीं. लगभग सभी गांवों से भूमिहीनता की समस्या तो दूर हुई है. इसी तरह लघु वनौपजों के संग्रहण की अनुमति देने, तेंदुपत्ता तोड़ाई की मजदूरी बढ़वाने के लिए भी हजारों जनता जन आंदोलनों में गोलबंद हुई. तेंदुपत्ता तुड़वाई की मजदूरी बढ़वाने के लिए 2012 में नुआपड़ा जिला मुख्यालय पर 3000 के आसपास लोगों ने रैली की. वनोपज के दाम बढ़वाने के लिए तुरेकेला में 5000 से ज्यादा लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. जनता ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और बंद का आव्हान दिया, जो सफल रहा. भावसिल, कटिनपानी आदि गांवों में साहूकारों, बड़े व्यापारियों व जमींदारों की जमीनों को जनता ने जब्त किया.

पार्टी का प्रभाव दूर-दूर तक फैला. इसको देख कर 2010 में मैनपुर डिवीजन से फिर आंदोलन विस्तार हुआ. पार्टी के नेतृत्व में ओड़िशा बरगढ़, बलांगिर और छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिलों तक विस्तार किया. इस विस्तार के दौरान हमारे कई प्रिय कामरेड शहीद हुए. लेकिन आज उनकी बदौलत हमारी पार्टी बरगढ़-बलिंगर-महासमुंद डिवीजनल कमेटी का गठन कर जनता को क्रातिंकारी आंदोलन में गोलबंद कर पा रही है. उस इलाके में जमींदारों के खिलाफ जनता उठ खड़ी हुई है. सामंती शोषण को चुनौती दे रही है. सूदखोरों द्वारा जब्त की गयी जमीन व गिरवी रखवाई जमीन को जनता ने संघर्ष फिर से वापिस अपने हाथों में लिया है. आज फिर वह किसान अपने खेतों को जोत रहे हैं.

वन अभ्यारण्यों के खिलाफ जनता लगातार संघर्षरत है. अभ्यारण्य के गांवों में न तो पीने के लिए पानी की सुविधा है, न खेती के लिए अनुमति और सिंचाई की सुविधा

है. बिजली के कनेक्शसन नहीं दिये जाते, लघु वनोपज के संग्रहण पर पूरी तरह से प्रतिबंद है. जमीनों का पट्टा भी नहीं दिया जाता. इन तमाम समस्याओं को लेकर सीतानदी और उदंती की जनता के संघर्ष को दबाने के लिए कई आंदोलनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया. इसके खिलाफ 2009 में ग्रामीणों को रिहा करने की मांग करते हुए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हजारों जनता ने विरोध प्रदर्शन किया. मैनपुर पुलिस थाना के सामने हजारों महिला व पुरुषों ने चक्काजाम किया.

बलांगिर जिला के लाटूर में दारु माफिया घासीराम अग्रवाल ने दलितों के घरों पर हमले करवाये, उनके घरों को जला दिया. इसका विरोध करते हुए घासीराम अग्रवाल की दो दारु की भट्टीयों को जलाया गया. जनता ने घासीराम पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए जुझारु आंदोलन किया.

गंदमर्धान पहाड़ बलांगिर-बरगढ़ जिलों में है, यहां ओड़िशा में बॉक्साइट के दूसरे सबसे बड़े भंडार हैं. एल्युमिनियम कंपनी बालको यहां पर अपनी गिध्द दृष्टि जमाये हुए है. लगभग तीस सालों से जनता लगातार इन खदानों के विरोध में आंदोलनरत है और अपने खनिज भंडारों की रक्षा कर रही है. गंदमर्धन बॉक्साइड खदन विरोधी आन्दोलन का हमारी पार्टी समर्थन करती है। माओवादी पार्टी के यहां विस्तार होने के बाद जनता में नया जोश आया है.

बलांगिर जिला पुजारपली में बांध का निर्माण किया जा रहा है जिसमें 27 गांव डूब जाने का खतरा है. इस बांध के विरोध में 2011 से आंदोलन जारी है. विस्थापन के खिलाफ जनता अपनी आवाज ऊंचा उठाये हुए है. जिस कारण 27 गांवों विस्थापन के खतरे से बच गए हैं.

गंदमर्धान से निकलने वाली नदियों पर कई बांध प्रस्तावित हैं. इन्हीं में से एक है लोयार सुकतेल बांध. इसकारण से दर्जनों गांवों विस्थापित हो जायेंगे और हजारों एकड़ कृषि व वनभूमि का नाश होगा अलग. इसलिए जनता लोयर सुकतेल बांध निर्माण के खिलाफ भी आंदोलन का झंडा उठाये हुए है.

क्रांतिकारी आंदोलन विस्तार से पहले ओड़िशा के नुआपाड़ा व छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिलों के ज्यादातर इलाकों में गांजा माफिया, वन विभाग व पुलिस की मिलीभगत से गांजा की खेती होती थी. भुखमरी व गरीबी का शिकार आदिवासी जनता उनके चंगुल में फंसी हुई थी. लेकिन जब क्रांतिकारी आंदोलन ने अपनी आमद दर्ज करवाई तो वन विभाग के साथ-साथ गांजा तस्करों को भी यहां से भागना पड़ा. जनता ने भी अपनी खेती-बाड़ी पर ध्यान देकर अपने विकास की शुरुआत की.

इलाके में आदिम जनजाति कमार का निवास स्थान है. कमार जाति बेहद पिछड़ी है. वह खेती बाड़ी करना नहीं जानती. जंगल से बांस लाकर उससे सूप, टोकरी, डलिया आदि बनाकर अपना जीवनयापन करती है. उसका मुख्य पेशा हस्तशिल्प ही है. लेकिन जंगल से बांस लाना कमार जनता के लिए बड़ी परेशानियां खड़ी करता था. सेंचूरी के नाम से वन विभाग मनमानी लूट करता, उनके दारु-मुर्गों की मांग करता और उनको जेल भेजने की धमकियां देता था. जनता वन विभाग के अमले से बहुत परेशान थी. लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन के विस्तार के बाद कमार जनता से वन विभाग का खोफ खत्म हुआ है और उसने हस्तशिल्प के साथ-साथ खेती बाड़ी करना भी शुरु किया है. उनको पिछड़े पन की दलदल में धकलने का काम सरकार व वन विभाग का ही है जो उनको न तो बांस भरपुर काटने देता था न ही घर व खेती करने के लिए जमीन ही काटने देता था. अब क्रांतिकारी आंदोलन की ताकत के बल पर वह अपनी किस्मत खुद लिख रहा है. क्रांतिकारी जन संगठन लगातर उसे खेती-बाड़ी करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनको बीज, खाद, हल-बैल, इंजन आदि हर प्रकार की मदद दे रहे हैं.

इस इलाके में जंगल भरपुर होने के चलते और मैदानी इलाकों में फसलों से भरे खेत होने के चलते भैंस, बकरी, ऊंट, भेड़ आदि चराने वाले लोग पहाड़ के ऊपर डेरा डालते हैं. लेकिन वन विभाग इनको भी अपनी लूट का शिकार बनाता रहा है. भैंस वालों का दूध, घी, भेड़-बकरी वालों से बकरों की मांग करके उन्हें लूटता था. मनमर्जी से बकरियां उठा कर ले जाता था. जो उसे नहीं देते उन्हें केस लगाने की धमकियां दी जाती थीं. लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन के बल पर आज बेखोफ होकर चरवाहे अपना जीवन यापन चला रहे हैं.

कहते हैं बिना रोए तो मां भी दूध नहीं देती. मतलब बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता. कमार, भूंजिया, कुव्वी, गोंड जैसी जनजातियों को सरकार दशकों उपेक्षित रखती आई है. उनके प्रति सरकार ने सौतेला रवैया अपनया है. उनकी अनदेखी की है लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन ने आज आदिवासी जनता के मुद्दों को न केवल भारतीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का मुद्दा बना दिया है. आज सरकार को उनके 'क्लयाण' के लिए 'योजनाओं' की घोषणा करनी पड़ रही है. झूठे सुधारों को लागू करना पड़ रहा है. तहसिलदार तक जिन इलाकों में झांक कर नहीं देखता था वहां केंद्रीय केबिनेट मंत्रियों को आना पड़ रहा है. जनता इसे 'चमत्कार' कहती है.

शेष पेज 18 पर

जनमुक्ति गुरिल्ला सेना (पीएलजीए) में भर्ती होकर अपने देश व प्रदेश को बचाने के लिए सशस्त्र संघर्ष में कूद पड़ें : संग्राम

ज.सं. - पार्टी ने क्या सोचकर, या किस लक्ष्य से छत्तीसगढ़-ओड़िशा बार्डर एरिया में विस्तार का निर्णय लिया था ?

सं. - छत्तीसगढ़-ओड़िशा बार्डर में क्रांतिकारी आंदोलन 2007 में विस्तार हुआ. यहां विस्तार करने का निर्णय हमारी केंद्रीय कमेटी ने 2007 में संपन्न हुई एकता कांग्रेस के बाद लिया था. तब बिहार-झारखंड और दंडकारण्य को आधार इलाका बनाने का लक्ष्य भी हमारी कांग्रेस ने हमारे सामने रखा था. दूसरा 2005 से दंडकारण्य में सलवा जुडूम नाम से भयंकर सैनिक फासीवादी दमन अभियान चल रहा था. इसलिए इस विस्तार के पिछे हमारी सोच यह थी कि बिजे और डीके, दो प्रधान जोनों के बीच के इलाके में आंदोलन का विस्तार किया जाये. अगर डीके-बिजे का आधार इलाका बनाना है और दुश्मन बलों के साथ दमन का प्रतिरोध करने में प्रधान जोनों को मदद देनी है तो यह छत्तीसगढ़-ओड़िशा बार्डर एरिया में आंदोलन का विस्तार कर के हो सकता है.

इसलिए हमारा लक्ष्य है - दंडकारण्य, बिहार, झारखंड को आधार इलाका बनाना, गुरिल्ला युध्द को चलायमान युध्द में तब्दील करना, पीएलजीए को पीएलए में विकसित करना. एकता कांग्रेस-नौवीं कांग्रेस के कर्तव्य को सफल करने के लिए आगे बढ़ाना, और अन्य इलाकों में वर्ग संघर्ष का विकास करना, गुरिल्ला बेसों और लाल प्रतिरोध इलाकों के निर्माण करने के लक्ष्य से आगे बढना है, खासकर बिजे व डीके के बीच में लाल आधार इलाका निर्माण करने के लक्ष्य से माओवादी पार्टी दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है.

ज.सं. - इस इलाके में पार्टी ने कब कदम रखे ? और उससे पहले क्या-क्या तैयारियां की गयी

सं. - देखिये, किसी भी राज्य, इलाके या शहर में अगर कम्युनिस्ट पार्टी को अपना आंदोलन फैलाना है तो उसको प्राथमिक रुप से सबसे पहले उस इलाके का सर्वे करना पड़ता है. जैसे वहां की सामाजिक अर्थिक परिस्थिति कैसी है. वहां लोगों की अजीविका का मुख्य साधान क्या है. जनता की मुख्य समस्याएं कौनसी हैं. ताकि जनता को उनपर गोलबंद कर वर्ग संघर्ष खड़ा किया जा सके. और अगर पीएलजीए के साथ आंदोलन का विस्तार करना है तो वहां का भौगोलिक सर्वे भी मुख्य होता है. इसलिए सबसे पहले डीके एसजेडसी ने इलाके के सर्वेक्षण का कार्यभार लिया. धमतरी के नगरी सिहावा, सितानदी, विश्रामपुर, रायपुर जिला के गरियाबंद, मैनपुर, उदंती आदि में एक टीम जनता की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए आई थी. लेकिन एक जमीनदार जो गांव का सरपंच भी था के घर में जब वह टीम रुकी तो उसकी जानकारी उसने पुलिस को दे दी और हमारे साथी अरेस्ट हो गए. उनमें से कामरेड गोपन्ना मड़काम अभी भी रायपुर जेल में है. यह सब 2007 के शुरुआती महिनों में हुआ. उसके बाद डीके एसजेडसी ने समिक्षा कर एक प्लाटून की संख्या में पीएलजीए को भेजने का निर्णय लिया. और 2007 अक्तुबर महीने में हमारी पीएलजीए की टुकड़ी सितानदी इलाके में प्रवेश की.

लेकिन इससे पहले ओड़िशा राज्य में 1998 में सीपीआई (एमएल) (पीपुल्सवार) और सीपीआई (एमएल) (पार्टी यूनिटी) के विलय के बाद परिपेक्ष लेके पार्टी वर्ग संघर्ष को आगे बढ़ाई है. बासाधारा से नयागढ़, कंधमाल, नियमगिरी में संघर्ष को विकास करते हुए विस्तार किये हैं. क्योंझर, मयुरभंज, कलिंगनगर संघर्ष को नेतृत्व दिये हैं. सुंदरगढ, देवगढ, संबलपुर इलाका में किसान, मजदूरों को विशाल आदिवासी इलाका में जनता को संगठित किये हैं. पोस्को के विरुध्द जन आंदोलन को मदद दिये हैं. पुजारीपाल, लोयरसुकतेल निर्माण के विरुध्द आंदोलन को हमारा पार्टी समर्थन दी है.

ज.सं. - जब पार्टी यहां पर आई , जनता की तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिली थी ?

सं. - यह हमारे आंदोलन के लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे आने से पहले ही यहां की जनता हमारी पार्टी को खोज रही थी. मिलने के लिए सोचती थी. जब दस्ता सितानदी में प्रवेश किया तो जनता ने दिल खोल कर स्वागत किया. क्योंकि यहां की जनता दशकों से वन विभाग द्वारा किये जाने वाले शोषण से परेशान थी. सरकारी वन कानूनों के दम पर जंगलात विभाग व पुलिस प्रशासन जनता से चोरों जैसा बरताव करता था. जनता यहां सितानदी-उदंती टाईगर रिजर्व के खिलाफ, अपने जल-जंगल-जमीन को बचाने के लिए लड़ रही थी. जंगलात विभाग की लूट से छूट मिलने की आशा जनता की हमारी पार्टी से थी. जब वन विभाग यहां से भाग खड़ा हुआ, जब विभाग के अधिकारियों को जन अदालतों में घसीट कर सजाएं दी गयी, जिन्होंने मजदूरी का भूगतान नहीं किया था, बेगार करवाई गयी थी उनकी मजदूरी दिलवाई गयी तो पूरे इलाके में इसका व्यापक असर हुआ. जनता दूर दूर से आवेदन लेकर

हमारे दस्ता को बुलाने आती थी. अपनी समस्याएं बताती थी और अपने गांव लेकर जाती थी. इस प्रचार का असर यह हुआ कि शहरों-कस्बों से जनता हमें मिलने आती थी. क्योंकि अभी तक इन शहर कस्बों में दुश्मन का प्रचार यह था कि माओवादी तो आतंकवादी और देशद्रोही है. लेकिन जब जनता से उन्हें सच्चाई का पता चला तो वह खुद चल कर हमें मिलने आने लगी. जनता 'भगवान' जैसे देखती थी. क्योंकि जंगल विभाग के खिलाफ भी कोई खड़ा हो सकता है, उसे भगा सकता है यह उसे विश्वास नहीं था. कई घटना तो ऐसी है कि जब हम डेरा बदल कर दूसरी जगह चले जाते थे और जनता हमें ढूंढते-ढूंढते आती तो उसे डेरा खाली मिलता था, तब वह वहां से चुल्हों की बची राख को घरों में ले जाती और भगवान का प्रसाद बताती थी.

ज.सं. - एक डिवीजन से एक जोन तक विकसित होने की प्रक्रिया को एक बार समझाइये. कैसे-कैसे आंदोलन आगे बढ़ा ?

सं. - आज ओड़िशा राज्य कमेटी के नेतृत्व में अभी छत्तीसगढ़ का धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद और ओड़िशा का नुआपाड़ा, बरगढ़, बलांगिर, नवरंगपुर व कालाहंडी, रायगढ़, सुदंरगढ़, देवगढ़, संबलपुर आदि जिले आते हैं. पूरे जोन में जनता साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी और खासतोर से विस्थापन के विरोध में व्यापक संघर्ष चला रही है. इस इलाके में मुख्यत: मांझी, कमार, भुंजिया, चौखट भुंजिया, कोंध, कुवी, बंडा जैसी आदिम जनजातियां निवास करती हैं. पूरे इलाके में खनिजों के प्रचूर भंडार हैं. जिसमें बॉक्साईट, कोयला, लोहा प्रमुख है. इसलिए बड़ी-बड़ी विदेशी कंपनियां, दलाल पूंजीपतियों की कंपनियां बड़ी-बड़ी परियाजनाएं चला रही है और बहुत सारी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं. इलाके के जल का दोहन पूरी तरह से इन बड़ी कंपनियों के लिए ही किया जा रहा है. सिकासर, सुंडरू, हिराकुड जैसे कई बांध है जिस कारण हजारों परिवारों को विस्थापित होना पड़ा है. धमतरी का सितानदी, गरियाबंद का उदंती और नुआपाड़ा का सोनाबेड़ा एरिया की जनता पर टाईगर रिजर्व के नाम से विस्थापन की तलवार लटक रही है. बरगढ़-बलांगिर में गंदमर्धान पहाड़ों पर बॉक्साईट के बड़े भंडार है. कुल मिलाकर देखा जाये तो विस्थापन एक बड़ा मुद्दा है. हमारी पार्टी सितानदी इलाके में सबसे पहले आई थी, तब जनता टाईगर रिजर्व के खिलाफ संघर्षरत थी, उदंती व सोनाबेड़ा भी इसी से सटा हुआ है. इस प्रकार यह समस्या धमतरी, गरियाबंद और ओड़िशा के नुआपाड़ा जिलों की व्यापक जनता की समस्या थी. जनता के संघर्ष को पार्टी ने समर्थन दिया. इसके अलावा और किसानों के कई मुद्दों को भी उठाया. इस प्रकार जनता संगठित होती गयी. सबसे पहले मैनपुर डिवीजन का गठन हुआ. इस डिवीजन में सितानदी, उदंती और नुआपाड़ा का सोनाबेड़ा इलाका भी आता था. फिर जब एरिया बहुत बड़ा हो गया और काम बढ़ गया तो मैनपुर डिवीजन को दो भागों में बांट कर 2012 एक नई डिवीजन नुआपाड़ा का भी गठन किया गया. नुआपाड़ा से सटे हुए बलांगिर, बरगढ़, महासमुंद की जनता भी हमारी पार्टी से प्रभावित हुई. वहां से भी जनता पार्टी को बुलावा भेजने लगी. दूसरी तरफ ऑपरेशन ग्रीनहंट के तहत बढ़ते दमन के कारण इलाके का विस्तार करना भी जरुरी हो गया था. इस प्रकार 2010 में फिर एक बार आंदोलन को विस्तार करने का लक्ष्य रखा और एक कंपनी की संख्या में पीएलजीए के बल बरगढ़, बलांगिर, महासमुंद में गए और क्रांतिकारी आंदोलन की नींव रखी. इसमें हमारे कई प्रिय कामरेडों ने अपने प्राणों की आहुती दी. महासमुंद के पड़किपल्ली गांव में दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करते हुए हमारे 6 साथी शहीद हुए, जिसमें डीवीसीएम कामरेड आयतु भी थे. इस विस्तार के बाद बलांगिर-बरगढ़-महासमुंद डिवीजन का गठन हुआ. तीन डिवीजनों को मिलाकर छत्तीसगढ़-ओड़िशा बार्डर (सीओबी) जोनल कमेटी का गठन गया.

ओड़िशा के कालाहांडी, जगतसिंगपुर, काशिपुर, सुंदरगढ़, देवगढ़, संबलपुर आदि जिलों में पहले ओड़िश स्टेट आर्गनाइजिंग कमेटी (एसओसी) के नेतृत्व में काम जारी था. लेकिन सब्यसाची पंडा की गद्दारी के बाद उस कमेटी को भंग कर दिया गया और सीओबी के इलाके व एसओसी के तहत आने वाले इलाकों को मिलाकर पिछले साल ओड़िशा राज्य कमेटी का गठन किया गया है.

एक डिवीजन से जोन बनने तक की प्रक्रिया में हमारे शहीद कामरेडों का अहम योगदान है. इस दौरान हमने कई जन आंदोलनों, जनसंघर्षों को संगठित किया है. दुश्मन पर भी कई करारे हमले किये है. हमारी पार्टी अपनी आत्मरक्षा करते हुए, दुश्मन पर हमले करते हुए जनता में मजबूत पकड़ बनाने में सफल हुई है.

ज.सं. - जनता का समर्थन व पार्टी के बढ़ते प्रभाव को देखकर सरकार की तरफ से किस प्रकार की प्रतिक्रिया आई ?

सं. - पार्टी के बढ़ते प्रभाव को देखकर केंद्र व राज्य सरकार ने दमन घेराव अभियान को और तेज किया है. धीरे-धीरे कार्पेट सैक्यूरिटी तरीका से पुलिस थाने, कैंप बढ़ाए हैं. बड़ी संख्या में अर्ध सैनिक बलों, एसओजी व अन्य बलों को तैनात किया गया है. नए पुलिस थाने, कैंप लगाकर एरिया को सैनिक छावनी में तब्दील कर दिया है. एरिया डामिनेशन, कुंबिंग हमेशा जारी रहती हैं.

कई झूठी मुठभेड़ें दुश्मन द्वारा की गयी है. जोलाराव में हमारे दस्ते को घेर कर सफाया करने की मंशा से हमला किया गया. उसमें हमारी तीन एरिया कमेटी सदस्य व बहादुर महिला कामरेड्स समीरा, अमीला और अरुणा शहीद हुई. कलिंगनगर, नियमगिरी, नारायणपटना जन आंदोलनों के ऊपर सरकार के पुलिस बल क्रूर तरीके से दमन, फायरिंग आदि करके 12 लोग को कलिंगनगर में, नारायणपटना में सिंगन्ना आंदू जैसे नेतृत्वकारी लोगों को मार डाले. विस्तार एरिया में आए पीएलजीए बलों के ऊपर षडयंत्रकारी हमला करके पीएलजीए के 6 व गांवों के 2 लोगों मार कर आंदोलन को रोकने की कोशिश किये हैं. सैकड़ों जनता को अरेस्ट कर जेल में डाल दिये हैं. पैकमाल में कामरेड आजाद, (बीबीएम डीवीसीएम) कामरेड रामबत्ती, श्यामबत्ती को हिरासत में लेकर दोनों राज्यों के केस लगाए हैं. बलांगिर में जनता के संघर्ष का नेतृत्व कर रहे माधव ठाकूर व रमेश साहु को भी फर्जी मुठभेड़ में मार डाला गया.

कोरापुट मलकानगिरी आदिवासी किसान आंदोलन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है. दर्जनों कार्यकर्ताओं की झूठी मुठभेड़ों में हत्याएं की गयी हैं. कामरेड माधव की हिरासत में लेकर हत्या कर दी, बाद में झूठी कहानी बनाई गयी. 2013 में क्लयाणसिंग पुर एरिया में तीन ग्रामीणों की हत्याएं कर दी. नवीन पटनायक रमन सिंग सरकार ने जनता को भयावह स्थिति में डाल कर जन मिलिशिया, जन संगठनों के नेतृत्व की हत्याएं कर जन आंदोलन को कुचलने के लिए दमन घेराव को बढ़ा रहे हैं. केंद्र व राज्य सरकार ने ग्रीनहंट नामक सैनिक अभियान के साथ जनता को गुमराह करने के लिए सुधार मुहिम भी तेज की है.

एक गहरी साजिश के साथ सरकार व पुलिस प्रशासन ने दुश्प्रचार युध्द भी शुरु से ही हमारे आंदोलन के खिलाफ शुरु कर दिया था. एसपी ऑफिस या एसपी अन्य झूठे संगठनों का खड़ा कर हमारे खिलाफ लगातार पोस्टर, पर्चा छाप रहे हैं. माओवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए उसके नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर गलत व झूठे आरोप लगा रहे हैं. किंतू जनता ने सदा ही इन झूठे आरोपों को नकारा है.

केंद्र राज्य सरकारों का जन विरोधी नीतियों के विरुध्द में जनता को संगठित कर वर्ग संघर्ष को संगठित रुप देने का प्रयास करते हुए हमारी पार्टी आंदोलन को आगे बढ़ा रही है. विस्थापन के खिलाफ आंदोलन पोस्को, कलिंगनगर, नियमगिरी, गंधमर्दान, पुजारीपाल, लोयर सुकतेल आदि आंदोलनों को समर्थन देते हुए सरकारी दमन का मुकाबला करते हुए आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है.

ज.सं. - पार्टी ने जनता को किन किन समस्याओं पर संगठित किया ?

सं. - पार्टी ने जनता को शुरु से ही ओड़िशा-छत्तीसगढ़ के इलाके में विभिन्न समस्याओं पर संगठित किया. महाजनों द्वारा किसानों के शोषण के खिलाफ, झूठे भू-सुधारों का पर्दाफाश करते हुए क्रांतिकारी भूमि सुधार के लिए यहां जनता को संगठित किया गया है. राज्य व केंद्र सरकार द्वारा दलाल पूंजीपतियों व जनता को विस्थापित करने वाली विदेशी कंपनियों के साथ हुए खदान समझौतों के खिलाफ जनता को कंक्रीट प्रोग्राम देकर संगठित किया गया है. टाईगर रिजर्व के खिलाफ, टाईगर रिजर्व, वन अभ्याण्रयों में वनोपजों के संग्रहण करने के लिए, ठेकेदारों व वन विभाग की मिलीभगत से जनता की हो रही लूट के खिलाफ, तेंदुपत्ता का रेट बढ़ाने के लिए, अभ्यारण्यों में भी तेंदुपत्ता का फड़ खोलने के लिए जनता को संगठित किया गया है. नियमगिरी, कलिंगनगर, नरायणपटना, गंधमर्दान के विस्थापन विरोधी आंदोलनों को आज सब जानते हैं. हमारी पार्टी ने उन आंदोलनों का समर्थन किया है. जनता को संगठित किया है.

दारु के विरोध में जनता को खासकर महिलाओं को संगठित किया गया है. हिंदू कट्टरपंथ के खिलाफ, छुआछुत के खिलाफ, दमन के खिलाफ जनता को संगठित किया गया है. दीर्घकालिन लोकयुध्द से ही जनता की मुक्ति संभव है कहते हुए, जनता को जागरुक किया है. जनता ने चक्काजाम, बंद, रैली, जुलूस आदि तरीकों से अपना विरोध प्रकट किया.

जन.सं. सैनिक रुपसे 2007 से अब तक यहां क्या-क्या सफलतायें प्राप्त की हैं ?

सं. - दुश्मन आंदोलन को कुचलने के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस और अर्ध सैनिक बलों को तैनात कर हमला किया. पीएलजीए की टुकड़ी आने से पहले मुखबिर की सुचना पर एक एसजेडसीएम और दो एरिया कमेटी सदस्यों को हिरासत में लेके एक सप्ताह-दस दिन के बाद कोर्ट में पेश किया. आंदोलन को विस्तार नहीं होने देने के इरादे से वह हमारे दस्तों पर हमले किया. इसके लिए एसपीओ, पुलिस, गुप्त-सैनिकों को रिक्रुट कर पैसा का लालच दिखाकर समाचार जमा करना व उसके बाद हमला करना, जनता को डराना, धमकियां देना भी जारी रखा है। प्रतिरोध किये बिना आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता था. 2009 में मांदागिरी में पीएलजीए ने बड़े हमले को अंजाम दिया. वह विस्तार करने के बाद पहला बड़ा हमला था जिसमें 12 पुलिस जवान मारे गए थे और पीएलजीए ने कई हथियारों पर कब्जा किया था.

सोनाबेड़ा में एक एएसपी सहित 9 पुलिस वालों का हमारी पीएलजीए ने सफाया किया.

वन अभ्यारण्य के खिलाफ लड़ने वाली जनता पर वन विभाग व पुलिस प्रशासन का दमन लंबे समय से जारी था. वन विभाग का सोनाबेड़ा में कैंप था जो जनता पर दमन के लिए कुप्रसिध्द था. पार्टी के नेतृत्व में जनता ना उनका बहिष्कार किया और कैंप को वहां से भागना पड़ा. वहीं मुखबिरों व एसपीओ की सुचना पर सोनाबेड़ा इलाके में दमन के लिए आने वाले पुलिस बलों को भी पीएलजीए ने सजा दी. डेकुनपानी में दो पुलिस वालों मो मार कर तीन हथियारों पर कब्जा किया गया. जिसमें एक एके-47 व एक इंसास सहित एक पिस्तोल भी पीएलजीए ने जब्त किया.

एक तरफ आंदोलन का निर्माण तो दूसरी तरफ मुखबिरों, एसपीओ को सजा देते हुए प्रतिरोध - इस प्रकार सैनिक रूप से अच्छी सफलता प्राप्त हुई है. आंदोलन आगे बढ़ा है.

जन.सं. - बढ़ते दमन के बीच क्या आप आंदोलन का और विस्तार कर सकते हैं?

ज.सं.- क्यों नहीं विस्तार कर सकते? जरुर कर सकते हैं. क्योंकि सरकारी दमन हो या सिविक एक्शन जैसे झूठे सुधार कार्यक्रम जनता की समस्याओं को हल नहीं कर सकते. वह जनता की आंखो में बह रहे आंसूओं को नहीं पोंछ सकते. दर असल सरकार को यह नहीं समझ आ रहा कि जब तक जनता की मूलभुत समस्याएं हल नहीं हो सकती माओवादी आंदोलन के विस्तार को नहीं रोका जा सकता. हमारा आंदोलन जमीन की समस्या से शुरु हुआ था मतलब जमीन जोतने वालों को. आज भी ज्यादातर जमीन पर जमींदारों का कब्जा है और दूसरी तरफ आदिवासियों, गरीब किसानों की जमीनों को साम्राज्यवादियों व दलाल पूंजीपतियों की परियोजनाओं के लिए उनसे छीना जा रहा है. आदिवासियों को अपने ही जल-जंगल-जमीन से बेदखल किया जा रहा है. जब तक यह समस्याएं रहेंगी जनता का गुस्सा सरकारों के खिलाफ फूटता रहेगा. इस समस्या को लेकर कोई भी बुर्जुआ राजनीतिक पार्टी जनता के आंदोलन का नेतृत्व नहीं करेंगी बल्कि उसको दबाने की कोशिश करेगी. वहीं हमारी पार्टी ऐसे आंदोलनों का नेतृत्व करते हुए जनता की मूलभूत समस्याओं का हल करेगी. इसलिए हमारे आंदोलन के विस्तार को कोई ताकत नहीं रोक सकती. हां आंदोलनों में उतार-चढ़ाव निश्चित ही आते हैं और जाते रहेंगे.

जन.सं.- पार्टी और पीएलजीए बलों के लिए क्या संदेश है ?

ज.सं. प्यारे कामरेडो, पार्टी की नौवीं-एकता कांग्रेस ने और देश की जनता ने हमें बड़ी जिम्मेदारी प्रदान की है. देश में नवजनवादी क्रांति के लिए शहीद हो चुके हजारों कामरेडों की आशाओं को पूरा करने की शपथ हमने खाई हुई है. ओड़िशा राज्य कमेटी तरफ से आप से, जनता के सैनिकों से हमारी आशा है कि ओड़िशा व पूर्वी छत्तीसगढ़ की विशाल जनता को उनकी मूलभुत समस्याओं पर संगठित करते हुए इस इलाके को लाल प्रतिरोध इलाके में तब्दील करना है. पार्टी, पीएलजीए व संयुक्त मोर्चा के निर्माण पर जोर देना है. पीएलजीए में मौजूद गैर सर्वहारा रुझानों को बहार निकाल फैंकते हुए जनता से सच्चे सेवक के रूप में अपने आप को विकसित करना है. अपनी तमाम कार्रवाईयों में जन दिशा व वर्ग दिशा का पालन करते हुए जनता का विश्वास जीतना है. मैदानी व शहरी जनता को भी संगठित करने पर जोर देना है. जनता को संगठित करते हुए, पीएलजीए का विस्तार करते हुए जनता के तीन बड़े दुश्मन साम्राज्यवाद-सामंतवाद व दलाल नौकरशाह पूंजीपति को उखाड़ कर जनता की सत्ता स्थापना करने के लिए अथक मेहनत करनी है. अगर इसमें अपने प्राणों की बाजी भी लगानी पड़े तो पीछे नहीं हटना है. यही हमारी राज्य कमेटी की आशाए हैं.

जन.सं. - जनता को आपने राज्य कमेटी ने क्या संदेश देना चाहते है?

सं. - प्यारी जनता, देश के शोषक-शासक वर्ग आपकी विशाल जल-जंगल-जमीन संपदा को लूट कर विदेशी कंपनियों व दलाल बड़े पूंजीपतियों को देने के लिए ऐड़ी-चोटी का जोर लगाए हुए हैं. आपको विस्थापित करने के लिए दिन रात नई-नई योजनाएं बना रहे हैं. कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं होता. सभी नेता, अफसर भ्रष्टाचार में डूब कर हमारे खेत-खलिहानों, जंगलों को बेच रहे हैं. किसानों को आत्महत्या कराने पर मजबूर होना पड़ रहा है. विदेशों में काला धन जमा है, महंगाई दिनरात बढ़ती जा रही है. उदंती-सितानदी, सोनाबेड़ा टाईगर रिजर्व सहित नियमगिरी, कलिंगनगर, नारायणपटना, बलंगिर, बरगढ़, कालाहंडी पूरे ओड़िशा में विस्थापन की नई आंधी आने वाली है. इसलिए आपसे अपील है अगर आपको अपने जल-जंगल-जमीन को बचाना है तो बिना सशस्त्र संघर्ष के यह संभव नहीं हो सकता. इसलिए आईए जनमुक्ति गुरिल्ला सेना (पीएलजीए) में शामिल होकर अपने देश व प्रदेश को बचाने के लिए सशस्त्र संघर्ष में कूद पड़ें.

जनता से आव्हान है कि केंद्र और राज्य सरकारों की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ने, रोजमर्रा और मूलभूत समस्याओं को हल करने के जुझारु आंदोलन खड़ा करो. सामंतवाद, दलाल नौकरशाही पूंजीवाद व साम्राज्यवाद इन तीनों पहाड़ों को जड़ से उखाड़ फैंकने के लिए संघर्ष तेज करो! तमाम तरह के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए केंद्र की फासीवादी सरकार की उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ उठ खड़े हो!★

ओड़िशा-छत्तीसगढ़ बार्डर में पुलिस दमन और जन प्रतिरोध

राज्य में लोह, बॉक्साईट, कोयला जैसे 27 प्रकार की खनिज संपदा है. घने जंगल हैं, भरपुर वन संपदा है. बराह मासों बहने वाली महानदी, ब्रह्मणी, कोयल, तेल, वंशाधारा, नागवेली आदि नदियों है तो साथ में एक हजार किलोमीटर से ज्यादा सागर तट है. यही संपदा अब यहां की जनता के लिए जी का जंजाल बनी हुई है. पहले जहां इस राज्य में अंग्रेज लूट करने के लिए यहां पर दमन बरपाए तो वहीं झूठी आजादी के बाद देश के दलाल पूंजीपतियों और साम्राज्यवादियों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शिकंजे में जकड़ गया है. अपनी जल-जंगल-जमीन में मौजूद खनिज व वनसंपदा के अंधधुंध दोहन व विनाशकारी सरकारी योजनाओं के खिलाफ ओड़िशा राज्य की जनता लगातार संघर्ष करती आ रही है. कभी - कहीं वह संघर्ष शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों, धरनों तक है तो कहीं-कहीं जनता जुझरु लड़ाकू संघर्ष के लिए मजबूर हो रही है. और कई जिलों में हमारी पार्टी के नेतृत्व में सशस्त्र संघर्ष के रास्ते को चुनी है और अपनी संपदा की रक्षा करने में कुछ हद तक सफल भी हुई है.

1960के दशक में देश के पहले प्रधानमंत्री जवहार लाल नेहरु ने आधुनिकता और विकास का सुंदर सपना दिखाकर राज्य की जनता को एक बड़ा धोखा दिया था. 1960 के दशक में संबलपुर के पास महानदी पर बहुउद्देश्यीय हिराकुंड बांध बनाया गया. इस बांध का जनता ने विरोध किया था. प्रधानमंत्री नेहरु ने विरोध की आवाजों को यह भाषण देकर चुप करा दिया था कि - यह बलिदान देश के विकास के लिए जरुरी है. यह आधुनिक विकास का मंदीर है. इस से यहां सिंचाई व्यवस्था सुधरेगी और किसानों को लाभ मिलेगा. लेकिन ठीक इसके उलटा हुआ. किसानों को पानी की बजाय विस्थापन मिला. पानी खेतों की बजाय कारखानों को मिला. आज भी जब बांध के कारण लगाकार विस्थापन व पलायन की समस्या बनी हुई है. लेकिन अब जनता शासकों के दिखाए झूठे सपनों के झंसे में आने की बजाय संघर्ष का रास्ता अपनाकर अपने हक मांग रही है.

इसी तरह 1960-70 के दशक में बरगढ-बलंगीर जिलों की सरहदों पर स्थित राज्य के बॉक्साईट के दूसरे सबसे बड़े भंडार गंदमर्धान पहाड़ से बॉक्साईट का दोहन करने के लिए बालको कंपनी को मंजूरी केंद्र सरकार ने दी थी. यहां की जनता हिराकुड बांध योजना से हुए नुकसान, विस्थापन को अपनी आंखों से देख चुकी थी. इसलिए जनता ने एकजुट होकर -गंदमर्धान बचाओ मंच – नामक संगठन के नेतृत्व में तीखा संघर्ष किया. जनता को सफलता मिली. खुदाई का काम 1985 में रोकना पड़ा था. अब फिर कुछ सालों से बहुराष्ट्रीय विदेशी कंपनियों ने अपनी चालबाजियां शुरु कर दी हैं. लेकिन जनता ने भी आंदोलन शुरु कर दिया है. हालांकि एनजीओ के माध्यम सरकार ने पहले सक्रिय रुप से नेतृत्व दिये नेताओं को भ्रष्ट बना दिया है. सरकार पैसों का लालच फैलाकर आंदोलन में कुछ हद तक फूट डालने में सफल हुई है.लेकिन फिर से जनता आंदोलन छेड़ दी है, और नया नेतृत्व उभर कर सामने आ रहा है.

राज्य में 1960-70 दशक से ही वामपंथी आंदोलन का असर रहा है. लेकिन यह अलग-अलग धड़ों के नेतृत्व में अलग-अलग इलाकों तक सिमित था. जन आंदोलन खड़ा करने में सभी ग्रुप विफल रहे. इस कारण से जन संघर्षों का नेतृत्व संशोधनवादियों के हाथों में गया. इससे कई जन आंदोलनों को धोखा खाना पड़ा. 1990 के दशक में अलग-अलग धड़ों के नेतृत्व में आंदोलन खड़ा करने का दूसरा दौर शुरु हुआ. इस बार आंध्र प्रदेश से सटे जिलों में व बिहार-झारखंड, बंगाल से सटे जिलों में काम शुरु हुआ. रायगढ़, कंदमाल में भी जन आंदोलन पनपना शुरु हुए.

देश जिन संकटों से जूझ रहा था उसके हल के रुप में 1990 के दशक में शासकों ने उदारवादी अर्थनीति को लागू करके देश को लूटने के लिए साम्राज्यवादियों को खूली छूट दे दी. तब से ओड़िशा भी साम्राज्यवादियों, बहुराष्ट्रीय व दलाल पूंजीपतियों की कंपनियों के लिए लूट का मैदान बन गया है.

राज्य की खनिज संपदा को लूटने के लिए दुनिया की टॉप टेन कंपनियां लगी हुई हैं. इनमें टाटा, जिंदल, एस्सार, महिंद्रा, पोस्को, वेदांता, स्टारलाइट, आर्सेलर मित्तल आदि प्रमुख हैं. यह कंपनियों ने 17205 हजार करोड़ रुपये का निवेश कर चुके हैं. वहीं हजारों करोड़ रुपये का पूंजी निवेश प्रस्तावित है. इनकी प्रस्तावित परियोजनाओं से लाखों जनता पर विस्थापन की तलवार लटकी हुई. राज्य के की कार्पोरेट अनुकूल नीतियों के कारण राज्य के चारों कोनों में आदिवासी जनता के लिए तो उनके असित्व का प्रश्न बन गया है. इसलिए जनता संघर्ष का रास्ता अपनाने पर मजबूर है.

कलिंगनगर के जगतसिंगपुर में टाटा के खिलाफ जनता ने संघर्ष का बिगूल फूंका था. यहां की आदिवासी जनता पर फायरिंग कर के 12 आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया गया. बर्बरता इतनी बरती गयी कि लाशों के हाथ का पंजा तक काट दिये गए ताकि कोई बोलने व संघर्ष करने की जुर्रत न कर सके. लेकिन जनता ने संघर्ष के रास्ते को नहीं छोड़ा.

पोस्को पारादीप में 50 हजार करोड़ रुपये पूंजीनिवेश करके स्टील प्लांट लगा

रही है. इस के खिलाफ भी जनता जुझरु संघर्ष छेड़े हुए है. इस प्लांट के लिए दो फसली जमीन अधिग्रहण करने के लिए सरकार मान लिया है मगर जनता देने से इनकार कर रही है.

इसी तरह कालाहंडी जिला के नियमगिरी पहाड़ों में लांजिगढ़ में अलुमिनियम रिफायनरी की स्थापना के लिए वेदांता कंपनी को केंद्र व राज्य सरकार ने सहमती दे दी है. स्थानीय कुव्वी आदिवासी और दलित जनता रिफायानरी एवं नियमगिरी पहाड़ की खुदाई के खिलाफ संघर्ष कर रही है. इस परियोजना से कुव्वी आदिवासी पूरी तरह विलुप्त हो जायेंगे. साथ ही पर्यावरण को भी भारी नुकसान होगा क्योंकि इनी पहाड़ों से वंशाधारा, नागावेली, तेल आदि नदियां निकलती हैं. इसलिए पर्यावरण प्रेमियों ने भी इस संघर्ष को अपना पूरा समर्थन दिया हुआ है. इस के अलावा दामनजोड़ी में नालको परियोजना के खिलाफ भी जनता ने संघर्ष किया है.

पश्चिम बंगाल की जनता नंदिग्राम और सिंगूर में सरकारी दमन और उद्योग जगत के गलत प्रचार के खिलाफ डट कर किये गए मुकबले से प्रेरणा लेकर यहां की जनता पूरे इलाके को कई दिनों तक, कभी महीनों तक पुलिस और सरकारी तंत्र को नाकाबंदी कर अंदर नहीं घुसने दी. इस संघर्ष में महिलाओं की भी अच्छी-खासी भूमिका रही थी. कई बार विरोध प्रदर्शनों पर नवीन बाबू सरकार द्वारा लाठी चार्ज करवाया गया, आसू गैस के गोले दगवाये गए, फायरिंग करवाई गयी. आंदोलन के नेतृत्वकारी लोगों व कार्यकर्ताओं सहित आम ग्रामीणों से जेलों को भर दिया गया. फिर भी जनता अपनी जमीन व जंगल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है. इसलिए सरकार द्वारा नेतृत्व को खरीदने व लोगों में अविश्वास का माहौल बनाने के प्रयास चल रहे हैं. दूसरी तरफ आंदोलन को बदनाम करने की कोशिशें भी जारी हैं. जब आंदोलनकारी अगली योजना बनने के लिए मीटिंग कर रहे थे तो पुलिस गुंडो द्वारा सभास्थल पर बम फैंकवाए गए जिसमें तीन-चार आंदोलनकारी मारे गए. पुलिस ने फिर प्रचार किया कि आंदोलनकारी बम बनाते हुए मारे गए हैं. इस कंपनी के लिए मुख्यमंत्री अपना राजनीतिक दबाव बार-बार डालने के बावजूद भी, जन आंदोलन के आगे झुककर कुछ महीने के लिए ही सही सरकार को पीछे हटना पड़ा है. लेकिन देश में आम चुनावों का माहौल बनते ही चुपचाप केंद्र सरकार ने फिर से इस कंपनी को मंजूरी देकर अपना जनविरोधी चेहरा उजागर किया है.

राज्य में निवेश किया और एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी वेदांता - जो लांजीगढ़ में रिफायनरी और झारसगुड़ा में स्मलि्टंग कंपनी स्थापना के लिए निवेश की है. इसके लिए नियमगिरी पहाड़ को खोदने के लिए सभी नियम कानून ताक पर रखकर मंजूरी दी गयी है.

नियमगिरी पहाड़ों का खनन में राज्य में कई समस्या उत्पन्न हो जायेंगी. इन्हीं पहाड़ों में आदिम जनजाति कुवी (डोंगरिया कोंध), जो विलुप्त होने वाली जनजातियों की श्रेणी में आती हैं, उनका निवास स्थान है. इस जनजाति की आस्था नियमगिरी पर्वत से जुड़ी हुई है. घने जंगलों का विनाश होने से पर्यावरण की समस्या भी उत्पन्न हो जायेगी. यहां से निकलने वाली नदियां जैसे नागावेली, वंशधारा, तेलनदी आदि सूख जायेंगी. इसकारण से दलित, आदिवासी एवं पर्यावरण प्रेमी, आदि यहां की जनजाति के आंदोलन में शामिल हो गए हैं. भारत के संविधान के अनुसार अगर यहां की जमीन ली जानी है तो स्थानीय जनता से इसकी अनुमति लेनी आवश्यक है. लेकिन यहां विदेशी कंपनियों के दबाव में आकर, कुछ सामाजिक नेताओं को पैसों का लालच दिखाकर, उन्हें बहला फूसला कर या फिर बंदूक की नोक पर मंजूरी ली जा रही है. आंदोलन में भाग लेने वाले आदिवासी जन संगठनों, एनजीओ, बुध्दिजीवियों को दबाने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग, कुंबिंग, एरिया डामिनेशन जैसे दमन अभियान चलाए जा रहे हैं. पहाड़ के चारों ओर बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ आदि अर्ध सैनिक बलों के कैंप लगा कर जनता पर दबाव बनाया जा रहा है. लेकिन जनता इसके सामने नहीं झूक रही है. एक तरफ जनता सड़कों पर आकर अपना विरोध धरना प्रदर्शन करना, नाकाबंदी करना किये. पीछले चार सालों से कुवी आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला राजापर्व को अब संकल्प पर्व के रुप में मनाया जा रहा है. इस दिन राज्य देश भरके विस्थापन विरोधी, पर्यावरण बचाव आंदोलन से जुड़े लोग जमा होकर संघर्ष को आगे ले जाने का संकल्प दोहराया जाता है. इस पर्व को विफल करने के लिए हर साल पुलिस 144 धरा लगाने से लेकर सभी

नियमगिरी के संघर्षरत आदिवासी

तरह का बाधाओं को तोड़ कर जनता जमा होकर तीन दिन परब मना रहे हैं. दूसरी तरफ कुछ जन संगठनों एनजाओं और व्यक्तियों द्वारा सर्वोच्य न्यायलय में यह कहकर केस डाले कि वेदांता को नियमगिरी पहाड़ों के खुदाई के लिए दिया परमिशन असंवैधानिक है क्योंकि संविधान के अनुसार जनजाति इलाका में धारा 6 के अनुसार प्रभावित होने वाले ग्रामसभाओं को अनुमति लेना अनिवार्य है लेकिन इस संदर्भ में ऐसी कोई प्रक्रिया अमल नहीं की गयी है. सुनवाई के दौरान न्यायलय ने मानाकि संविधान का उल्लंघन हुआ है. फिर से जन सभाओं के आयोजन का आदेश दिया गया. जनमत प्राप्त करने के लिए वेदांता को कहा - यह प्रक्रिया न्यायलय के द्वारा नियुक्त अधिकारियों की देखरेख में ही पूरी करनी है.

दिखावा के लिए ही सही कोर्ट ने जनता के हित में दिये इस आदेश को वेदांता कंपनी ने खुद के फायदे के लिए (हाईजेक) करने के लिए अपने दलालों, गुंडो को उतार कर जनमत को प्रभावित करने की कोशिश को नाकाम होते देखकर सरकार से मिलिभगत होकर वर्दिधारी गुंडो (पुलिस) को बड़ा पैमाने पर उतार कर जनता में पहले से ही भय का माहोल पैदा करने के लिए अरेस्ट, कुंबिंग सर्चिंग नाकाम होते देख कर पहली सभा के ठीक एक दिन पहला रायगढ़ जिला के तीन आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं को क्लयाणसिंगपुर पुलिस थाना के अंतर्गत आने वाले जंगल में झूठी मुठभेड़ में हत्या कर खूनी इरादा को भी साफ किया कि पूंजीपतियों के हित में कुछ भी कर सकता है. तो जनता भी इन हत्याओं का खंडन करते हुए ही पूरा ग्राम सभा एकमत से 'नहीं' करके पुलिस को मुंहतोड़ जवाब दिया और पर्यवेक्षक को साफ साफ बताया कि हम अपना जान देने के लिए तैयार हैं लेकिन अपना जल-जंगल-जमीन नहीं देंगे!

यह हत्याएं पहली बार किया नहीं, इस से पहले 2011 के जनवरी माह में इस जन आंदोलन को सफलता की ओर सूत्रबध्द तरीका से समन्वय करते हुए अपना नेतृत्व दे रहे कामरेड रवी और छह स्थानीय आदिवासी युवक और युवतियों को झूठी मुठभेड़ में हत्या किया है. 2012 दिसंबर माह में अलग-अलग गांवों से उठाकर लाये तीन युवकों को झूठी मुठभेड़ में माओवादियों के नाम से हत्या किया. आंदोलन को कुचलने के लिए माओवादियों का ठप्पा लगाकर जनप्रतिनिधियों को भी गिरफ्तार कर के सलाखों के पीछे ढकेल दिया है.

दूसरी तरफ 1990 दशक के अलग-अलग इलाका में क्रांतिकारियों के नेतृत्व में चल रहे जन आंदोलन नई ऊंचाईयों को छूते हुए नई जनवादी क्रांति विकल्प को आगे लाकर विकास की ओर बढ़ रहा था. इस जन आंदोलन को देख घबराया शासक वर्ग ने इनसे सख्ती से निपटना शुरु किया. सैकड़ों जनता को अरेस्ट करके जेलों में कैद करना, गांवों पर पुलिस हमला करके महिला, पुरुष, बच्चे-बुढ़ों में भेदभाव किये बिना लाठियों से पीटना, दमन अपना चरम पर पहुंच कर झूठी मुठभेड़ों में दर्जनों कार्यकर्ताओं की हत्या किया गया. जन आंदोलन को मजबूत करने के तहत भूतपूर्व पीपुल्सवार ने जनता और पीएलजीए को सशस्त्र करने का निर्णय लिए इसके लिए 2003 में कोरापुट जिला केंद्र पर मल्टीरेड करके हथियार जब्त किया गया.

1995 से ही क्रांतिकारी जन आंदोलन चल रहे राज्यों को केंद्र सरकार अपना नेतृत्व में पुलिस व मंत्रियों का कमेटियां गठित कर के आंदोलन को कुचलने का दिशा में ठोस कदम उठा रही थी. इस से घबराया गया राज्य सरकार ने खुद को और अपना बल को और फासीवादी बनाने का दिशा में पहले 'ग्रेहाउंडस' नाम से विशेष पुलिस बल का निर्माण का निर्णय लिया.

इस तरह सरकारी साम्राज्यवादी जनविरोधी योजनाओं का खिलाफ जन आंदोलन एक वैकल्पिक विकास को आगे रख कर चल रही क्रांतिकारी जन आंदोलन तो दूसरी दृश्य उदारवादी आर्थिक नीतियां यानि वैश्विकरण के चलते राज्य में मौजूद अपार खनिज संपदा पर साम्राज्यवादियों का नजर टिकी है. उसे तुरंत लूटना भी चाहते हैं. इसलिए केंद्र राज्य सरकारों पर दबाव बनाया कि राज्य में सभी प्रकार के जन आंदोलनों को किसी तरह खत्म करो. लगभग इसी समयस 2003-2006 के बीच देश के दुनिया के टोप टेन कंपनियां यहां निवेश किया है.

2004 में पार्टी एकता के बाद, ग्रामस्तर पर लूटेरी राज्य व्यवस्था का विकल्प बनकर उभर रही क्रांतिकारी जन कमेटियों का गला घोटने के लिए राज्य के पुलिस बलों को आधुनिक प्रशिक्षण देकर और हथियार देकर ग्रेहाउंडस बल को एसओजी नाम से पुनर निर्माण किया. तभी से कलिंगनगर नरसंहार हुआ, पोस्को विरोधी आंदोलन पर दमन अत्याचार हो रहे हैं. वेदांता की आग सुलग रही है.

देवगढ से लेकर संबलपुर के बीच कुकुरमुतों की तरह उभर कर आये दर्जनों स्पंज आयरन फैक्ट्रियों व लोह आयस्क खान से उत्पन्न धूल, कोयला खदानों से हो रहे प्रदुषण के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरने के लिए विवश होना पड़ रहा है. तो यहां भी दमन ही नहीं झूठी मुठभेड़ों में हत्याओं का सिलसिला शुरु हो चुका है.

जनता सुलझा हुआ समझे गंदमर्धान समस्या को साम्राज्यवाद के दलालों ने फिर से पूराने घाव को ताजा कर दिया है. इस आंदोलन से जूड़े अपंग नेता माधव सिंग ठाकूर और रमेश साहू अपने गांव आते समय बड़साम्बर गांव के पास घात लगाकर बैठे पुलिस वालों ने पकड़ लिया. पकड़ने के बाद उनकी निमर्म हत्या की गयी. बाद में समाचार पत्रों की

सुर्खियां बनी की मुठभेड़ में माओवादी मारे गए. हर साल यहां की जनता द्वारा विजय दिवस और संकल्प दिवस मनाया जाता है. पिछले दो तीन सालों से सरकार पुलिस का तैनात कर के विफल करने के लिए कोशिशें कर रही है. लेकिन जनता किसी न किसी रुप से उसे मनाती आ रही है. गंदमर्धान पहाड़ से बॉक्साईट निकालने के लिए गुपचुप रुप से हर कोशिश जारी हैं. इन्हीं कोशिशों के तहत लोयर सुकतेल बांध निर्माण कार्य किया जा रहा है. सरकार की चाल को समझने में जनता को ज्यादा वक्त नहीं लगा और जनता ने इसका भी विरोध शुरु कर दिया. इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में खासी संख्या में महिलाएं आगे आ रही हैं. पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया तो 4 लोग घायल हुए. कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया. जेलों से जमानत मिलते ही फिर वे लोग आंदोलन में शामिल हो गए. बुर्जुआ राजनीतिक पार्टियां इस आंदोलन के खिलाफ कुटिल चाले चलने में लगी हुई हैं. आंदोलनकारियों की जमानत में बाधाएं डाल रही हैं वहीं उच्च वर्ग के वकीलों को भी उनके केस न लड़ने के लिए तैयार कर रही हैं. आंदोलन समर्थक वकीलों ने जनता के केस लड़े और उन्हें जमानतें दिलवाई.

ये कुछ ही उदहारण हैं जो जाहिर करते हैं कि बड़ी-बड़ी कंपनियों के हितों के लिए शोषक-शासक कहां तक जा सकते हैं. और साथ में जनता भी कैसे उनके खिलाफ लगातार जीवन-मरण का संघर्ष छेड़े हुए है. न केवल विस्थापन व अपनी दैनिक समस्याओं के लिए संघर्ष जारी है बल्कि जमींदारों और सांमतों, सूदखोरों द्वारा जारी लूट के खिलाफ भी जनता वर्ग संघर्ष छेड़े हुए है.

नारायणपटनम जन विद्रोह जमींदारी, सुदखोरी व शराब माफियाओं के खिलाफ एक नई मिसाल है. जिसने फिर साबित कर दिया है कि कृषि क्रांति ही नवजनवादी क्रांति की धूरी है. आदिवासी व किसानों ने सूदखोरी, महाजनी लूट के खिलाफ जुझारु संघर्ष का इतिहास रचा है. जनता ने कई महिनों तक पूरे सरकारी अमले को पंगू बना दिया. एक समय ऐसा आया जब पुलिस इस इलाके में घूस नहीं पाई. जनता द्वारा रखी गयी शर्तों को सबने स्वीकार करना पड़ा. जमींदारों, सूदखोरों, महाजनों, शराब माफियाओं को जनअदालतों में घसीटा गया और उनके जुल्मों-सितम का हिसाब लिया गया. जनता ने हजारों एकड़ जमीन को वापिस प्राप्त किया जो जमींदारों व सूदखोरों ने अपने कब्जे में ले ली थी. सालों साल बाद महिलाओं को अपने जेवर वापिस प्राप्त हुए जो महाजनों की तीजोरियों में गिरवी रखे हुए थे. शराब भट्ठीयों के मालिकों को अपना कारोबार समेटना पड़ा. जनता ने ग्रामस्तर पर अपना जन मिलिशिया खड़ा कर अपने आंदोलन की रक्षा की.

अक्सर जैसे होता है, जमींदारों-सूदखोरों की रक्षा के लिए राज्य सरकार, पुलिस बल खुल कर मैदान में आ गए. गांव-गांव में गिरफ्तारियों, मारपीट, अत्याचारों, मुठभेड़ों का दौर चला. आंदोलन को तोड़ने के लिए कुछ लोगों को लालच देकर मुखबिर बनाया गया. आंदोलन के लोकप्रिय नेता सिंगन्ना को पुलिस थाना में प्रदर्शन के बीच पुलिस ने गोली मार कर शहीद कर दिया. उनके अंतिम संस्कार के लिए जनता का हूजुम उमड़ पड़ा. वह अपने आप में संघर्ष की एक बड़ी घटना है.

पूरे भारत की तरह पश्चिम ओड़िशा के गांवों में सामंती जमींदारों द्वारा जनता का शोषण और उत्पीड़न आम बात है. भू-हदबंदी कानून फाइलों में दबा पड़ा धूल चाट रहा है. किसानों को कागजों पर ही जमीन मिली है, असली कब्जा अभी भी जमींदारों का ही है. कंधमाल जिला देश भर में पलायन और भुखमरी के लिए जाना जाता है. यहां एक तरफ अकाल पड़ता है तो दूसरी तरफ पूरी जमीन सूदखोंरो व जमींदारों के हाथों में सीमित है. मंदिरों के नाम पर भी हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई है. यह सब राजनेताओं की देख रेख में ही हो रहा है.

2012 में बलांगिर जिला के लाटूर में दलितों की बड़ी बस्ती को जला दिया गया. इसमें शराब माफिया, विश्व हिंदू परिषद व पुलिस की मिलिभगत थी. दलित बारबार थानों व कलेक्टर दफ्तर में फोन लगाते रहे लेकिन किसी ने नहीं उठाये. सैकड़ों लोगों को दारु पीलाकर लंपट तत्वों को उकसाया गया.

इसी तरह सितंबर 2012 में काप्रकोल ब्लाक के अंतर्गत बेहरापानी गांव पर तड़के चार बजे हमला करके कुछ को अरेस्ट करने के लिए कोशिश किया तो जनता विरोध की थी. जनता पर फायरिंग की गयी जिससे तीन लोग घायल हुए. सुबह होते ही अगल-बगल के गांवों की जनता जमा होकर पुलिस थाने जाकर थाने का घेराव की. इस गांव को इसलिए पुलिस ने निशाना बनाया क्योंकि गंदमर्धान पहाड़ बचाओं आंदोलन हो, लोयर सुकतेल बांध के खिलाफ आंदोलन या फिर सामंती शोषण के खिलाफ आंदोलन ग्रामीण हमेशा सक्रिय भूमिका निभाते थे.जनता को खौफजदा करने के लिए यह हमला किया गया.

2012 में बर्तोंडा गांव के मुस्लिम जमीनदार गांव का गौठिया से सीलिंग जमीन पर हक के लिए लड़ कर कब्जा लिए तो जमींदारों ने अपने गुंडो से हमला करवाकर कईयों से मारपीट. पुलिस ने कई लोगों को माओवादी होने का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया. 2013 में यहां पर सीआरपीएफ ने अपना कैंप लगा दिया है ताकि कोई आंदोलन में शामिल न हो सके.

फसीवाद की ओर बढ़ता राज्ययंत्र

भारत का बाजार वैश्विकरण के नाम से साम्राज्यवादी नीतियां अपना गया तब से ही साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कंपनियो ं का निवेश अनुकूल महोल बनाना शुरु किया यानि राजनीतिक, कानून, न्यायपालिका, पुलिस व्यवस्था को बदलना शुरु किया गया है.

राजनीतिक तौर पर केंद्रीय गृहमंत्री के नेतृत्व में खासकर नक्सलवादी प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राज्य के गृहमंत्रियों से कमेटियां गठित करके विभिन्न राज्यों का दलों के बीच में आपसी समझौता करके पुलिस का घुसपैठ को अनुमोदन दिया. इसी तरह राज्यों को पुलिस के आला अधिकारियों अर्ध सैनिक बलों के आला अधिकारियों को मिलाकर आपसी तालमेल के लिए - ज्वाइंट ऑपरेशनल कमांड, जेओसी गठित करके विभिन्न राज्यों के बीच बॉर्डर इलाकों में संयुक्त अभियान चलाने का निर्णय लिया है.

कानूनों को निजी क्षेत्र के अलावा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्रों में भी साम्राज्यवादी निवेश के लिए अनुकूल बनाना, न्यायपालिका का वाक्या में भी कारपोरेट अनुकूल बदलाव देखा जा सकता है.

इन बदलावों का विश्वसनीयता के लिए कुछ, विश्वनियता बढ़ाने के लिए उदारमतवादी बुध्दिजीवियों को शासक वर्ग के साथ साथ कार्पोरेट घरानों ने अपना और आर्किषत किया. दूसरी ओर एनजीओ को खुद प्रायोजित कर जनता को संघर्ष की राह से भटकाने के लिए गुस्सा को बहार लाने के लिए सेफ्टीवाल्व जैसे इस्तेमाल करना आरंभ हुआ. इतना त्यारियों के बावजूद साम्राज्यवादियों दलाल नौकरशाहों का जनविरोदी प्रकल्पों,योजनाओं को कदम कदम पर डटर कर विरोध करना चलता राह.

राज्य में बढ़ते वामपंथी जन आंदोलनों जो वैकल्पिक विकास नमूना को जनता के आगे लाकर जनमोदन हासिल कर रही थी तो दूसरा तरफ राज्यबर में हर तबके के जनता अपना रोजमर्रा समस्याओं पर आंदोलन भी तूल पकड़ना लगा. सैनिक रुप से पीएलजीए - मिलिशिया का निर्माण मजबूत होना - कोरापुट मल्टी रेड जैसी कार्रवाइयों से घबराई सरकार ने आंध्रा की तर्ज पर पहले ग्रेहाउंडस जैसे बलों को बनाने की शुरुआत की फिर इसका नाम एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) रख दिया. इसकी 30 से 40 यूनिट बनाई गयी.

शुरुआती दिनों में एसओजी घमंड के साथ हमले करता था. लेकिन जब मलकानगिरी के बालीमेला जलाश्य में ग्रेहाउंडस पर पीएलजीए ने जबरदस्त हमला किया, तेल्लराई एंबुश में एसओजी का एक अधिकारी मारा गया, उसी तरह नयागढ़ हमले के बाद गोसामा जंगल की शोर्यपूर्ण लड़ाई में एसओजी का एक असिस्टेंट कमांडेट मारा गया तब एसओजी का घमंड चकनाचुर हो गया था. जहां पीएलजीए बलों ने डटकर एसओजी का मुकाबला किया वहां एसओजी आगे नहीं बढ़ा. जहां प्रतिरोध कमजोर या न के बराबर रहा वहां हमे नुकासन उठाना पड़ा.

2009 अगस्त महीने से चालू किये गए देशव्यापी बहूमुखी सैनिक हमला - आपरेशन ग्रीनहंट यहां पर भी चालू हुआ. दंडकारण्य की तर्ज पर यहां पर भी कार्पेट सेक्यूरिटी के तहत हर पांच किलोमीटर पर कैंप बिठाये जा रहे हैं. सुंदरगढ, संबलपुर, देवगढ़ से लेकर कंदमाल, मलकानगिरी तक यही हाल है. ओड़िशा को उत्तर और पूर्व से पश्चिम भाग के भौगोलिक इलाके के रणनीतिक महत्व को समझकर दुश्मन रणनीतिक तैयारी शुरु कर दिया है. सुंदरगढ़, देवगढ़ से लेकर नियमगिरी तक झूठी मुठभेड़ों में जनता व सक्रिय कार्यक्रर्ताओं को, समर्थकों को दर्जनों संख्या में मार डाला गया है. जब 2010 में छत्तीसगढ़ ओड़िशा बार्डर में पीएलजीए की कंपनी राजनीतिक प्रचार में जूटी हुई थी तो पीएलजीए की कंपनी पर पडकिपाली के पास जंगल में दोनों राज्यों के विशेष बलों के अलावा सीआरपीएफ व कोबरा बल के 400 जवानों ने घात लगाकर हमला किया. इस हमले में पीएलजीए के छह लाल योद्धाओं सहित 2 ग्रामीण शहीद हो गए थे. दो ग्रामीणों को घर से निकाल कर निमर्म तरीके से मार डाला गया.

2012-2013 में छत्तीसगढ के गरियाबंद जिला और नवरंगपुर के इलाका में 60 से 150 संख्या में कार्पेट सेक्यूरिटी के तहत कई कैंप लगाए गए हैं. नुआपाडा में भी नया नया कैंप लगा दिये गए हैं. बीबीएम डिवीजन में भी गंधमर्दान पहाड़ों के चारों तरफ कैंप बिठाये गए हैं. नियमगिरी खदान चालू करने के लिए जनमत लेना जरुरी है करके सुर्पीम कोर्ट बताने पर जनमत का नाटक क्लयाणसिंगपुर के जंगलों में झूठी मुठभेड़ों की शुरुआत कर के किया गया. लेकिन जनता ने एकमत से खदान का विरोध किया. वह उन मुठभेड़ों से डरी नहीं. बीबीएम में 2013 जनवरी में अपने गुरिल्ला दस्ता के डेरा पर जनवरी 5 को सबेरे एसओजी बलों ने हमला किया तो हमारे सेंटरी ने पहले ही देख कर फायरिंग की जिसमें एक कमांडो वहीं पर डेर हो गया. दो जन घायल भी हुए. इसी तरह सितंबर में भी हमले की फिराक में घुम रही पुलिस का पता चलने से हमारे कामरेडों ने डेरा खाली किया. लेकिन बाद में सामान लाते हुए एंबुश में फंसकर हमारे एक कामरेड धनजय शहीद हो गए. अगस्त माह में एपीटी पर गयी छोटी टीम पर मुखबिर की सूचना पर एसओजी ने तीन तरफ से फायरिंग की. पीएलजीए ने भी जवाबी फायरिंग की. रिट्रीट होते हुए कामरेड संतोष शहीद हो गए. इसी तरह नियमगिरी में गांव में संपर्क करने के लिए जा रहे अपने दस्ते पर घात लगाकर किये हमले में हमारी कामरेड सुक्कायी शहीद हो गयी. सोनाबेड़ा में कैंप लगाकर घमंड से मोटरसाइकिलों पर घूम रहे जवानों पर हमारी पीएलजीए ने हमला किया. इसमें दो पुलिस वाले मारे गए व

उनके हथियार भी जब्त कर लिए. इस हमले के बाद पेट्रोलिंग छोड़कर पुलिस कैंप में ही सीमित होकर रह गयी है.

मैनपुर डिवीजन के खल्लारी जंगल में 1 जून को दस्ता के डेरा पर सीआरपीएफ ने हमला किया तो अपने सेंटरी ने सूझबूझ का परिचय देते हुए फायरिंग की. इसमें एक कमांडेट मारा गया और बाद में डेरा में पहले से लगायी गयी बुबीट्रैप की चपेट में आकर दो पुलिस वाले भी घायल हुए.

कुंबिंग एक बड़े इलाके में होती है. जिस इलाके में कुंबिंग होती है उस इलाके के सभी पुलिस थानों और कैंपों से एक साथ ही समन्वय के साथ दुश्मन बाहर निकलता है. जंगल में हमारे सभी डेरों व पानी की जगहों पर तलाशी ली जाती है. यह अभियान कभी तीन दिन तो कभी-कभी 8 से 10 दिनों तक भी जारी रहता है. जब पहला बैच तीन दिन तक जंगल में पैट्रोलिंग कर वापिस कैंप जाता है तो दूसरा बैस उसी सिलसिले में जंगल में घुसता है. वह इस बात को ध्यान रखते हैं कि जंगल में जनता को नजर नहीं आना. जनता से पूछने पर पता नहीं चलता लेकिन उनके जूतों के निशान जगह-जगह दिखाई देते हैं. कभी-कभी दुश्मन वापिसी के समय गांवों में भी घुसता है. पहले दुश्मन दाल-चावल आदि कच्ची खाद्य सामग्री लाता था अभी पका-पकाया पैकेटों वाला भोजन लाता है. जिसमें दाल, पनीर, मटर, हलवा जैसे पदार्थ रहते हैं. जो खासकर सेना के लिए ही तैयार किये गए हैं. इसे गरम पानी में पांच मिनट डालने से, पाकेट खोल कर खा सकते हैं. इसके अलावा दूध से बनी कई प्रकार की चीजें भी दुश्मन ला रहा है. कभी-कभी अपने मुखबिरों से रोड प्वांइट पर खाने का इंतजाम करवा रहे हैं. घुमने का तरीका तो पहला रास्ता पकड़ आना-जाना करता था, बाद में मुखबिरों की मदद से तो अब सेटेलाईट फोनों, जीपीएस सिस्टमों के जरिये ना रास्ता ना पहाड़ जिधर बोले उधर जैसा बोले वैसा चल रहे हैं. इसी लिए उतना आसानी से हमारे टार्गेट में नहीं आ रहे हैं. फिर भी मंदागिरी से लेकर 14 मार्च तक सुनाबेड़ा एंबुश तक जब तब मौका मिला तो पीएलजीए ने कार्रवाई करके पुलिस को धुल चटाई है. मांदागिरी में आठ आमामोरा एंबुश में एक एएसपी सहित नौ जन पुलिस वालों का सफाया किया गया. 2012 मई में कुंबिंग अभियान में लगे एएसआई को धर्मबंदा में मार गिरया गया. दिसंबर में नियमगिरी में तीन पुलिस को एंबुश में मार गिराया गया.

दमन, घेराव अभियान से जनता का ध्यान हटाने के लिए और जनता में फूट डालने के इरादे से सरकार का ओर से आर्थिक सुधारों को तूल दे रही है. इस सुधार योजना में 75 प्रतिशत रुपया सड़कों पर खर्च कर रही है. दूसरा स्थान मोबाईल टावरों पर, मुखबिर नेटवर्क पर खर्च कर रहे हैं. दूसरी तरफ खुद केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों ने करोड़ों रुपयों से अपना क्रूर छवी को छुपाने के लिए सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मेडिकल कैंप चलाना, जनता में कुछ को फुक्कट में सामान बांटना, युवाओं को खेलखूद का स्पर्दा आयोजन करना, बच्चों और छात्र छात्राओं को पेन, नोटबुक, चाकलेट जैसे सामान बांटना कर रहे हैं. युवा और छात्र -छात्राओं से संपर्क करके एसपीओ पुलिस में भर्ती के लिए प्रेरित कर रहे हैं. आंदोलन को 2010 से पार्टी को नुकसान करने में मुखबिरों या एसपीओ का ही मुख्य भूमिका रही है. सभी डिवीजनों में गांव में रहकर हो या व्यापार या नौकर चार के रुप में रहकर पार्टी, पीएलजीए या ग्राम स्तर के निर्माणों की सूचना पुलिस को देने वालों को पहचान करके सुधारने का मोका दिया गया. नहीं सुधरने वालों पर कार्रवाई की गयी. इन्हीं में आते हैं बर्तोंडा के मुस्लिम जमींदार, सुनाबेड़ा के गुणीमनि, मैनपुर के रइमन दुर्व, बलांगिर में चेतन मांझी और सुनिल देवांगन.

साम्राज्यवादियों ने अपना घोर आर्थिक संकट से उबरने के लिए विकाशील - अविकसित देशों का प्राकृतिक संपदा को बेचुट लूटकर लेजाना चाहते हैं. इसके लिए अपना दलालों पर दबाव बना रहे हैं. साम्राज्यवादियों का सेवा में तत्पर अपना शोसकों ने जनता द्वारा की जाने वाली किसी प्रकार का विरोध को सहने का स्थिति में नहीं रही! इसलिए राज्य सरकार सभी विभागों को ओडिशा राज्य के सभी जेलों के क्षमता से दो तीन गुना ज्यादा कर रहे है तो दूसरी तरफ राज्य सुरक्षा का नाम से आम जनता हो या बुध्दिजीवि या क्रांतिकारी सभी पर राजद्रोह केस लगाकर सालों साल जेल में ठूस रहे हैं. सभी जेलों को आंदोलनकारियों से भर दिया गया है. कंदमाल में भगवा आतंकवादियों ने आदिवासियों व इसाईयों पर, उनके गिरजाघरों पर हमले किये. कईयों के हत्या किया गया, महिलाओं पर अत्याचार किया गया, फिर भी उन लोगों को आसानी से छोड़ दिया जा रहे हैं तो वहीं आदिवासियों, इसाईयों को आजीवन कारावास का सजा दिया जा रहा है. यही दर्शाता है कि राज्य दिन ब दिन फासीवादी बनता जा रहा है. दूसरी तरफ सभी तबके की जनता रोजमर्रा समस्याओं से लेकर अपना मूलभुत अधिकारों व जल-जंगल-जमीन पर अधिकार के लिए चल रही जुझारु संघर्ष में और संगठित होकर सभी संघर्षों जैसे सशस्त्र संघर्ष, विस्थापन, आदिवासी दलिता, पर्यावरण जैसे एक मंच पर आना और जनता के बीच में धोका देने वाले एनजीओ से सतर्क रहना और सरकार के विरोध में लड़ना जरुरी है. आज पहले से कहीं ज्यादा जरुरत है तभी गंदमर्धान से 'बालको', सिंगूर से टाटा को भगाया जैसे यहां से भी टाटा, पोस्को, वेदांता, नालको, बालको जैसे बहुराष्ट्रीय एवं दलाल पूंजीपतियों को यहां से भगा सकते हैं और जनहितकारी योजनाओं को लागू कर सकते हैं.☆

श्रधांजली

भारतीय क्रांति के वरिष्ठ नेता, संशोधनवाद के खिलाफ लड़ने वाले अथक योध्दा और भाकपा (माओवादी) के पोलिट ब्यूरो सदस्य कामरेड विप्लव सुशील राय उर्फ बरुण दा को लाल सलाम! आईये उनके त्याग व आदर्शों को ऊंचा उठाते हुए क्रांति को आगे बढ़ाएं!

''मानव जीवन में मौत आती ही है. मैने अपनी पूरी जिंदगी अपनी शोषित-उत्पीड़ित जनता और मातृभूमि की मुक्ति के संघर्ष में लगा दी है. मैं इस संघर्ष को मौत के बाद भी जारी रखना चहाता हूं. इसलिए मैं चहाता हूं कि किसी धार्मिक रीति-रिवाज के जरिये मेरा अंतिम संस्कार न किया जाये, मेरे शव को लोगों के क्लयाण के लिए हस्पताल को दान में दे दिया जाये. ताकि मेरा शरीर चिक्तिसा विज्ञान व लोगों के विकास के लिए काम आ सके. यही मेरी अंतिम इच्छा है !''

कामरेड सुशील राय

ये शब्द उस शख्स ने अपनी शहादत से पहले अपने भाई को कहे थे, जिस शख्स को पश्चिम बंगाल व भारत सरकार ने 68 साल की उम्र में गिरफ्तार करके सालों तक जेल में सड़या, उसका ठीक से इलाज तक नहीं होने दिया. और उसे मौत के मुंह में धकेल दिया. ये शब्द उस शख्स के है जो अपने देश को असीम प्यार करता था लेकिन उस पर देशद्रोह का मुकद्दमा चलाया गया, जिसे देश की 'आंतिरक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा' माना. उनका नाम है कामरेड विप्लव सुशील राय, जो क्रांतिकारी हल्को में कामरेड वरुण दा के नाम से प्रसिध्द थे. उन्होंने न केवल आखरी सांस तक देश की शोषित-पीड़ित जनता के लिए त्याग और बलिदान दिये बल्कि मौत के बाद भी उसने अपना शरीर जनता व देश के चिक्तिसा विज्ञान के विकास के लिए सौंप दिया.

कामरेड वरुण दा 18 जून 2014 को, 78 साल की उम्र में देश की जनता को अंतिम लाल सलाम पेश कर भौतिक रुप से हमसे जूदा हो गए. उन्होंने नई दिल्ली के एम्स हस्पताल में आखरी सांसे ली. उनके परिजनों व क्रांति समर्थक बुध्दिजीवियों, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं, प्रगतिशील, जनवादी लोगों ने उनके शरीर को, उनकी इच्छा के अनुसार एम्स हस्पताल को दान कर दिया.

कामरेड बरुण दा हमारी पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य थे.उनकी पूरी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई है. एक तरफ उन्होंने शोषक-शासकों के खिलाफ जनता का नेतृत्व किया वहीं भाकपा, माकपा के संशोधनवाद के खिलाफ भी अथक संघर्ष किया. उनको 22 मई 2005 को पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था. तब वह हावड़ा-हुगली-कोलकाता मजदूरों को संगठित करने के काम में लगे हुए थे. जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनकी उम्र 68 साल की थी.सालों तक उनको सरकार ने जमानत नहीं दी. उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता गया. जब उनके बचने की आशा नहीं रही, तब क्रूर फासीवादी सरकार ने उनको इलाज के लिए जमानत पर छोड़ा. अंततः 18 जून 2014 को वह शहीद हो गए.

उनके क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत 1961 में शुरु हुई. तब वह पश्चिम बंगाल के बंशादरोनी इलाके की उषा फेन कंपनी में स्थाई नौकरी करते थे. उनकी कंपनी में मजदूरों ने अपनी बुनियादी मांगो को लेकर हड़ताल शुरु की थी. तब चीन के साथ भारत का युध्द चल रहा था. नेहरु सरकार ने सभी कारखानों में हड़तालों को गैर कानूनी घोषित कर दिया था. उस हड़ताल में कामरेड सुशील राय ने सक्रिय भूमिका अदा की थी. छह महा चली हड़ताल के बाद सरकार व कंपनी को मजदूरों की मांग माननी पड़ी थी. इस प्रकार वह भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) की ट्रेड यूनियन से जुड़े और एक क्रांतिकारी मजदूर नेता के रुप में स्थापित हुए.

1963-64 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 'महान बहस' हुई. उस महान बहस

ने भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन को भी प्रभावित किया और वरुण दा काम करने वाली यूनियन को भी. कामरेड वरुण दा ने रूस के ख्रुश्चेव के संशोधनवाद की कड़ी आलोचना की और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का पक्ष चुना. पूरी पार्टी उस समय दो गुटों में बंट गयी थी एक रूस का पक्ष लेता था तो दूसरा चीन का पक्ष लेता था. 1964 में हुई भाकपा की सातवीं कांग्रेस में पार्टी विभाजित हो गयी. तब सीपीआई (मार्क्सवादी) का जन्म हुआ. तब वरुण दा माकपा में शामिल हो गए.

जब अमेरिकी साम्राज्यवाद ने वियतनाम पर क्रूर फासीवादी सैनिक हमला शुरु कर दिया तब पूरी दुनिया अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ सड़कों पर उतर आई. पार्टी ने वरुण दादा को दक्षिण कोलकाता की जनता को संगठित करने की जिम्मेदारी प्रदान की. उन्होंने पार्टी के आव्हान पर हजारों-हजार जनता को संगठित किया. पूरा कोलकाता अमेरिकी साम्राज्यवाद के विरोध में सड़कों पर उमड़ आया. तब उन्होंने नारा लगाया था 'तोमार नाम, आमार नाम, वियतनाम' यानी तेरा नाम, मेरा नाम वियतनाम! 1966 में अकाल के खिलाफ खाद्य आंदोलन शुरु हुआ. पार्टी ने 72 घंटों का बंगाल बंद का आव्हान दिया. तब भी दक्षिण कोलकाता की जनता ने कामरेड वरुण दा के नेतृत्व में अहम भूमिका निभाई. तब बंगाल व केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी. कांग्रेसी गुंडो व पुलिस ने मिलकर उन पर हमला किया और जेल में डाल दिया.

कांग्रेस के दमन व अत्याचारों के खिलाफ बंगाल में पहली बार 1967 में कम्युनिस्टों के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी. लेकिन कुछ ही दिनों के बाद 1967 में कोलकाता से बहुत दूर नक्सलबाड़ी की चिंगारी भड़की. किसानों ने जमींदारों की जमीनों पर कब्जा कर लिया. कामरेड चारु मजूमदार की अगुवाई में आंदोलन पूरे भारत में दावनल की तरह फैल गया. तब भाकपा, माकपा व संयुक्त मोर्चा की सरकार ने नक्सलबाड़ी आंदोलन को चरमपंथी बताते हुए, उस पर दमन चालू कर दिया. 25 मई को नक्सलबाड़ी गांव पर हमला कर संयुक्त मोर्चा की सरकार ने 11 लोगों का कत्ल कर दिया जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे. कामरेड बरुण दा पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा. महान बहस की रोशनी में, चीनी क्रांति के इतिहास को देखते हुए उन्होंने अपनी पार्टी माकपा का विरोध करते हुए नक्सलबाड़ी आंदोलन का पक्ष चुना और उसका समर्थन करने लगे. उन्होंने नक्सलबाड़ी आंदोलन को मात्र एक घटना के तौर पर नहीं बल्कि उनके शब्दों में कहा जाये तो 'सत्ता दखल करने की एक वैक्लपिक राजनीतिक-सांगठनिक लाईन के तौर पर देखा'. कोलकाता में माकपा के नेताओं के सामने उन्होंने सवाल उठाये, कई मीटिंगों में बहसे की. उन्होंने सीपीएम पर सवाल उठाये कि वह क्रांति को आगे नहीं बढ़ा रही है. सही राह नक्सलबाड़ी की राह है. इस प्रकार वह अपने विचारों और सपनों को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह से 1968 में क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़े. उन्होंने अपनी नौकरी व चाहाने वालों को छोड़ कर सूदूर ग्रामीण क्षेत्र को आपनी कर्मभूमि बनाया और हजारों-हजार जनता को गोलबंद किया.

कामरेड कन्नाई चटर्जी, अमूल्य सेन, चंद्रशेखर दास जैसे संशोधनवाद के खिलाफ लड़ने वाले योध्दाओं के साथ मिलकर उन्होंने माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी) की नींव रखी. उन्होंने अपनी पूरी उम्र चीनी क्रांति से सबक लेकर स्थापित की राजनीतिक-सांगठनिक-सैनिक लाईन को मजबूत करने और भारतीय क्रांति को पूरा करने में लगा दी. एमसीसी को बंगाल से विस्तार करते हुए झारखंड, बिहार, असाम, हरियाणा, पंजाब, ओड़िशा, छत्तीसगढ़ तक फैलाने में उन्होंने अपना अहम योगदान दिया. कामरेड कन्नाई चटर्जी, कामरेड अमूल्य सेन जैसे वरिष्ठ नेताओं के शहीद हो जाने के बाद उन्होंने पार्टी को नेतृत्व प्रदान किया. वह 1995 तक एमसीसी के महासचिव रहे.

एमसीसी और पीपुल्सवार की एकता में भी उनके अहम योगदान को कभी भारतीय क्रांतिकारी इतिहास भूल नहीं सकता. उन्होंने 1984-95 में हुए एकता प्रयासों में भी सकारात्मक भूमिका निभाई थी. लेकिन कुछ कारणों के चलते एकता विफल हो गयी थी. एमसीसी और पीपुल्सवार के बीच हुई खूनी झड़पों के काले अध्याय को खत्म कर, लाल अध्याय में बदलने में कामरेड बरुण दा ने भरपूर योगदान दिया. जिसका नतीजा

21 सितंबर 2004 को हुई दोनों पार्टियों की एकता है. उन्होंने उन नेतृत्वकारी कामरेडों के खिलाफ भी अथक संघर्ष चलाया जो दोनों व्पार्टियों की एकता होने में बाधा डाल रहे थे. कामरेड बरुण दा हमेशा नौजवानों से आशाएं करते थे. हमेशा नेतृत्व को विकसित करने के लिए प्रयास करते थे. अपने से निचले कैडर को ऊपर उठाने के लिए शिक्षित करते और उनका सहयोग करते थे.

1995 में उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ था. लेकिन ऑपरेशन सफल नहीं होने से एक आंख की रोशनी पूरी तरह चली गयी थी. इसके बाद भी उनकी क्रांतिकारी उर्जा और उत्साह में कोई फर्क नहीं आया. वह हमेशा युवा की तरह पार्टी कामकाज में अपनी भूमिका निभाते रहे. अपनी गिरफ्तारी के समय भी वह हावड़ा-कोलकाता-हूगली मजदूर क्षेत्र में उन्हें संगठित कर संघर्ष पथ पर बढ़ा रहे थे. दुश्मन की फासीवादी जेलें भी उनके उत्साह व जोश को तोड़ नहीं पाई. 2012 में इंडियन एक्सप्रैस नामक दैनिक समाचार पत्र को दिया उनका ऐतिहासिक साक्षात्कार इसका गवाह है. जिसे अपनी हेडिंग में लिखना पड़ा 'स्वास्थ्य कमजोर लेकिन हौंसले बुलंद'!

भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के विकास में, माओवादी पार्टी की स्थापना में, और तमाम उतार-चढ़ावों में कामरेड वरुण दा के योगदान को हमेशा याद रखा जायेगा. वह भारतीय उपमहाद्वीप के क्रांतिकारी आंदोलन व क्रांतिकारी पार्टियों का जीता-जाता एनसाईकलोपिडया थे. हर ऐतिहासिक घटना को उन्होंने अपनी आंखों से देखा. खासकर भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के विकासक्रम में उन्होंने अपना अहम योगदान दिया. उनके पास क्रांति के अपार अनुभव थे. आज जब दुनिया की क्रांतिकारी परिस्थितियां अभूतपूर्व रुप से क्रांति के अनुकूल बनती जा रही हैं और भारत के शोसक-शासक वर्ग क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने के लिए पूरजोर प्रयास कर रहे हैं, जब भाकपा (माओवादी) और भाकपा (माले) (नक्सलबाड़ी) मिलकर एक पार्टी बन और मजूबत होने के इरादे से आगे बढ़ रही है तब ऐसे अनुभवी कामरेड की बेहद जरुरत थी. आज उनकी शहादत से भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को एक बहुत भारी क्षति हुई है.

हमारी राज्य कमेटी शोकसतंप्त वरुण दा के परिजनों, दोस्तों, शुभचितंको, पार्टी कतारों के प्रति गहरी सहानभूमि प्रकट करती है. तमाम पार्टी सदस्यों, पीएलजीए के लाल योध्दाओं, जन संगठनों के नेता व कार्यकर्ताओं से आव्हान करती है कि उनके द्वारा स्थापित किये गए आदर्शों को आत्मसात करें, अपने गैर सर्वहारा रुझानों के खिलाफ लड़कर उनके सपनों को पूरा करने के लिए शपथ लें. जनता से आव्हान है कि अपने-अपने गांव में, बस्ती में, शहर में उनको याद करें. उनके दिखाए गए रास्ते पर आगे बढ़ें. ✯

पेज 4 का शेष...

उसको एहसास हो रहा है कि हमारी ताकत से दिल्ली दहल रही है, दिल्ली तक सरकार अब हमें देख रही है! हालांकि यह सब क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के लिए ऑपरेशन ग्रीनहंट का ही हिस्सा है लेकिन कुछ भी हो - जनता का अपनी ताकत पर भरोषा बढ़ता जा रहा है.

हमारी पार्टी के नेतृत्व में जनता के जारी संघर्ष से घबरा उठी विदेशी कंपनियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और जमींदारों की लूट को जारी रखने के लिए माओवादी आंदोलन को कुचलने के लिए ऑपरेशन ग्रीनहंट चलाया जा रहा है. हम कहते हैं हमारा आंदोलन जनता का जायज आंदोलन है. यह एक न्यायीक युध्द है. जबकि लूटेरे शासक वर्ग जो जनता पर लाखों सशस्त्र बलों को उतार रहे हैं, हवाई हमलों की तैयारी कर रहे हैं वह पूंजीपति व जमींदारों के फायदे के लिए किया जाने वाला नजायज व अन्यायपूर्ण युध्द है. यह युध्द उन तमाम लोगों के खिलाफ है जो विस्थापन, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, और अपने जल-जंगल-जमीन के लिए लड़ रहे हैं. क्योंकि सरकार को डर यह सारे लोग आने वाले समय में माओवादी ही बनेंगे!

दोस्तो युध्द जारी है, टाई और लंगोटियों के बीच, झोपड़ी और कोठियों के बीच, आपको तय करना है आप किसके पक्ष में हैं, आदमखोरों की ओर हो या आदमी की ओर हो! हमारा लक्ष्य सीधा है, देश को आजाद करवाने के लिए, सबके लिए रोटी, कपड़ा और मकान के लिए, हर हाथ को काम हर व्यक्ति को सम्मान के लिए, आदिवासी, दलित जनता के विकास के लिए, महिला-पुरुषों की समानता के लिए बड़े दलाल पूंजीपतियों, जमींदारों, साम्राज्यवादियों को उखाड़ फैंकना है. इसके लिए मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, कर्मचारी,छात्र, अल्पसंख्यक, राष्ट्रीय पूंजीपति सब हमारे दोस्त हैं. आईये मिलकर एक नवजनवादी भारत के सपने को साकार करें. आईये माओवादी जनयुध्द को हर तरह की मदद देते हुए जनता के पक्ष में खड़े हों!✯

जनता अपने शहीदों को कभी नहीं भूलती!
मेहनतकश जनता की मुक्ति के लिए शहीद हुए तमाम शहीद कामरेडों को लाल सलाम!
28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद यादगार सप्ताह मनाओ!
शहीदों के सपने पूरे करने के लिए क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़ो!

प्यारी जनता

28 जुलाई 1972 के दिन भारतीय क्रांति के पथ प्रदर्शक और हमारी पार्टी के संस्थापकों में से एक कामरेड चारु मजूमदार को भारतीय राजसत्ता ने हिरासत में लेकर मार डाला था. इसके अलावा नक्सलबाड़ी से लेकर अब तक हर वर्ष सैकड़ों क्रांतिकारी मेहनतकश जनता की मुक्ति के लिए, देश में नवजनवादी क्रांति की सफलता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते आ रहे हैं. उन्हीं तमाम शहीदों की याद में हमारी पार्टी हर वर्ष 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक शहीद यादगार सप्ताह मनाने का आव्हान जनता से करती है. आईए हमारी पार्टी के संस्थापक, भारतीय क्रांति के महान नेता कामरेड चारु मजूमदार और कामरेड कन्हाई चटर्जी सहित तमाम ज्ञात-अज्ञात शहीदों को लाल सलाम पेश करते हुए उनके सपने पूरे करने की शपथ लें.

हमारा देश आज भी विदेशी कंपनियों, दलाल बड़े पूंजीपतियों और बड़े-बड़े जमींदारों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है. ये तीनों पहाड़ देश की मेहनतकश जनता के कंधों पर लदे हुए हैं जिस कारण से हाड़तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी जनता को दो जून का खाना नसीब नहीं हो पा रहा है. आदिवासियों, दलितों व किसानों की जमीनों को छीन कर उसे बड़ी-बड़ी विदेशी कंपनियों को दिया जा रहा है. पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए महंगाई को आसमान पर चढ़ाया जा रहा है. हर चीज के दाम बढ़ाए जाते हैं. जोतने वालों को जमीन नहीं है. पढ़ने वालों को नौकरी नहीं है, मजदूरों व कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है - यह सब हो रहा है शोषक वर्ग के हितों के लिए. हमारी पार्टी शुरु से ही इसके विरोध में और जनता के हित में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व कर रही है. जनता व शोषकों के बीच चल रहे इस युध्द में हजारों क्रांतिकारी शहीद हो गए हैं.

ओड़िशा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक विदेशी व बड़े पूंजीपतियों का सबसे बड़ा दलाल है. इसने सैकड़ों कंपनियों के साथ आदिवासियों की जमीनों को बेचने के समझौते कर रखे हैं. वहीं ओड़िशा की जनता हमारी पार्टी के नेतृत्व में अपने जल-जंगल-जमीन की लड़ाई लड़ रही है. इसलिए ओड़िशा के शोसक-शासक जनता के इस आंदोलन को दबाने के लिए सीआरपीएफ, कोब्रा, एसओजी व पुलिस बलों को उतार रहे हैं. अपने आंदोलन व जनता की रक्षा करते हुए, केंद्र व राज्य के फासीवादी अर्ध सैनिक, स्पेशल व पुलिस बलों का मुकाबला करते हुए पिछले अगस्त महीने से अब तक ओड़िशा में हमारे कई प्रिय कामरेड्स शहीद हुए हैं.

सितंबर 2013 में मलकानगिरी जिला के पडिया ब्लॉक के सिलकोटा जंगल में जन मिलिशिया के एक शिविर पर राज्य के फासीवादी बलों ने साजिश के तहत मुखबिर की सुचना पर एक बड़ा हमला किया. इस हमले में स्थानीय मिलिशिया के 14 कामरेड शहीद हुए. जिसमें एक महिला कामरेड भी थी.

दक्षिण बस्तर डिवीजन के बासागुड़ा एरिया में जन्मे कामरेड संतोष 11 अगस्त 2013 को ओड़िशा के बलांगिर जिले में शहीद हुए. मुखबिर की सुचना पर ओड़िशा के फासीवादी बल एसओजी ने यह हमला किया था.

पूर्व बस्तर डिवीजन के गांव कोटमेट्टा के सपूत कामरेड रोंडा उर्फ धनाजी भी 2013 में गस्त पर आई पुलिस के साथ ओड़िशा में हुई मुठभेड़ में बहादुरी के साथ लड़ते हुए शहादत का जाम पीये.

11 सितंबर 2013 को रायगढ़ जिला के क्लयाणसिंगपुर ब्लॉक में हुए पुलिस हमले में बहादुरी के साथ लड़ते हुए कामरेड सुक्कई शहीद हुई. उनका जन्म बिजापुर जिला के, भैरमगढ़ ब्लॉक के गांव जांगला में हुआ था. वह एक जनकलाकार थी जो अपने नाच-गाने के साथ क्रांतिकारी राजनीति का प्रचार करती थी.

झूठे लोकसभा चुनावों के बहिष्कार का प्रचार करने के लिए जा रहे सोनाबेड़ा दल को घेर कर नुआपाड़ा जिला के रिंगझोला के पास पुलिस ने हमला किया. यह एक बेहद फासीवादी हमला था जिसमें हमारे कामरेडों के ऊपर ओड़िशा के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, कोब्रा व पुलिस बलों ने जहरीली गैस के गोले दागे. जिस से सभी कामरेडों को सांस लेनें में तकलीफ हुई, चलना मुश्किल हुआ. 14 अप्रैल 2014 को इस हमले में कामरेड मोती मड़काम शहीद हुई. पुलिस ने उसकी लाश के साथ भी

बेहद बर्बरता बरती. कामरेड मोती का जन्म दक्षिण बस्तर डिवीजन के बट्टुम गांव में हुआ था.

मलकानगिरी एरिया कमेटी सदस्य और पीछले दो सालों से एओबी प्रैस में काम कर रही कामरेड शिरीषा जनवरी 2014 में बीएसएफ के हमले में शहीद हो गयी. वह 15 बरस की उम्र में ही पार्टी में भर्ती हो गयी थी. वह एक क्रांतिकारी परिवार में जन्मी कामरेड थी. उनकी मां भी 1997 में पुलिस द्वारा किये गए हमले में श्रीकाकूलम जिला में शहीद हो गयी थीं. उनके पिता जी एओ ी एसजेडसी के सदस्य थे जो अपनी कमजोरियों के चलते 2004 में सरेंडर हो गए थे. बाद में शिरीषा के पति भी सरेंडर हुए लेकिन वह जनता के लिए माओवादी आंदोलन में आखरी सांस तक टीकी रही. उसने जनता की जीत पर पूरा यकीन था.

ये सभी कामरेड हमारे सामने क्रांतिकारी आदर्शों की विरास्त छोड़ कर गए हैं. उन्होंने अपने गांव, राज्य, भाषा-बोली, को छोड़ जहां गए जनता की भाषा-बोली को अपनाए, उसकी संस्कृति में घुलमिल गए और जनता के प्यारे कामरेड बने. उन्होंने पार्टी कांग्रेस व केंद्रीय कमेटी द्वारा दिए गए आंदोलन विस्तार के लक्ष्य के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी.

आंध्र प्रदेश की फासीवादी खुफिया एजेंसी एसआईबी ने साजिशन सड़क दुर्घटना को अंजाम देकर मानव अधिकार कार्यकता, अलग तेलंगाना आंदोलन के जनप्रिय नेता आकुला भूमय्या को मार डाला. वह अपने स्कूटर पर एक प्रैस कांफ्रेंस को संबोधित करने के बाद अपने घर जा रहे थे. रास्ते में फिल्मी अंदाज में उनका एक्सीडेंट करवा दिया गया.

इसके अलावा पूरे देश में भी जारी ऑपरेशन ग्रीनहंट 'देश की जनता पर युध्द' में कई बहादुर जननेताओं, कमांडरों, पीएलजीए लाल योध्दाओं, जन संगठन के कार्यकर्ताओं, जनताना सरकार के नेताओं व क्रांतिकारी जनता ने अपनी जान की कुर्बानी दी है. बहुत सारे कामरेड स्वास्थ्य कारणों से शहीद हुए है.

ओड़िशा में विदेशी कंपनियों व पूंजीपतियों के दलाल नवीन पटनायक की पार्टी को फिर एक बार 'बहुमत' मिला और वह सत्ता में बैठ गयी है. केंद्र में भी कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जनता का गुस्सा फूटा जिसका बीजेपी फायदा मिला और वह नरेंद्र मोदी के लोकलुभावने सपनों के कारण सत्ता में आ गयी. नरेंद्र मोदी का 'गुजरात मॉडल' और नवीन पटनायक का 'ओड़िशा मॉडल' पूरी तरह से बड़े पूंजीपतियों व विदेशी कंपनियों के हित में है. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शेयर बाजार नरेंद्र मोदी सत्ता संभालते ही सारे रिकार्ड तोड़ गया. विदेशी कंपनियों ने बहुत पैसा भारत में लगाया. आने वाला समय आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं व राष्ट्रमुक्ति संघर्षों के बेहद चुनौतियों भरा है. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय राजसत्ता भयंकर फासीवाद की तरफ बढ़ रही है. पूंजीपतियों व विदेशी कंपनियों को विकास के नाम पर पूरे देश को बेचा जायेगा. आदिवासियों-किसानों की जमीनों को छीना जायेगा और हर क्षेत्र में निजीकरण किया जायेगा. और इसके विरोध में आवाज उठाने वाला हर व्यक्ति, मानव अधिकार कार्यकर्ता, बुध्दिजीवि सरकार की नजर में 'आतंकवादी, देशद्रोही, विकास विरोधी' बन जायेगा. जिसका नतीजा यह होगा कि हरेक आवाज दमन के कारण दबा दी जायेगी. दूसरी तरफ दमन होगा तो प्रतिरोध अनिवार्य बन जायेगा. फासीवाद के खिलाफ मोर्चे की जरुरत होगी और तमाम क्रांतिकारी, प्रगतिशील ताकतें एकजुट होंगी. यह प्रक्रिया शुरु हो चुकी है.

1 मई - महान अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर सच्ची क्रांतिकारी पार्टी भाकपा (माओवादी) और भाकपा (माले) नक्सलबाड़ी का विलय संपन्न हो गया है. इससे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के माओवादी आंदोलन पर जनता व क्रांतिकारी ताकतों का भरोषा और ज्यादा बढ़ गया है. इससे भाकपा (माओवादी) और मजबूती से देश की जनता का नेतृत्व दे सकेगी और देश की मुक्ति में अपना अहम योगदान दे सकेगी. इस एकता से शासक वर्ग डर रहे हैं वहीं जनता खुश हो रही है.

हम जनता व हमारी पार्टी कतारों से आव्हान करते हैं कि आने वाला समय क्रांति के बेहद अनुकूल बनता जा रहा है. आइये नवीन पटनायक व नरेंद्र मोदी के फासीवादी 'विकास मॉडल' को ठोकर मारते हुए अपने प्यारे शहीदों के नवजनवादी भारत के सपने को साकार करें जिसमें हर मेहनतकश को अपनी मेहनत का पूरा दाम मिले, हर हाथ को काम मिले, हर मुंह को खाना व जोतने वालों को जमीन मिले. ★

अमर शहीदों का पैगाम - जारी रखना है संग्राम!

आपरेशन ग्रीनहंट को हरायेंगे - माओवादी जनयुध्द को फैलाएंगे!

शहीद तुम्हारे सपनों को - मंजिल तक पहुंचाएंगे!

नवजनवादी क्रांति जिंदाबाद!

बस्तर में पैदा हुई और ओड़िशा के रिंगजोला में शहीद हुई कामरेड मोती मड़काम (कोसी) को लाल सलाम! शहीद तुम्हारे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे!!

14 अप्रैल 2014 सुबह सात बजे थे. सोनाबेड़ा एलओएस के कामरेड चुनाव बहिष्कार के लिए जनता को जागरुक करने के लिए जा रहे थे. तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरी एक जगह पर दुश्मन घात लगाकर बैठा हुआ था. हमारे कामरेडों को इसकी भनक नहीं लगी. वह दुश्मन के एंबुश में फंस गए. दुश्मन ने ताबड़तोड़ फायरिंग की. सीआरपीएफ, एसओजी व जिला पुलिस बल के क्रूर आतंकियों ने न केवल गोलीबारी की बल्कि जहरीली गैस के गोले भी दागे. जिस कारण से हमारे कामरेडों का निकलना बेहद मुश्किल हो गया. गैस के कारण हमारे साथियों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, पांव उठ नहीं पा रहे थे. सब बेहोशी की हालत में हो गए. एक तरफ जहां भारत सरकार व अमेरीकी साम्राज्यवाद सिरीया, इराक, इरान आदि देशों पर केमिकल वेपन यानि रासायनिक हथियारों का उपयोग कर जनता को मारने का विरोध करते हैं दूसरी तरफ अपने ही देश में ऐसे रासयानिक जहरीले हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं. कामरेड मोती भी ऐसे रासयानिक हथियारों से बेहोश होकर दुश्मन के हाथों शहीद हुई. हमारे कामरेडों ने डटकर प्रतिरोध किया लेकिन कामरेड मोती को नहीं बचा पाये. वहीं एक साथी घायल भी हो गया. सभी कामरेडों ने बड़ी बहादुरी का परिचय दिया. अलग-अलग हुए कामरेडों का जनता ने भी भरपुर सहयोग किया. उनको बचा कर रखा और पार्टी को सोंप दिया.

कामरेड मोती पिछले ढाई सालों से ओड़िशा के सोनाबेड़ा इलाके में काम कर रही थी. वह 2010 में ओड़िशा विस्तार एरिया में काम करने के लिए आई थी. वह सोनाबेड़ा एरिया कमेटी के अंतर्गत काम करने वाले आमामोरा एलओएस की सदस्या थी. उनका जन्म एक गरीब मड़काम आदिवासी परिवार में हुआ था. उनका गांव बट्टुम दक्षिण बस्तर डिवीजन के कुंटा एरिया में आता है. वह अपने माता-पिता की दूसरी संतान थी. उसका बचपन गांव के क्रांतिकारी माहोल में बीता था. 2005 में सलवा जुडूम शुरु हुआ. जिसने बच्चें, किशोरों, महिलाओं, बुढ़ा सबको बुरी तरह प्रभावित किया.हर किसी का, जीवन के लिए लड़ना एक मजबूरी बन गयी थी. खेत जोतना हो या जंगल से वनोपजों का संग्रहण कुछ भी बिना लड़ असंभव था. जनता ने अपना कोया भूमकाल मिलिशिया बनाया. सब नौजवान उसका हिस्सा बन गए थे. कामरेड मोती भी जनता की रक्षा करने वाले उस मिलिशिया की एक सदस्या बनी. वह गांवों में पहरा देने, सलवा जुडूम गुंडे गांव पर हमला करने आयें तो उन पर पलटा हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी. जब सलवा जुडूम गुंडे जबरदस्ती युवक-युवतियों व गांव वालों को शिविरों में ले जाते थे तो उसने उनका विरोध किया व अपने साथियों के साथ जंगल मां की शरण में चली गयी.

कामरेड मोती एक ओर जन मिलिशिया की जिम्मेदारी को लगन से निभाती थी तो दूसरी तरफ अपने परिवार की जिम्मेदारी भी उतनी ही लगन से निभाती थी. अपने परिवार की खेती कमाई में मदद करती थी. उनकी बड़ी बहन की शादी होने के बाद उसकी मां बीमार पड़ गयी थी, उसके भाई छोटे-छोटे थे तो उसने बखूबी अपने परिवार की देखभाल की. जब युवक-युवतियां दूसरे राज्य में मजदूरी करने की योजना बनाते तो वह उनका विरोध करती ओर बोलती थी कि इससे हमारा मिलिशिया, हमारी लड़ाई कमजोर हो जायेगी. इसलिए वह जंगल में अपने भाई-बहनों के लिए हमेशा महुआ, टोरा, तेंदुपत्ता आदि वनोपज जमा कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिती को ठीक करने के लिए सोचती थी. और दूसरे लोगों को भी यही सलाह देती थी. एक तरफ घर का काम तो दूसरी तरफ पार्टी का काम भी वह लगातार कर रही थी. दस्तों की सक्रिय मदद को देखकर उनके घर वालों ने उसकी शादी जल्द ही करने का मन बना लिया. परंपरा के अनुसार परिजनों ने समधी से 'शराब पीकर' शादी तय कर दी. लेकिन कामरेड मोती ने इसका विरोध किया और अपनी इच्छा के खिलाफ तय की गयी शादी को जनताना सरकार के सामने लेकर गयी. जनताना सरकार ने उसके परिजनों छोटी उम्र में शादी करने से होने वाले नुकसानों के बारे में समझाया और छोटी उम्र में होने वाली इस शादी को रुकवा दिया.

कुछ दिनों के बाद कामरेड मोती पुर्णकालीन रुप से दस्ता की सदस्या बन गयी. दल में पढ़ना-लिखना व गुरिल्ला अनुशासन को सीखी. धीरे-धीरे अपनी राजनीतिक समझ को बढ़ाई. दक्षिण बस्तर में पार्टी की जरुरत को देखते हुए पलटन-10 का गठन किया गया. जब उसके सामने पलटन में बदली होने का प्रस्ताव रखा तो वह खुशी से उसको स्वीकार की. कम समय में ही वह सैनिक विषयों को सीख ली. पार्टी ने पलटन-10 को विस्तार एरिया में बदली करने का निर्णय लिया. पूरी पलटन के साथ कामरेड मोती ने भी बिना हिचकिचाहट के इस निर्णय को स्विकार कर लिया था. हंशी-खुशी के साथ वह नए इलाके में आयी थी.

यहां पर विस्तार में आने से पहले वह पार्टी से अनुमति लेकर अपने परिवार से मिलने के लिए गयी थी. उस समय उनकी मां का देहांत हो गया था. भाई छोटे-छोटे थे. पिताजी काम करने के लिए अकेले पड़ गए थे. उसके सामने यह बहुत बड़ी चुनौती थी. एक तरफ अपना घर था तो दूसरी तरफ देश. किस को चुने. किस को पहले देखे. किस को पहले सुधारे. कामरेड मोती ने बड़ी दृढ़ता दिखाई. नहीं जब तक पूरी जनता की समस्या हल नहीं हो जाती तब तक हमारे परिवार की समस्या भी हल नहीं हो सकती. पूरे देश की गरीबी दूर होने से ही हमारे परिवार की गरीबी दूर हो सकती है. कम समय में सीखी बुनियादी राजनीति से उसने बड़ा फैसला लिया और अपने परिवार का त्याग कर देश की लड़ाई लड़ने के लिए ओड़िशा में विस्तार के लिए आ गयी. जब 2012 में अपने पिता जी के देहांत की खबर उसने सुनी तो तब भी कामरेड मोती दृढ़ता के साथ जनता की सेवा में लगी रही और घर जाकर देखने की इच्छा का त्याग की.

यहां आने के बाद इलाका नया, भाषा नई, लोग नए और नए रीति-रिवाज. एक गरीब आदिवासी लड़की के लिए जो अपने इलाके से बहार कभी गयी ही नहीं, जो अपनी गोंडी भाषा के अलावा दूसरी भाषा जनती ही नहीं. उसके लिए ऐसी परिस्थितियों में काम करना बेहद मुश्किल भरा था. पार्टी में, उसके दल में काम करने वाले दूसरे कामरेडों की भी यही हालात थी. लेकिन उसने इस चुनौती को स्वीकार किया. स्थानीय ओड़िया, छत्तीसगढ़ी भाषा को सीखने की कोशिश की. जनता को राजनीतिक रुप से संगठित करने की कोशिशों में भागीदार बनी. स्थानीय भुंजिया, कमार आदिवासी जनता के कुछ पुराने व पिछड़े रीतिरिवाजों को छोड़ने के लिए महिलाओं को संगठित की. जबरन शादियों के खिलाफ यहां पर भी उसने महिलाओं को जागरुक किया. इस प्रकार सोनाबेड़ा एरिया की जनता के दिलों में उसने एक खास जगह बना ली थी. मेडिकल कैंप में प्रशिक्षण लेकर वह एक गुरिल्ला डॉक्टर भी बनी. महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी विषय पर उसने ध्यान दिया. वह अपने दल की अच्छी डॉक्टर बनी. और जनता के लिए भी अच्छी सेविका बनी. स्थानीय आदिवासी महिलाएं ज्यादातर एनिमिया की शिकार हैं. इसलिए वह खान-पान, साफ-सफाई आदि पर ध्यान देने के लिए महिलाओं को अच्छे से समझाती थी. कामरेड मोती का मानना था कि अगर गुरिल्ला स्वस्थ नहीं रहेगा तो वह जनता की सेवा नहीं कर सकता! कामरेड मोती को जंगल में मिलने वाले कंद-मूलों और साग-सब्जियों का अच्छा खासा ज्ञान था. उसे पता था क्या खाने से क्या लाभ होता है. इसे ज्ञान का उपयोग भी उसने बखूबी अपने डॉक्टरी कामों में किया.

कामरेड मोती छोटी उम्र में शहीद होकर हमारे लिए बड़े आदर्श निर्माण कर के हमसे विदा हो गयी है. पार्टी द्वारा दिए गए आंदोलन विस्तार के लक्ष्य के लिए वह अपनी अंतिम सांस तक काम की. तमाम चुनौतियों का सामना की. हमारी डिवीजनल कमेटी कामरेड मोती को सिर झुकाकर सलाम पेश करती है. कामरेड मोती के परिजनों, बहन-भाईयों के प्रति गहरी सहानभूति प्रकट करती है. तमाम कामरेडों से आशा करती है कि आंदोलन विस्तार के उसके सपनों को पूरा करने के लिए जीजान से कोशिश करेंगे और कामरेड मोती की राह पर आगे कदम बढ़ाएंगे.

कामरेड मोती केवल अपने इलाके, अपनी जाति के लिए ही नहीं लड़ रही थी. उसकी सोच थी पूरी दुनिया की मेहनतकश जनता की मुक्ति, महिलाओं की मुक्ति. वह केवल सोच ही नहीं थी, वह हर रोज व्यवहार में यह करती थी. आखिर में अपने इलाके, राज्य को छोड़ कर दूसरे राज्य में आकर जनता के लिए अपनी जान की भी बाजी लगा दी. स्थानीय जनता से हमारी अपील है कि अपनी लाडली के सपनों को पूरा करने के लिए आगे आएं. उनकी कुर्बानी से सीख लेते हुए नौजवानों को पार्टी में भर्ती करें और अपने अस्तित्व व जल-जंगल-जमीन पर अधिकारों की लड़ाई लड़ें. ✯

'जनता के लिए मरना हिमालय पर्वत से भी भारी है और लुटेरों के लिए मरना पंख से भी हलका!'

प्रैस विज्ञप्तियां

13 जुलाई 2014 - ओड़िशा राज्य कमेटी

राशनकार्डों को रद्द करने वाली छत्तीसगढ़ सरकार मुर्दाबाद

छत्तीसगढ़ खाद्य व पोषण कानून एक धोखा है! गरीबों के राशकार्ड रद्द करना बंद करो!

राशनकार्ड सत्यापन की प्रकिया में ग्रामसभा व मोहला सभा की राय को निर्याणक मानने की मांग करो!

2012 में छत्तीसगढ़ खाद्य व पोषण कानून छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने लागू किया. जनता के वोटों को लूटने के लिए यह हथकंडा अपनाया गया था और प्रचार किया गया था कि पूरी दुनिया को छत्तीसगढ़ के पीडीएस सिस्टम और खाद्य सुरक्षा कानून से सीख लेनी चाहिए. यह सबसे प्रगतिशील कानून बताया जा रहा था. लेकिन असल मंशा को छुपाया गया. दरअसल सच्चाई यह है कि देश में जरुरत से ज्यादा अनाज देश के अन्नदाता ने उगया है. उसको ओने-पोने दामों पर सरकारों ने अपने गोदामों में जमा भी कर लिया है लेकिन जनता को उसे बांटा नहीं जा रहा. वह अनाज सड़ रहा है. अनाज को भरने के लिए बोरों का खर्च भी सरकार नहीं उठा पा रही है. वहीं गोदमों के आगे जनता भूख से मर रही है. इसे देखते हुए सुर्पीम कोर्ट ने सरकारों को फटकार लगायी थी. उसका नतीजा था वोट पाने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों ने तरह-तरह की लोकलुभावनी 'क्लयाणकारी' योजनाएं बनानी पड़ी. इस प्रकार कोई राज्य ढाई रुपये तो कोई दो रुपाये और कोई एक रुपये किलो चावल, गेहूं बांटने लगा और नाम कमाने लगा. छत्तीसगढ़ का खाद्य सुरक्षा कानून भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है. यह कानून लागू होने के बाद नियम यह बनाया गया कि पूराने कार्ड रद्द किये जायेंगे और नये कार्ड महिला मुखिया के नाम से जारी किये जायेंगे.

लेकिन कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों को गरीबों को सस्ता अनाज देना सहन नहीं हो रहा है. इसलिए 4 फरवरी को विधानसभा में कांग्रेस ने सरकार से यह पूछ कर हंगामा किया कि कितने राशकार्ड अभी तक बनाए गए हैं. सरकार ने जवाब दिया कि 70 लाख से ज्यादा बनाए जा चुके हैं. काग्रेस ने आरोप लगाया कि यह तो राज्य की जनसंख्य के अनुपात से ज्यादा है इसमें धांधली हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए. सरकार मानो इसके लिए तैयार बैठी थी. सरकार ने जांच के आदेश दिये ताकि लोगों के राशनकार्ड काटे जा सकें. अब सरकार ने नियम यह बना दिया है कि एक छत या मकान में रहने वाले लोगों का एक परिवार माना जाये. इस आधार पर राशनकार्डों का सत्यापन किया जा रहा है. जब वोट बैंक के भाजपा ने यह कानून बनाया तो कांग्रेस भी चुप रही क्योंकि राशनकार्ड बनाने का विरोध अगर वह करती तो जनता में उसकी छवी खराब होती. तब कांग्रेस ने यह प्रश्न नहीं पूछे जो अब पूछ रही है. अब पूरे प्रदेश में राशनकार्ड सत्यापन का नहीं राशनकार्ड काटे जाने का अभियान चल रहा है. इसके लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों बराबर की जिम्मेदार हैं. हर जिले में जनता राशनकार्ड काटे जाने के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है. महासमुंद में 12 जुलाई को सत्यापन प्रक्रिया को सही ढंग से चलाने की मांग कर रही जनता पर पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया गया. राजनंदगांव में भी जनता सड़कों पर उतरी. हर गांव हर महोल्ले में आग सुलग रही है. अधिकारी अनान-फानन में आकर मकान को देख कर राशन कार्ड काट रहे हैं. अगर एक मकान में चार भाई अलग-अलग रहते हैं तो उनके तीन कार्ड काटे जा रहे हैं. इस प्रकार राजनंदगांव में 13 हजार, महासमुंद में एक ही महोल्ले में 70 प्रतिशत तक कार्ड काटे जा चुके हैं. गांव में तो हाल और भी बूरा है. वहीं छुटभैया नेताओं व अधिकारियों के रिश्तेनातेदारों को चांदी हो रही है. पैसे देकर राशनकार्ड बचवाने का धंधा भी जोरों पर शुरु हो गया है.

हमारी पार्टी गरीबों के राशनकार्ड काटने का विरोध करती है. सरकार से मांग करती है कि यह भ्रष्टाचार में लिप्त राशनकार्ड काटो अभियान तुरंत बंद किया जाये. सत्यापन की प्रक्रिया ग्रामसभा व महोल्ला सभा आयोजित कर चलाई जाये. उसमें मौजूद जनता के बयानों को निर्णायक मानकर राशन कार्ड बनाए जायें व उनका सत्यापन किया जाये. निदोर्ष जनता पर लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों को कड़ी सजा दी जाये.

- **सत्यापन की प्रक्रिया ग्रामसभा व महोल्ला सभा के जरिये पूरी की जाए.**
- **जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, अब तक बनाए गए राशनकार्डों पर राशन निर्बाध दिया जाये.**
- **धंधली व भ्रष्टाचार फैलाने वाले अधिकारियों को कड़ी सजा दी जाए.**

चुनाव बहिष्कार करने वाली जनता का क्रांतिकारी अभिवादन!

जनता ने अपनी इच्छा से वोट नहीं डाले बल्कि पीठ पर संगीने टीका कर दबवाये गए हैं बटन!

22 अप्रैल 2014 - मैनपुर डिवीजनल कमेटी

मैनपुर डिवीजन के उदंती, गरियाबंद, धमतरी, मैनपुर, छुरा, विश्रामपुरी, देवभोग आदि इलाकों की जनता पीछले कई सालों से अपनी मूलभुत समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रही है. उदंती-सितानदी टाईगर रिजर्व के नाम पर इस इलाके के 51 गांवों के 3000 से ज्यादा परिवारों पर विस्थापन की तलावर लटक रही है. समय-समय पर वन विभाग की तरफ से गांव को खाली करवाने के नोटिस थामा दिये जाते हैं. जनता पर जंगल में जाने पर प्रतिबंद है, उनको ऊपर दैनिक उपयोग के लिए लकड़ी लाने व लघु वनोपजों का संग्रहण करने पर भी झूठे केस लगाए जाते हैं. एक तरह से सरकार ने पूरे इलाके की जनता को वनों में रहने के 'जुर्म' में अपराधी घोषित कर दिया है. टाईगर रिजर्व होने के नाम पर शासन की तरफ से मिलने वाली सुविधाएं भी नहीं दी जा रही. बिजली, हस्पतालों, स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों व राशन की दुकानों का बुरा हाल है. सिंचाई के लिए तालाब नहीं है, न ही बिजली कनेक्शन और जो पांच बड़े-बड़े बांध बनाए गए उनका सारा पानी भिलाई, बिलासपुर व रायपुर जैसे शहरों में पूंजीपतियों की फैक्ट्रीयों के लिए ले जाया जाता है. इसी कारण से लोकसभा चुनावों से पहले जनता ने अधिकारियों के सामने अपनी ऐसी मूलभुत समस्याएं रखी और चेतावनी दी थी कि अगर इन समस्याओं का हल नहीं किया जाता तो हम चुनावों का बहिष्कार करेंगे. हमारी पार्टी ने भी जनता से आव्हान किया था कि इन झूठे चुनावों से आपकी मूलभूत समस्याएं हल नहीं हो सकती. इनका बहिष्कार कर जन संघर्ष का रास्ता चुनना ही समय की मांग है.

इलाके की जनता ने खासकर ग्रामीण इलाके की जनता ने बड़े पैमाने पर चुनावों का बहिष्कार किया. लेकिन अर्ध सैनिक बलों व पुलिस बलों ने इलाके को सैनिक छावनी में बदल दिया. बंदूक की नौक पर जनता से इवीएम मशीनों के बटन दबावाए गए हैं. चुनावों से एक-दो दिन पहले ही पूरे गांवों को घेर लिया गया था. गांवों को खुली जेल में तब्दील कर दिया गया था. जैसे कि पूरे गांव की जनता ही अपराधी हो. यह समय महुआ बीनने का समय है, जनता को महुआ नहीं बीनने दिया गया. यहां तक की शौच के लिए जाना भी अपराध था. महिलाओं को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा. जिडार, झरगांव, केरलाझाड़, नागेश, कोदोमाली, साहेबनकच्छार, भुतभेड़ा, अमलीपदर, गरीबा, कोच्चेंगा आदि गांव में जनता ने अधिकारियों को पहले से ही लिखित में चुनाव बहिष्कार करने का अल्टिमेटम दिया था. मार्च महीने में देवभोग, अमलीपदर, इंदागांव एरिया के 70 गांवों में पंच-सरपंचों सहित बड़ी संख्या में लोग कलेक्टर को अपनी मूलभुत समस्याओं के हल के लिए ज्ञापन दिये थे. समस्याएं हल नहीं होने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दिये. लेकिन जनता की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं. चुनाव का बहिष्कार करने के 'अपराध' में अब गांव के मुखियाओं, जनता का नेतृत्व करने वाले लोगों को पुलिस व खासकर सीआरपीएफ के अधिकारी प्रताड़ित कर रहे हैं. उनको अवैध रुप से हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं, जिसके चलते गांव वालों का बाजार और रिश्तेदारी में आना-जाना मुश्किल हो गया है. डर के मारे लोग हस्पतालों तक में नहीं जा रहे हैं. जिडार गांव के लोगों ने चुनाव अधिकारियों, पुलिस व तहसिलदार को काले झंडे दिखाकर चुनावों का बहिष्कार किया तो सीआरपीएफ के जवानों ने गांव को घेर कर घर-घर की तलाशी ली. शादी के लिए जमा किया सामान तहस-नहस कर दिया. गांव कनफाड़ में जाकर सीआरपीएफ जवानों ने 7-8 लोगों की पीटाई की. कोदोमाल्ली ग्रामीणों पर बंदूक की नौक पर वोट डलवाये गए. साहिबेन कच्छार के ग्रामीणों पर पुलिस अधिकारियों ने वोट डलाने का दबाव डाला.

कांकेर जिला, नरहपुर ब्लॉक की टेमा ग्रामपंचायत के सभी गांवों ने चुनाव का पूर्ण बहिष्कार किया. मनरेगा के तहत करवाये गए काम की मजदूरी गांवों वालों को नहीं दी जा रही. लंबे समय से गुहार लगाते हुए जब जनता थक गयी तो उसने चुनाव बहिष्कार का रास्ता चुना.

साहिबेन कच्छार ग्रामपंचायत के गांव नागेश में हमारे पीएलजीए के बलों ने 17 अप्रैल को सीआरपीएफ जवानों पर हमला किया था. सीआरपीएफ जवानों ने अंधुधुंध गोली गांव की तरफ दागी, एक मोर्टार सेल तो गांवों आकर एक घर के पीछे आकर पड़ा. इसके बाद ग्रामीणों पर नक्सलियों का साथ देना का आरोप लगाकर जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है. सीआरपीएफ के अधिकारी इसलिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं ताकि जनता में दहशत फैला कर उदंती-सितानदी टाईगर रिजर्व के खिलाफ व जंगल पर जनता के अधिकार के लिए चल रहे उनके संघर्ष को दबाया जा सके. हम जनता को प्रताड़ित करने वाले अर्ध सैनिक बलों के अधिकारियों की कड़ी निंदा करते हैं. जनता से आव्हान करते हैं कि गांव में दहशत फैलाने के लिए आने वाले पुलिस व अर्ध सैनिक बलों के जवनों का सामाजिक रुप से बहिष्कार करें, उनका किसी भी प्रकार का सहयोग न करें. उनके साथ मुंह से बोलना भी बंद कर दें.

समाचार पत्रों में चुनाव आयोग अपने मुंह मिया मिटठू की तरह बयान दे रहा है कि - हमारी कोशिशों से चुनावों में प्रतिशत बढ़ा है. वहीं कांग्रेस के अजीत जोगी इसे कांग्रेस की विकासकारी नीतियों का परिणाम बता रहे हैं तो वहीं बीजेपी के रमन सिंग भी इसे राज्य सरकारी की विकासकारी नीतियों का परिणाम बता रहे हैं. कुछ बुध्दिजीवी यह सोच रहे हैं कि जनता चुनावों पर में भरोषा जता रही है. हमारी पार्टी का मानना है कि वोटों का प्रतिशत दो कारणों से बढ़ा है, जिन इलाकों में जनता चुनावों का बहिष्कार की उन इलाकों में सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसे अर्ध सैनिक बलों ने बंदूक के दम पर वोट डलवाये हैं. दूसरा कारण है कि पूंजीपतियों से काला धन चंदे के रुप में लेकर बुर्जुआ राजनीतिक पार्टियों ने पानी की तरह बहाया है. महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर दारु व नकदी बांटी गयी है. वोटों को पैसे के दम पर खरीदा गया है ग्रमीण इलाकों खासकर हमारे आंदोलन के इलाकों में कोई वृध्दि नहीं हुई है, शहरी इलाकों के वोट प्रतिशत को जोड़ कर उसे बढ़ा-चढ़ा कर बताया जा रहा है. सच्चाई यही है कि जनता 70 साल के चुनावों से तंग आ चुकी है और वह किसी भी उम्मीद्वार पर भरोसा नहीं करती यही कारण है की चुनाव आयोग को मशीनों में नोटा बटन लगाना पड़ा.

भुंजिया-कमार आदिम जनजाति के अस्तित्व के लिए खतरा बन गये हैं - ओड़िशा पुलिस, एसओजी व केंद्रीय अर्ध सैनिक बल! आदिवासी जनता पर दमन के खिलाफ आवाज उठाओ!!!

18 मई 2014 - नुआपाड़ा डिवीजनल कमेटी

दुनिया के सबसे बड़े 'लोकतंत्र' का नाटक अभी-अभी समाप्त हुआ है. जब यह नाटक चल ही रहा था, जब लोकसभा व ओड़िशा विधानसभा चुनावों के लिए वोट डाले जा रहे थे तब केंद्र के अर्ध सैनिक बलों व ओड़िशा के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप व ओड़िशा पुलिस ने निर्दोष व निहथ्य ग्रामीणों पर अपनी बहादुरी दिखाई. गांवों वालों को जबरदस्ती मतदान केंद्रों पर बंदूक के दम पर ले जाया गया. इतना ही नहीं माओवादियों के समर्थन, मददगार होने के झूठे आरोप लगाकर निर्दोष आदिम जनजाति भुंजिया व कमार आदिवासियों की बे वजह निमर्म पिटाई की गयी.

सोनाबेड़ा ग्रामपंचायत के सनबायली गांव के निर्दोष आदिवासी बिजू को पुलिस घर से उठाकर ले गयी. अवैध हिरासत में रख कर उसको यातनाएं दी गयी. गांव वालों को न कोई कारण बताया न कोई वरंट दिखाया. अभी तक उसका कोई अतापता नहीं है. कोर्ट में पेश किया गया है या न ही इसकी किसी को जानकारी है. इसी पंचायत के डेकुनपानी गांव के हिरालाल को पुलिस ने सुबह चार बजे उसके घर से पकड़ा. उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर पुलिस कैंप में लेजकर लाठियों से पिटाई की गयी. न कोई केस दर्ज किया न ही कोर्ट में पेश किया. पिटाई करके जब वह मरने की हालत में हो गया तो उसे गांव में छोड़ दिया गया. उस गरीब आदिवासी की हालत अब कमाने-खाने लायक नहीं रही है. इसी पंचायत के गातिबेड़ा के मारेन व सोनाबेड़ा के एक अन्य आदिवासी को भी पुलिस ने बुरी तरह से पीटा है.

सोसेंग व ओडेर की एक-एक महिला पर अत्याचार किया गया. पुलिस व बदनामी के डर से महिलाएं मुंह नहीं खोल पा रही हैं.

चौखट भुंजिया एक आदिम जनजाति है. यह विलुप्त होने की श्रेणी में आती है. कहने को तो सरकार ने उसकी संस्कृति, रीति-रिवाजों, भाषा को संरक्षित व उनका विकास करने के लिए कई तरह की योजनाएं मंजूर कर रखी हैं. लेकिन उसकी अपनी पुलिस व अर्ध सैनिक बल उस आदिम जनजाति के अस्तीत्व को ही मीटाने पर तुले हुए हैं.

नुआपाड़ा जिला, कोमना ब्लॉक का सोनाबेड़ा पुलिस कैंप व अभी-अभी डाला गया सोसेंगा पुलिस कैंप इस आदिम जनजाति के अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है. उनके आदिम जन जीवन में हस्तक्षेप, उनकी पिटाई, उनके लाल बंगला में घुस जाना, जिसमें किसी भी दूसरी जाति के व्यक्ति के अंदर जाने पर निषेध होता है, उनकी महिलाओं को हवस का शिकार बनाना, लोगों को जेल ले जाना बढ़ रहा है. इतना ही नहीं फासीवादी तरीके से कुछ आदिवासियों को पैसों, दारु आदि का लालच देकर पुलिस मुखबिर बना रही है. इस कारण भुंजिया को भुंजिया के खिलाफ , कमार को कमार के खिलाफ खड़ा कर रही है. इन दोनों को आपस में लड़वाकर अपना उल्लू सीधा कर रही है.

सरकार द्वारा चौखट भूंजिया विकास एजेंसी (सीबीडीए) का ऑफिस खोला गया था आज वह कोबरा बलों का अड्डा बन गया है. सोसेंगा गांव में स्कूली छात्राओं का हॉस्टल है, उस में पुलिस का कैंप बिठा दिया गया है.

हमारी डिवीजनल कमेटी आदिम जनजातिय इलाकों में खोले जाने वाले पुलिस कैंपों, थानों का विरोध करती है. इसके साथ-साथ निर्दोष आदिवासियों को मारने-पीटने, महिलाओं पर अत्याचार करने की कड़ी निंदा करती है. मानव अधिकार कार्यकर्ताओं, आदिवासी शुभचिंतकों, पत्रकारों, बुध्दिजीवियों से आव्हान करती है कि आदिवासियों को बचाने के लिए आगे आएं. जनता पर किये जा रहे दमन की जांच कर उसको उजागर करें और समाज के सामने सच्चाई पेश करें. ★

टाईगर रिजर्व के नाम पर जनता को विस्थापित करने की साजिश को नाकाम करदो!

विस्थापन के खिलाफ तमाम आदिवासी-गैर आदिवासी जनता एकजुट हो संघर्ष तेज करो!

23 अप्रैल 2014 - मैनपुर डिवीजनल कमेटी

तय करो किस ओर हो
आदमी की ओर हो
या कि आदमखोर की ओर हो

17 अप्रैल को एक दैनिक समाचार पत्र में खबर छपी है कि '13 करोड़ खर्च करवा कर उदंती में दिखा एक बाघ'. यह समाचार उदंती-सितानदी-आमामोरा इलाके की जनता को विस्थापित करने के लिए हो रहे प्रयासों में सबसे नया कदम है. गरियांबद जिला में आने वाले इस टाईगर रिजर्व में एक भी टाईगर नहीं है. लेकिन पीछले 10 सालों से वन विभाग के अधिकारी केंद्र व राज्य सरकारों से टाईगर प्रोजेक्ट के तहत मोटा बजट आवंटन करवाने व उसको खाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाते आ रहे हैं. कभी टाईगर के पंजो के निशान दिखाने के नाम पर तो कभी उसकी आवाज सुनने के नाम पर. 2009 से अब तक इस योजना के तहत 13 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से मिले हैं. पीछले दस सालों में पहली बार यहां आटोमेटिक कैमरे में शेर की तस्वीर कैद होने की बात छापी गयी है. यह जनता को विस्थापित करने की साजिश का ही एक हिस्सा है.

2009 में रायपुर जिला के सितानदी-उदंती एरिया को टाईगर रिजर्व घोषित किया गया था. अब यह इलाका गरियाबंद जिले में आता है. इसे इलाके को दो श्रेणियों में बांटा गया है पहला कोर जोन तो दूसरा बफर जोन. इसमें 51 गांव के 3000 हजार से ज्यादा भारत के मूलनिवासी आदिवासी परिवार निवास करते हैं. एक तरफ हजारों आदमी हैं तो एक तरफ एक आदमखोर. पीछले महीने ही इस इलाके में एक चीते ने 40 से ज्यादा पालतु पशुओं को अपना शिकार बनाया है. छोटे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं. चुनावों में भी यह मुद्दा बना. तो सवाल उठता है कि एक शेर के लिए 1580 वर्ग किलोमीटर के इलाके से क्या हजारों आदिवासियों को उजाड़ना जरूरी है! क्या सदियों से आदिवासी और शेर एक साथ नहीं रहते रहे हैं! शेर विलुप्त होने का कारण आदिवासी हैं या सरकार, वन अधिकारी और वन माफिया. जंगल को खत्म किसने किया है! आदिवासियों ने तो खदाने नहीं खोली, न ही फैक्ट्रीयां लगाई, न ही बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों के लिए इमारती लकड़ी का दोहन किया! यह सब तो सरकार ने पूंजीपतियों के लिए किया है. जंगल में शेर का शिकार आदिवासी नहीं पुलिस, वन अधिकारियों से साठगांठ कर बड़े-बड़े पूंजीपति, जमींदार, राज घरानों के अय्याश शिकारी करते हैं. या फिर तस्कर शिकार करते हैं. लेकिन कोई करे एक बात साफ है - इन सबकी साठगांठ सरकार में बैठे मंत्रियों से लेकर थाने के थानेदारों तक से होती है. तो इसकी सजा हजारों आदिवासियों को विस्थापित कर क्यों दी जा रही है. क्यों उनको तेंदुपत्ता नहीं तोड़ने दिया जाता, क्यों उनकी तेंदुपत्ता समितियां बंद कर दी गयी हैं, क्यों महुआ, शहद, टोरा, मोम, बांस का संग्रहण नहीं करने दिया जाता. जबकि केंद्र सरकार ने वन अधिकार कानून-2006 में इन सब बातों की अनुमति प्रदान की है.

उदंती इलाके के 70 गांवों की जनता ने चुनावों का बहिष्कार की चेतावनी दी थी. उनका प्रमुख मुद्दा यही था. इन में से 17 गांव सितानदी-उदंती टाईगर रिजर्व के कोर जोन में आते हैं. इनकी यह मांग थी कि इस टाईगर रिजर्व को रद्द किया जाये, जंगल में से लघु वनोपजों का संग्रहण करने दिया जाये, गांव में तेंदुपत्ता की फड़ी खोली जाये और सिंचाई के लिए बिजली की व्यवस्था की जाये. लेकिन टाईगर रिजर्व के नाम से जनता को इन तमाम मूलभुत सुविधाओं से दूर रखा जा रहा है. इसी लिए 17 गांव में 4 पुलिस कैंप बिठा दिये गए हैं ताकि आंदोलन को दबाया जा सके.

हम वन्य प्राणियों, खासकर विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने के लिए की जा रही कोशिशों के साथ हैं. हम उन बुध्दिजीवियों, वैज्ञानिकों के साथ हैं जो इस मुहिम में लगे हुए हैं. हमने हमारे इलाके में शिकार पर प्रतिबंध लगाया हुआ है. जहां हमारा प्रभाव है वहां पर शिकार घटा है. और जंगल का रकबा भी बढ़ा है. लेकिन हम इन कोशिशों में जनता के खासकार आदिवासियों के मौलिक अधिकारों के हो रहे हनन के खिलाफ हैं. वन्य प्राणियों के विलुप्त होने की जिम्मेदार सरकार की भूमंडलीकरण,नीजिकरण व उदारीकरण की नीतियां हैं. जिससे जंगल का रकबा घट रहा है. हम मानते हैं कि आदिवासी व जानवरों में कोई शत्रुता नहीं है, वह सहअस्तित्व में रह सकते हैं. वही उनका असली सरंक्षण कर सकते हैं. इसलिए इसकी जिम्मेदारी स्थानीय जनता को ही दी जानी चाहिए न कि उनको विस्थापित करना चाहिए.

टाईगर दिखने की खबर जनता को विस्थापित करने का बहाना मात्र है. हमारी कमेटी वन अधिकारियों को चेतावनी देती है कि वे यहां से जनविरोधी नीतियों पर अमल करने के कारण अपना बोरईया बिस्तर समेट लें, तमाम कैमरों, जीपीएस सिस्टम, वन भवनों को हटा लें. क्योंकि इससे जनता को विस्थापित करने की कोशिशें तेज हो रही हैं. जनता से आव्हान है कि टाईगर रिजर्व के खिलाफ संघर्ष तेज करो, हमारी पार्टी कदम-कदम पर आपके साथ है. ज्ञापन सौंप-सौंप कर आप देख चुके हैं. कोई आपकी नहीं सुनने वाला इसलिए अपनी मूलभूत समस्याओं का हल करने के लिए, जल-जंगल-जमीन पर अपने अधिकार के लिए सशस्त्र कृषि क्रांति ही एकमात्र रास्ता है. आईये माओवादी पार्टी के साथ मिलकर हथियारबंद होकर टाईगर रिजर्व व वन विभाग के तमाम अधिकारियों को खदेड़ दें और अपनी अधिकार कायम कर लें.

11 सीआरपीएफ और 4 पुलिस के जवानों का सफाया 16 हथियारों पर किया कब्जा

11 मार्च 2014 को सुकमा जिला के तोंगपाल के निकट पीएलजीए के बहादुर लाल योध्दाओं ने जनता पर जुल्म के ढहाने के लिए प्रसिध्द सीआरपीएफ व जिला पुलिस के 15 जवानों का सफाया कर दिया. इस शानदार एंबुश के बाद पीएलजीए ने 6 एके-47, 7 इंसास, 2 एसलएलआर, 1 एलएमजी, ग्रेनेड लांचर और दो वाकिटाकियों पर भी कब्जा कर लिया. इतना ही नहीं इसमें 3 जवान भी गंभीर रुप से घायल हुए.

खबरों के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का कार्य चल रहा था. उसे सफल करने के लिए हर रोज सीआरपीएफ की 80वीं बटालियन व जिला पुलिस बल के जवान सुरक्षा देने के लिए आते थे. इस सड़क का निर्मण जन आंदोलन को कुचलने व लोकसभा चुनावों की सुरक्षा के लिए पुलिस व सशस्त्र बलों की आवाजाही के लिए किया जा रहा था. पीएलजीए ने मौका ताड़ कर जबरदस्त एंबुश किया और एक बड़ा झटका झीरमघाटी हमले के बाद फिर उसी जगह पर सीआरपीएफ को दिया.

इस हमले से न केवल राज्य सरकार को बल्कि केंद्र सरकार को भी हिला कर रख दिया. रमन सिंग अपना दिल्ली दौरा रद्द कर आननफानन में वापिस आ गए वहीं कंद्रीय गृहमंत्री भी जगदलपुर आया. उसने अपने संविधान को ताक पर रखते हुए बयान दिया कि इस घटना का बदला लिया जायेगा.

एक तरफ जहां केंद्र राज्य सरकार के हाथ-पांव फूल गए तो दूसरी तरफ क्रांतिकारी जनता व क्रांतिकारी संगठनों ने खुशियों का इजहार किया. मणीपुर रिव्यलूशनरी फ्रंट ने सुकमा हमले का समर्थन करते हुए पीएलजीए को बधाईयां भेजी और कहा कि भारतीय उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है, हम सीपीआई माओवादी द्वारा शुरु किये गए मानव मुक्ति व समानता के संघर्ष को अच्छी तरह समझते हैं और उसका पूरा समर्थन करते हैं. और इसी तरह के कई संदेश दूसरे-दूसरे क्रांतिकारी संगठनों व पार्टियों की तरफ से भी आए.

सरकारी बुध्दिजीवियों, 'अंतरिक सुरक्षा के विशेषज्ञों' ने फिर खुफिया विभाग की कमजोरी, आधुनिक हथियारों के अभाव व कमजोर प्रशिक्षण का राग अलापा. ऐसा कर वे सुरक्षा बलों की कमजोरियों को छुपा रहे हैं. दरअसल सीआरपीएफ, कोबरा, आईटीबीपी, बीएसएफ सहित तमाम राज्यों की पुलिस आधुनिक हथियारों से सिर से पांव तक लैस हैं. सेना की प्रत्यक्ष मदद अभियानों में उनको मिल रही है. जंगल वारफेर जैसे कालेज जगह-जगह बनाए गए हैं. लेकिन वह कमतर व कमजोर हथियारों से लैस लाल गुरिल्लाओं से हमेशा करारी चोट खा रहे हैं. इसका एक मात्र कारण है पीएलजीए को आम जनता की मदद जो सरकारी आतंकी बलों को न तो आधुनिक हथियारों के बल पर न ही सीविक एक्शन जैसे झूठे आर्थिक सुधारों से मिल रही है. गुरिल्लाओं के कमजोर हथियार भी सुरक्षा बलों पर इसलिए भारी पड़ रहे हैं क्योकि हमारे लाल गुरिल्ला जनता के लिए निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का त्याग करने के लिए कभी नहीं हिचकिचाते. हमारे गुरिल्ला पैसों के लिए नहीं जनता की मुक्ति के लिए स्वेच्छा से लड़ रहे हैं. जबकि सुरक्षा बल भाड़े पर अपनी रोजी-रोटी के लिए लड़ते हैं. गुरिल्लाओं की हिम्मत के आगे आधुनिक हथियार भी घुटने टेक रहे हैं. ऐसे बुध्दिजीवि जो सेना उतारने, प्रशिक्षण को बेहतर करने, आधुनिक हथियारों को खरीदने की सलाहे दे रहे हैं वह जनता के दुश्मन हैं. उनके ये सारे सलाह सुझाव भारतीय गरीब व आदिवासी जनता पर और ज्यादा दमन को बढ़ाने के लिए जनमत तैयार करने, दमन को वैध ठहराने के लिए दिये जा रहे हैं. ऐसी सलाहों से माओवाद खत्म नहीं हो सकता. माओवाद जनता की मूलभुत समस्याओं से पैदा हुआ है. जब तक वह समस्याएं समाप्त नहीं होती तब तक माओवादी आंदोलन जारी रहेगा. और वह समस्याए हैं भूमिहीन किसानों को भूमि नहीं, रोटी-कपड़ा-मकान नहीं, बेरोजगारी, भूख, गरीबी और एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण. जब तक यह खत्म नहीं होता हमारा संग्राम जारी रहेगा.

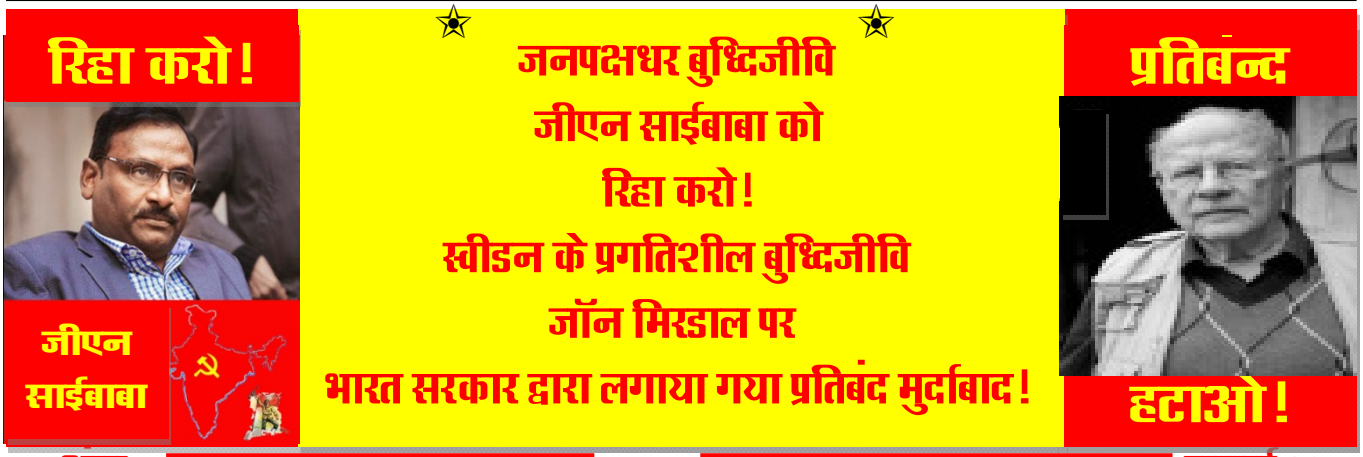

सैध्दांतिक लेख

पध्दति

(संक्षप्ति नोट्स)

पिछले अंक में हमने 'कार्यशैली' नामक लेख छापा था. अबकी बार हम पध्दति नामक यह लेख छाप रहे हैं. यह लेख महान शिक्षक कामरेड स्तालिन की पुस्तक 'लेनिनवाद के मूलसिध्दांत' नामक पुस्तक से लिया गया है. हमारी आशा है कि पार्टी कार्यकर्ता इसे ध्यानपूर्वक पढ़ कर इस पर अमल करेंगे और अपनी कमजोर पध्दति को छोड़कर लेनिनवादी पध्दति को अपनाएंगे जिससे क्रांतिकारी आंदोलन आगे बढ़ सके. यह लेख पार्टी द्वारा शुरु किये गए बोल्शेविककरण अभियान के तहत छापा जा रहा है. यह मूल लेख का संक्षिप्त रुप है.

लेनिनवादी पध्दति की क्यों जरुरत पड़ी ?

लेनिनवादी पध्दति की जरुरत दूसरे इंटरनेशनल[0] की कमजोरियों खासकर उसके अवसरवादी मार्ग के खिलाफ पड़ी थी.

क्योंकि – दूसरे इंटरनेशनल में मौजूद पार्टियां आराम से पैर फैलाकर सो रही थीं. क्रांति, सर्वहारा अधिनायकत्व और जनता की क्रांतिकारी शिक्षा आदि के प्रश्नों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की ओर उनका ध्यान नहीं था.

क्योंकि सही जागरुक क्रांतिकारी नीति की जगह पर राजनीतिक मोलतोल, कानूनी कूटनीतिज्ञता और संसद भवन के जोड़तोड़ और तिकड़मों का बोलबाला था. दिखाने के लिए क्रांतिकारी दिखने वाले प्रस्ताव और नारे तो दिये जाते थे लेकिन बाद में उन पर अमल नहीं होता था.

क्योंकि - पार्टी सदस्यों को सही क्रांतिकारी कार्यनीति सिखलाने और अपनी भूलों को सुधारने में उनकी सहायता की बजाय, विवादस्पद प्रश्नों पर जानबूझकर चुप्पी साध ली जाती थी. विवादस्पद प्रश्नों का सही ढंग से हल नहीं किया जाता था,

क्योंकि - सामने आ रही क्रांतिकारी परिस्थितियों को देखते हुए, उनका सही इस्तेमाल करने के लिए दूसरे इंटरनेशनल की पार्टियों के काम के सारे तरीकों को पूरी तरह बदल देना जरुरी हो गया था. नहीं तो पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना, मजदूरों को तैयार करना संभव नहीं हो पाता था.

इसी से लेनिनवादी पध्दति का जन्म हुआ. इसकी बहुत जरुरत थी

पहली जरुरत ....सैध्दांतिक वाद-विवादों को जनता के क्रांतिकारी आंदोलन की कसौटी पर, जीवित प्रयोग की कसौटी पर, परखा जाये. यानि सिध्दांत और व्यवहार के टूटे हुए समन्वय को फिर से जोड़ा जाये तथा सिध्दांत और व्यवहार के बीच की खाई को भर कर बराबर कर दिया जाये. क्रांतिकारी सिध्दांत के हथियार से सुसज्जित सच्ची क्रांतिकारी पार्टी का केवल इसी तरह से निर्माण किया जा सकता था.

दूसरी जरुरत यह थी कि - दूसरे इंटरनेशनल की पार्टियों की नीति का मूल्य उनके नारों और प्रस्तावों के अनुसार नहीं बल्कि उनके आचरण और कार्यों के अनुसार आंका जाये. सिर्फ इसी रास्ते से मजदूर वर्ग का विश्वास प्राप्त किया जा सकता था और उसके विश्वास के योग्य बना जा सकता था.

तीसरी जरुरत इस बात की थी कि क्रांतिकारी युध्द के लिए जनता को तैयार करने के उद्देश्य से पार्टी के तमाम कार्यों का नये और क्रांतिकारी ढंग से पुनर्गठन किया जाये. जनता को सर्वहारा क्रांति के लिए तैयार करने का यही एक मात्र तरीका था.

चौथी जरुरत इस चीज की थी कि मजदूर पार्टियों के अंदर आत्मालोचना का प्रचार किया जाये, जिससे कि वे अपनी भूलों से सीख सकें और इस प्रकार अपने को शिक्षित और कार्यकुशल बना सकें. पार्टी के सच्चे कार्यकर्ताओं और सच्चे नेताओं को शिक्षित करने का यही एक मार्ग था.

यह लेनिनवादी पध्दति का आधार है और यही उसका सारांश है.

इस पध्दति को प्रयोग में कैसे लाया गया ?

सर्वहारा को अल्पमत में होते हुए भी राजसत्ता पर अधिकार के लिए लड़ना चाहिए. लेनिन ने कहा है - मान लिजिए कि ऐसी ऐतिहासिक परिस्थिति उत्पन्न हो जाये जैसे युध्द, कृषि संकट आदि यानि जिस में सर्वहारा वर्ग, तमाम विशाल जनसंख्या के हिसाब से अल्पमत में होते

हुए भी, इस अवस्था में हो कि वह मेहनतकशों के विशाल जनसमूह को अपने पक्ष में कर सकता है तो इस हालत में उसे राजसत्ता को अपने हाथों में ले लेना चाहिए.

राजसत्ता पर कब्जा कर के सर्वहारा वर्ग के समुचित विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करके मेहनतकश जनसमूह को सांस्कृतिक रुप से उंचा उठाना चाहिए, उस दिशा में लंबे-लंबे डग भरकर मजदूरों के अंदर से सैकड़ों शिक्षक, नेता, और शासक तैयार करने चाहिए. मजदूरों के अंदर से चुने हुए कार्यकर्ता सर्वहारा राज्य की छत्रछाया में पूंजीवादी राज्य की अपेक्षा सौ गुनी तेजी से बढ़ते और नेतृत्व की योग्यता प्राप्त करते हैं. यह सिध्दांत गलत है कि मजदूर या सर्वहारा वर्ग राजसत्ता पर कब्जा करने के योग्य नहीं है, उसे पहले इस योग्य होकर राजसत्ता पर कब्जा करना चाहिए.

सर्वहारा वर्ग के संघर्षों का प्रधान रुप गैर कानूनी संघर्ष है. क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास यह साबित करता है कि कानूनी संघर्ष, गैर कानूनी संघर्ष सीखने का स्कूल होता है. पूंजीवादी शासन व्यवस्था में मजदूर वर्ग की मौलिक समस्याओं का हल तो बल प्रयोग से ही हो सकता है.

''क्रांतिकारी सिध्दांत कोई धार्मिक सिध्दांत नहीं है, क्रांतिकारी सिध्दांत वास्तविक क्रांतिकारी जनांदोलन के संपर्क में आकर ही परिपक्व होता है'' .... सिध्दांत को व्यवहार का मार्गदर्शन करना चाहिए, सिध्दांत को व्यवाहारिक क्षेत्र में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए''. - लेनिन

केवल कागजी नारों और प्रस्ताव के पास करने वाली और व्यवहार में असवरवादी पार्टियों की तीव्र आलोचना करते हुए लेनिन ने लिखा है -

''काउत्सकी की यह उक्ति कि *नारा लगाने से ही स्थिति बदल जाती है,* निम्न पूंजीवादी वर्ग के एक अधकचरे दिमाग की उपज है. पूंजीवादी जनवाद का सारा इतिहास काउत्सी[1] के इस मत को असत्य प्रमाणित कर रहा है. जनता को धोखा देने के लिए पूंजीवादी जनवादी लोग बराबर तरह-तरह के 'नारे' लगाते आए है. और आज भी लगा रहे हैं. लेकिन सवाल है कि उनकी ईमानदारी की *जांच करने का,* उनके शब्दों का मूल्य उनके कार्यों से लगाने का, हमें इन लोगों की धोखेबाज और आदर्शवादी *बातों से* संतुष्ट न होकर उनके पीछे छिपी हुई *वर्गीय सच्चाई की* की खोज करी चाहिए'' लेनिन

आत्मलोचना से किसी को डरना नहीं चाहिए. अपनी गलतियों को छुपाना नहीं चाहिए. प्रधान और विवादस्पद प्रश्नों से बचना नहीं चाहिए. *सबकुछ ठीक है का झूठा दावा करके वे अपनी कमजारियों को ढंके रखना चाहती हैं, जिनसे विचार शक्ति जड़ हो जाती है, और पार्टी की क्रांतिकारी शिक्षा में बाधा पड़ती है, क्योंकि इससे अपनी भूलों से सबक लेने का मार्ग बंद कर दिया जाता है. लेनिन ने लिखा है*

अपनी भूलों के प्रति किसी राजनीतिक पार्टी का रुख क्या है? यह उसकी तत्परता और ईमानदारी का पता लगाने का सबसे अच्छा और निश्चित तरीका है. इससे यह जाना जा सकता है कि अपने वर्ग और श्रमजीवी जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन वह व्यवहार में किस हद तक कर रही है. किसी भूल को स्पष्ट शब्दों में स्वीकार कर लेना, उसके कारणों को ढूंढना, उसे उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का विश्लेषण करना और उसके सुधार के उपयों पर गंभीरतापूर्वक विचार और चर्चा करना - किसी तत्पर और ईमानदार पार्टि के ये ही लक्षण हैं. इसी तरह अपने वर्ग की और सारी जनता की शिक्षादीक्षा करनी चाहिए - लेनिन

''क्रांतिकारी सिध्दांत कोई धार्मिक सिध्दांत नहीं है, क्रांतिकारी सिध्दांत वास्तविक क्रांतिकारी जनांदोलन के संपर्क में आकर ही परिपक्व होता है'' .... सिध्दांत को व्यवहार का मार्गदर्शन करना चाहिए, सिध्दांत को व्यवाहारिक क्षेत्र में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए''. - **लेनिन**

कुछ लोग कहतें हैं कि अपनी निजी भूलों को उघाड़ना और अपनी आलोचना आप करना पार्टी के लिए खतरे की चीजें हैं, क्योंकि दुश्मन उसका इस्तेमाल सर्वहारा पार्टी के खिलाफ कर सकता है. लेनिन इन आपत्तियों को तुच्छ और बिल्कुल गलत मानते थे. सन् 1904 में ही जब हमारी पार्टी अभी छोटी और कमजोर थी, लेनिन ने अपनी पुस्तक में एक कदम आगे दो कदम पीछे में इस बात पर अपनी राय प्रकट की थी :

''हमारे विवादों को सुनसुन कर वे यानि मार्क्सवादियों के विरोधी, मुंह बनाते हैं और आंखें चमकाते हैं, और सच पूछीए तो वे मेरी पुस्तिका से अलग-अलग ऐसे पहरों को चुनने की कोशिश करेंगे जो हमारी पार्टि की कमियों व कमजोरियों को दर्शाते हैं और उनका प्रयोग अपनी स्वार्थ साधाना के लिए करेंगे. परंतु रुसी मार्क्सवादी संघर्ष की भट्ठी में तपकर अब तक काफी मजबूत बन चुके हैं. इन तुच्छ मजाकों से वे विचलित नहीं हो सकते. इन लोगों को परवाह किये बिना स्वयं अपनी आलोचना करने और अपनी कमियों को अच्छी तरह खोलकर दिखा देने के पथ पर वे निरंतर बढ़ते जायेंगे. जैसे जैसे मजदूर आंदोलन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी कमियां और खामियां निश्चिय ही दूर हो जायेंगे'' लेनिन ☆

भगत सिंग की बात सुनो - माओवाद की राह चुनो

भगत सिंग के महत्वपूर्ण दस्तावेजों की श्रृंखला

अछूत समस्या

सोए हुए शेरो! उठो और बगावत खड़ी कर दो!

काकिनाडा में 1923 में कांग्रेस - अधिवेशन हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने भाषण में आजकल की अनुसूचित जातियों को, जिन्हें उन दिनों अछूत कहा जाता था, हिन्दू और मुस्लिम मिशनरी संस्थाओं में बाँट देने का सुझाव दिया। हिन्दू और मुस्लिम अमीर लोग इस वर्गभेद को पक्का करने के लिए धन देने को तैयार थे।

इस प्रकार अछूतों के यह 'दोस्त' उन्हें धर्म के नाम पर बांटने की कोशिशें करते थे। उसी समय जब इस मसले पर बहस का वातावरण था, भगतसिंह ने 'अछूत का सवाल' नामक लेख लिखा। इस लेख में श्रमिक वर्ग की शक्ति व सीमाओं का अनुमान लगाकर उसकी प्रगति के लिए ठोस सुझाव दिये गये हैं। भगतसंह का यह लेख जून, 1928 के 'किरती' नाम पत्रिका में विद्रोही नाम से प्रकाशित हुआ था। इस लेख को लिखे हुए आज 86 साल हो चुके हैं. लेकिन आज भी देश में यह समस्या बनी हुई है. आज भी दलितों पर आए दिन अत्याचार होते हैं. इस समस्या को समझने के लिए हम यह लेख 'जनसंग्राम' प्रकाशित कर रहे हैं.- सं.

हमारे देश - जैसे बुरे हालात किसी दूसरे देश के नहीं हुए। यहाँ अजब-अजब सवाल उठते रहते हैं। एक अहम सवाल अछूत समस्या है। समस्या यह है कि 30 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में जो 6 करोड़ लोग अछूत कहलाते हैं, उनके स्पर्श मात्र से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा! उनके मंदिरों में प्रवेश से देवगण नाराज हो उठेंगे! कुएं से उनके द्वारा पानी निकालने से कुआँ अपवित्र हो जाएगा! ये सवाल बिसवीं सदी में किए जा रहे हैं, जिन्हें कि सुनते ही शर्म आती है।

हमारा देश बहुत अध्यात्मवादी हैं, लेकिन हम मनुष्य को मनुष्य का दर्जा देते हुए भी झिझकते हैं जबकि पूर्णतया भौतिकवादी कहलाने वाला यूरोप कई सदियों से इन्कलाब की आवाज उठा रहा है। उन्होंने अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों के दौरान ही समानता की घोषणा कर दी थी। आज रुस ने भी हर प्रकार का भेदभाव मिटा कर क्रांति के लिए कमर कसी हुई है। हम सदा ही आत्मा-परमात्मा के वजूद को लेकर चिन्तित होने तथा इस जोरदार बहस में उलझे हुए हैं कि क्या अछूत को जनेऊ दे दिया जाएगा? वे वेद शास्त्र पढ़ने के अधिकारी हैं अथवा नहीं? हम उलाहना देते हैं कि हमारे साथ विदेशों में अच्छा सलूक नहीं होता। अंग्रेजी शासन हमें अंग्रेजों के समान नहीं समझता। लेकिन क्या हमें यह शिकायत करने का अधिकार है?

सिन्ध के एक मुस्लिम सज्जन श्री नूर मुहम्मद ने, जो बम्बई कौंसिल के सदस्य हैं, इस विषय पर 1926 में खुब कहा

"If the Hundu society refuses to allow other human beings, fellow creatures so that to attend public school, and if|| the president of local board representing so many lakhs of people in this house refuses to allow his fellows and brothers the elementary human right of having water to drink, what right have they to ask for right of having water to drink, what right have they to ask for more rights from the bureaucracy? Before we accuse people coming from other lands, we should see how we ourselves behave toward our own people How can we ask for greater political rights when we ourselves deny lementary rights of human beings."

वे कहते हैं कि जब तुम एक इन्सान को पीने के लिए पानी देने से भी इनकार करते हो, जब तुम उन्हे स्कूल में भी पढ़ने नहीं देते तो तुम्हें क्या अधिकार है अपने लिए अधिक अधिकारों की माँग करो? जब तुम एक इन्सान को समान अधिकार देने से भी इनकार करते हो तो तुम अधिक राजनीतिक अधिकार माँगने के अधिकारी कैसे बन गए?

बात बिल्कुल खरी है। यह क्योंकि एक मुस्लिम ने कही है इसलिए हिन्दू कहेंगे कि देखो, वह उन अछूतों को मुस्लमान बना कर अपने में शामिल करना चाहते हैं।

जब तुम उन्हें इस तरह पशुओं से भी गया-बीता समझोगे तो वह जरूरी ही दूसरे धर्मों में शामिल हो जाएंगे, जिनमें उन्हें अधिक अधिकार मिलेंगे, जहां

उनसे इन्सानों जैसा व्यवहार किया जाएगा। फिर यह कहना कि देखो जी, ईसाई और मुस्लमान हिन्दू कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, व्यर्थ होगा।

कितना स्पष्ट कथन है, लेकिन यह सुन कर सभी तिलमिला उठते हैं। ठीक इसी तरह की चिन्ता हिन्दूओं को भी हुई। सनातनी पण्डित भी कुछ-न-कुछ इस मसले पर सोचना लगे। बीच-बीच में बड़े युगांतरकारी कहे जानेवाले भी शामिल हुए। पटना में हिन्दू महासभा का सम्मेलन लाल लाजपत राय (जोकि अछूतों के बहुत पूराने समर्थक चले आ रहे हैं) की अध्यक्षता में हुआ, तो जोरदार बहस छिड़ी। अच्छी नोंक-झोंक हुई। समस्या यह थी कि अछूतों को यज्ञोपवीत धारण करने का हक है अथवा नहीं? तथा क्या उन्हें देव- शास्त्रों का अध्ययन करने का अधिकार है? बड़े-बड़े समाज-सुधारक तमतमा गये, लेकिन लालजी ने सबको सहमत कर दिया तथा यह दो बातें स्वीकृत कर हिन्दू धर्म की लाज रख ली। वरना जरा सोचो, कितनी शर्म की बात होती। कुत्ता हमारे गोद में बैठ सकता है। हमारी रसोई में नंगा फिरता है, लेकिन एक इन्सान का हमसे स्पर्श हो जाए तो बस धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इस समय मालवीय जी जैसे बड़े समाज-सुधारक, अछूतों के बड़े प्रेमी और न जाने क्या-क्या पहले एक मेहतर के हाथों गले में हर डलवा लेते हैं, लेकिन कपड़ों सहित स्नान किये बिना स्वयं को अशुद्ध समझते हैं! क्या खूब यह चाल है! सबको प्यार करने वाले भगवान की पूजा करने के लिए मन्दिर बना है लेकिन वहां अछूत जा घुसे तो वह मन्दिर अपवित्र हो जाता है! भगवान रुष्ट हो जाता है! घर की जब यह स्थिति हो तो बाहर हम बराबरी के नाम पर झगड़ते अच्छे लगते हैं? तब हमारे इस रवैये में कृतघ्नता की भी हद पाई जाती है। जो निम्नतम काम करके हमारे लिए सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं उन्हें ही हम दुरदुराते हैं। पशुओं की हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन इन्सान को पास नहीं बिठा सकते!

आज इस सवाल पर बहुत शोर हो रहा है। उन विचारों पर आजकल विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश में मुक्ति कामना जिस तरह बढ़ रही है, उसमें साम्प्रदायिक भावना ने और कोई लाभ पहुँचाया हो अथवा नहीं लेकिन एक लाभ जरूर पहुंचाया है। अधिक अधिकारों की मांग के लिए अपनी-अपनी कौमों की संख्या बढ़ाने की चिन्ता सबको हुई। मुस्लिमों ने जरा ज्यादा जोर दिया। उन्होंने अछूतों को मुसलमान बना कर अपने बराबर अधिकार देने शुरूकर दिए। इससे हिन्दूओं के अहम को चोट पहुँची । स्पर्धा बढ़ी। फसाद भी हुए। धीरे-धीरे सिखों ने भी सोचा कि हम पीछे न रह जायें। उन्होंने भी अमृत छकाना आरम्भ कर दिया। हिन्दू-सिखों के बीच अछूतों के जनेऊ उतारने या केश कटवाने के सवालों पर झगड़े हुए। अब तीनों कौमें अछूतों को अपनी-अपनी ओर खींच रही है। इसका बहुत शोर-शराबा है। उधार ईसाई चुपचाप उनका रुतबा बढ़ा रहे हैं। चलो, इस सारी हलचल से ही देश के दुर्भाग्य की लानत दूर हो रही है।

इधर जब अछूतों ने देखा कि उनकी वजह से इनमें फसाद हो रहे हैं तथा उन्हें हर कोई अपनी-अपनी खुराक समझ रहा है तो वे अलग ही क्यों न संगठित हो जाएं? इस विचार के अमल में अंग्रेजी सरकार का कोई हाथ हो अथवा न हो लेकिन इतना अवश्य है कि इस प्रचार में सरकारी मशीनरी का काफी हाथ था। 'आदि धर्म मण्डल' जैसे संगठन उस विचार के प्रचार का परिणाम हैं।

अब एक सवाल और उठता है कि इस समस्या का सही निदान क्या है? इसका जवाब बड़ा अहम है। सबसे पहले यह निर्णय कर लेना चाहिए कि सब इन्सान समान हैं तथा न तो जन्म से कोई भिन्न पैदा हुआ और न कार्य विभाजन से। अर्थात् क्योंकि एक आदमी गरीब मेहतर के घर पैदा हो गया है, इसलिए जीवन भर मैला ही साफ करेगा और दुनिया में किसी तरह के विकास का काम पाने का उसे कोई हक नहीं है, ये बातें फिजूल हैं। इस तरह हमारे पूर्वज आर्यो ने इनके साथ ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार किया तथा उन्हें नीच कह कर दुत्कार दिया एवं निम्नकोटी का कार्य करवाने लगे। साथ ही यह भी चिन्ता हुई कि कहीं ये विद्रोह न कर दें, तब पुनर्जन्म के दर्शन का प्रचार कर दिया कि यह तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का फल है। अब क्या हो सकता है? चुपचाप दिन गुजारो! इस तरह उन्हें धैर्य का उपदेश देकर वे लोग उन्हें लम्बे समय तक के लिए शान्त करा गए।

लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अर्थात् संगठनबद्ध हो अपने पैरों पर खड़े होकर पूरे समाज को चुनौती दे दो। तब देखना,कोई भी तुम्हें तुम्हारे अधिकार देने से इन्कार करने की जुर्रत न कर सकेगा। तुम दूसरों की खूराक मत बनो। दूसरों के मुंह की ओर न ताको। लेकिन ध्यान रहे, नौकरशाही के झांसे में मत फंसना। यह तुम्हारी कोई सहायता नहीं करना चाहती, बल्कि तुम्हें अपना मोहरा बनाना चाहती है। यही पूंजीवादी नौकरशाही तुम्हारी गुलामी और गरीबी का असली कारण है। इसलिए तुम उसके साथ कभी न मिलना। उसकी चालों से बचना। तब सब कुछ ठीक हो जायेगा। तुम असली सर्वहारा हो... संगठनबद्ध हो जाओ। तुम्हारी कुछ भी हानि न होगी। बस गुलामी की जंजीरें कट जाएंगी। उठो, और वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध बगावत खड़ी कर दो। धीरे-धीरे होनेवाले सुधारों से कुछ नहीं बन सकेगा। सामाजिक आन्दोलन से क्रांतिकारी पैदा कर दो तथा राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। तुम ही तो देश का मुख्य आधार हो, वास्तविक शक्ति हो। सोए हुए शेरो! उठो और बगावत खड़ी कर दो।

लेकिन उन्होंने बड़ा पाप किया। मानव के भीतर की मानवियता को समाप्त कर दिया। आत्मविश्वास एवं स्वावलम्बन की भावनाओं को समाप्त कर दिया। बहुत दमन और अन्याय किया गया। आज उस सबके प्रायश्चित का वक्त है।

इसके साथ एक दूसरी गड़बड़ी हो गयी। लोगों के मनों में आवश्यक कार्यों के प्रति घृणा पैदा हो गई। हमने जुलाहे को भी दुत्कारा। आज कपड़ा बुननेवाले भी अछूत समझे जाते हैं । यूपी की तरफ कहार को भी अछूत समझा जाता है। इससे बड़ी गड़बड़ी पैदा हुई। ऐसे में विकास की प्रक्रिया में रुकावटें पैदा हो रही हैं।

इन तबकों को अपने समक्ष रखते हुए हमें चाहिए कि हम न इन्हें अछूत कहें और न समझें। बस, समस्या हल हो जाती है। नौजवान भारत सभा तथा नौजवान कांग्रेस ने जो ढंग अपनाया है वह काफी अच्छा है। जिन्हें आज तक अछूत कहा जाता रहा उनसे अपने इन पापों के लिए क्षमायाचना करनी चाहिए तथा उन्हें अपने जैसा इन्सान समझना, बिना अमृत छकाए, बिना कलमा पढ़ाए या शुद्धि किए उन्हें अपने में शामिल करके उनके हाथ से पानी-पीना यही उचित ढंग है। और आपस में खींचतान करना और व्यवहार में कोई भी हक न देना कोई ठीक बात नहीं है।

जब गाँवों में मजदूर-प्रचार शुरू हुआ उस समय किसानों को सरकारी आदमी यह बात समझा कर भड़काते थे कि देखो, यह भंगी-चमारों को सिर पर चढ़ा रहे हैं और तुम्हारा काम बंद करवाएंगे। बस किसान इतने में ही भड़क गए। उन्हें याद रहना चाहिए कि उनकी हालत तब तक नहीं सुधर सकती जब तक कि वे इन गरीबों को नीच और कमीन कह कर अपनी जूती के नीचे दबाए रखना चाहते हैं। अक्सर कहा जाता है कि वह साफ नहीं रहते। इसका उत्तर साफ है- वे गरीब हैं। गरीबी का इलाज करो। ऊंचे-ऊचे कुलों के गरीब लोग भी कोई कम गन्दे नहीं रहते। गन्दे काम करने का बहाना भी नहीं चल सकता, क्योंकि माताएं बच्चों का मैला साफ करने से मेहतर तथा अछूत तो नहीं हो जातीं।

लेकिन यह काम उतने समय तक नहीं हो सकता जितने समय तक कि अछूत कौमें अपने आपको संगठित न कर लें। हम तो समझते हैं कि उनका स्वयं को अलग संगठनबद्ध करना तथा मुस्लिमों के बराबर गिनती में होने के कारण उनके बराबर अधिकारों की मांग करना बहुत आशाजनक संकेत हैं। या तो साम्प्रदायिक भेद का झंझट ही खत्म करो, नहीं तो उनके अलग अधिकार उन्हें दे दो। कौंसिलों और असेम्बलियों का कर्तव्य है कि वे स्कूल-कॉलेज, कुएं तथा सड़क के उपयोग की पूरी स्वतंत्रता उन्हें दिलाएं। जबानी तौर पर ही नहीं, वरन साथ ले जाकर उन्हें कुओं पर चढ़ाएं। उनके बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाएं। लेकिन जिस असेंबली में बालविवाह के विरुद्ध पेश किए बिल तथा धर्म के बहाने हाय-तौबा मचाई जाती है, वहां वे अछूतों को अपने साथ शामिल करने का साहस कैसे कर सकते हैं?

इसलिए हम मानते हैं कि उनके अपने जनप्रतिनिधि हों। वे अपने लिए अधिक अधिकार माँगें। हम तो साफ कहते हैं कि ऊठों, अछूत कहलाने वालो असली जनसेवको तथा भाईयों! ऊठों! अपना इतिहास देखो। गुरु गोविन्दसिंह की फौज की असली शक्ति तुम्हीं थे। शिवाजी तुम्हारे भरोसे पर ही सब कुछ कर सके, जिस कारण उनका नाम आज भी जिन्दा है। तुम्हारी कुर्बानियां स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई हैं। तुम जो नित्यप्रति सेवा करके जनता के सुखों में बढ़ोतरी करके और जिन्दागी संभव बना कर यह बड़ा भारी अहसान कर रहे हो, उसे हम लोग नहीं समझते। लैण्ड-एलियेनेशन एक्ट के अनुसार तुम धन एकत्र कर भी जमीन नहीं खरीद सकते। तुम पर इतना जुल्म हो रहा है कि मिस मेयो मनुष्यों से भी कहती हैं- उठों अपनी शक्ति पहचानो। संगठनबद्ध हो जाओ। असल में स्वयं कोशिश किए बिना कुछ भी न मिल सकेगा। (Those who would be free must themselves strike the blow) स्वतंत्रता के लिए स्वाधीनता चाहने वालों को यत्न करना चाहिए। इन्सान की धीरे-धीरे कुछ ऐसी आदतें हो गई हैं कि वह अपने लिए तो अधिक अधिकार चाहता है, लेकिन जो उनके मातहत हैं उन्हें वह अपनी जूती के नीचे ही दबाए रखना चाहता है। कहावत है- लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अर्थात् संगठनबद्ध हो अपने पैरों पर खड़े होकर पूरे समाज को चुनौती दे दो। तब देखना,कोई भी तुम्हें तुम्हारे अधिकार देने से इन्कार करने की जुर्रत न कर सकेगा। तुम दूसरों की खूराक मत बनो। दूसरों के मुंह की ओर न ताको। लेकिन ध्यान रहे, नौकरशाही के झांसे में मत फंसना। यह तुम्हारी कोई सहायता नहीं करना चाहती, बल्कि तुम्हें अपना मोहरा बनाना चाहती है। यही पूंजीवादी नौकरशाही तुम्हारी गुलामी और गरीबी का असली कारण है। इसलिए तुम उसके साथ कभी न मिलना। उसकी चालों से बचना। तब सब कुछ ठीक हो जायेगा। तुम असली सर्वहारा हो... संगठनबद्ध हो जाओ। तुम्हारी कुछ भी हानि न होगी। बस गुलामी की जंजीरें कट जाएंगी। उठो, और वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध बगावत खड़ी कर दो। धीरे-धीरे होनेवाले सुधारों से कुछ नहीं बन सकेगा। सामाजिक आन्दोलन से क्रांतिकारी पैदा कर दो तथा राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। तुम ही तो देश का मुख्य आधार हो, वास्तविक शक्ति हो। सोए हुए शेरो! उठो और बगावत खड़ी कर दो।

'अच्छे दिन आने वाले हैं'... 'विदेशी कंपनियों के! जमींदारों के!! दलाल पूंजीतियों के!!!

भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की जीत

मेहनतकशों की लूट, जनआंदोलनों का दमन व फासीवाद के बढ़ने का संकेत!

ब्रह्मणवादी हिंदू फासीवाद के खतरे को हराने के लिए

सभी क्रांतिकारी और जनवादी तकतों को एकजुट कर व्यापक संघर्ष का निर्माण करो!

बहुत समय नहीं बिता है जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आने से पहले नारा दिया 'अच्छे दिन आने वाले हैं' लेकिन सत्ता में आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है. जनता को समझ में आ गया है कि अच्छे दिन किस के लिए आए हैं और बुरे दिन किसके लिए आए हैं. नरेंद्र मोदी की जीत की आहट से ही विदेशी कंपनियों और दलाल बड़े पूंजीपतियों की बांछे खिल उठी थीं. देश का शेयर बाजार सारे रिकार्ड तोड़कर 26 हजार से ज्यादा अंकों पर पहुंच गया है. क्या यह आसानी से समझ में नहीं आता की भारत में वित्तीय पूंजी का यह प्रवाह पूंजीपतियों के फायदे के लिए नहीं है! इसे समझने के लिए वेद पढ़ने की जरुरत नहीं है कि पूंजीपति केवल और केवल मुनाफे के लिए ही इतना निवेश भारत में कर रहे हैं! ऐसा ही उच्छाल शेयर बाजार में यूपीए की सरकार जब मनमोहन सिंग के नेतृत्व में बनी तब भी आया था. तब भी शेयर बाजार ने सारे रिकार्ड तोड़कर 20 हजार का आंकड़ा पार कर लिया था. और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा. जनता को. नरेंद्र मोदी जिस 'गुजरात विकास मॉडल' का नारा देकर सत्ता में आया है वह मनमोहन सिंग द्वारा शुरु की गयी आर्थिक नीतियों का ही परिणाम है. मनमोहन सिंग ने ही निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण की शुरुआत की थी. उन्हीं आर्थिक नीतियों के दुष्परिणाम का नतीजा था देश में भयांकर भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण, भूख, गरीबी. इस दुष्परिणाम के कारण मनमोहन सिंग की सरकार बुरी तरह हारी. साम्राज्यवादियों को भी मनमोहन सिंग बुढ़ा शेर दिखने लगा जो अब शिकार करने के काबिल नहीं रहा. साम्राज्वादियों को एक ऐसे शख्स की जरुरत थी जो लोगों को बरगलाने, बहकाने में माहिर हो, जो दूसरे दौर के आर्थिक 'सुधारों' को लागू कर सके. वह शख्स नरेंद्र मोदी दिखाई दिया. और साम्राज्यवादियों, विदेशी कंपनियों व देश के बड़े उद्योग घरानों ने मिलकर नरेंद्र मोदी को 'विकासपुरुष' बना दिया. और अब आ रहे हैं उनके अच्छे दिन!

सरकार बने दो महीने नहीं हुए हैं असलियत सामने है. आलू-प्याज लोगों को थालियों से गायब होता जा रहा है. किसान जब अपने आलू-प्याज को मंडियों में लेकर जाते हैं तो उन्हें कोड़ियों के दाम में खरीदा जाता है और जब पूंजीतियों, बड़े व्यापारियों के गोदाम में जमा हो जाते हैं तो वह आलू-प्याज 40 से 80 रुपये किलो तक पहुंच जाता है. सरकार किसानों की सब्जियों के लिए कोई नीति ही नहीं बना रही. सब बड़े व्यापारी तो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं. उन पर क्यों सरकार कार्रवाई करेगी. डिजल-पेट्रोल और रेल किराया में बढ़ोतरी कर सरकार ने महंगाई के राकेट को आग लगा दी है जो आसामान को चीरता जा रहा है! पिछले दस सालों में रेल किराया नहीं बढ़ा था लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने दो महीनों में ही बढ़ा दिया है. इतना ही नहीं 13 लाख रेल कर्मचारियों का भविष्य भी अब अंधकारमय नजर आ रहा है. नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई को अपने खास 'नाटकिय अंदाज' में भषाण दिया है कि जब सरकारी सड़कों पर निजी वहान चल सकते हैं, तो...सरकारी रेल पटरियों पर प्राईवेट रेल गाड़ियों क्यों नहीं चल सकती!' बात सीधी सी है जिस रेल मंत्रालय को सरकार चलाती थी, उसके लिए अलग से रेल बजट पारित करती थी आने वाले सालों में अब उसका जिम्मा देश विदेश के पूंजीपति टाटा, अंबानी, मित्तल जैसे लोग संभालेंगे.

जब पूंजीवादी व्यवस्था अपने अंतहिन संकट में फंस जाती है और निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता. दिन ब दिन जनता का गुस्सा सरकारों के खिलाफ, पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ बढ़ जाता है, जनता क्रांति चाहती है, हर शोषण व जुल्म को उखाड़ फैंकना चाहती है तब फासीवाद का उदय होता है. तब बुर्जुआ राजनीतिक पार्टियां जनता के गुस्से को अपने फायदे के लिए अल्पसंख्यक समुदायों की तरफ मोड़ देती है. क्योंकि उसे बहुसंख्यक शोषित जनता से खतरा होता है. इसलिए वह उसे अपने खिलाफ नहीं खड़ा होने देती. आज देश में हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या ज्यादा है. लेकिन क्या सारे हिंदू धर्म को मानने वाले मुस्लमानों, इसाइयों, सिखों को अपना दुश्मन मानते हैं. बिल्कुल भी नहीं. देश में नरेंद्र मोदी की बिजेपी सरकार विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, शिवसेना, बजरंगदल जैसे कट्टरपंथी हिंदूत्ववादी संगठनों के गुप्त एजेंडे पर काम करना शुरु कर दी है. आज जब देश की जनता अपने जल-जंगल-जमीन को बचाने के लिए, विदेशी व बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के खिलाफ, विस्थापन के खिलाफ लड़ रही है तो नरेंद्र मोदी सरकार इन को दमन के जरिये दबाने के लिए दिन रात तैयारियों में जुट गयी है. जनता का महंगाई, भ्रष्टाचार, भूख, गरीबी जैसी बुनियादी समस्याओं से ध्यान हटा कर उसका ध्यान अंधविश्वास, आस्था, धार्मिक

भावनाओं की तरफ मोड़ रही है. जगह-जगह दंगे करवाने शुरु कर दी है.

गोवा के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि - अगर जनता ऐसे ही मोदी जी को समर्थन मिलता रहा तो कुछ समय में भारत हिंदू राष्ट्र बन जायेगा. इससे भी आगे बढ़ते हुए विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने कहा कि भारत तो है ही हिंदू राष्ट्र और यहां रहने वाले सभी हिंदू है. इस संगठन का पहले भी नारा है कि -गर देश में रहना होगा, हिंदू बनकर रहना होगा! इस प्रकार ईसाईयों, मुस्लमानों में आतंक फैलाया जा रहा है. आदिवासी जातियों को जबरदस्ती हिंदू धर्म का ही हिस्सा बताया जा रहा है. वहीं पिछड़ी जातियों को भी धार्मिक भावनाएं भड़का कर बीजेपी हिंदूत्ववादी एजेंडे को लागू करवाने के लिए इस्तेमाल कर रही है. यूपी में जाट समुदाय और मुस्लमानों के बीच दंगे करवाने में सिधा सिधा नरेंद्र मोदी के सबसे नजदीकी नेता अमित शाह का हाथ है. चुनाव से पहले यूपी का उसे प्रभारी बनाया गया था. तभी से वहां दंगे भी शुरु हो गए थे.

जम्मू और कश्मीर को बांटने की पूरी तैयारी चल रही है. कश्मीरी पंडितों के अधिकारों के नाम पर वहां पर धार्मिक दंगो को भड़काने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है. इतना ही नहीं केंद्रीय बजट में कश्मीरी पंडितों की बस्ती बसाने के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसने का पूरा अधिकार है. लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार अलग से बस्ती बसाना चाहती है. यह ऐसा ही है जैसा फिलीस्तिन में इस्रायली यहूदी फासीवादी अलग से अपनी बस्तियां बसा रहे हैं और वहां की जनता पर अब बड़ा युध्द छेड़े हुए है. आगे जाकर मोदी की भी यही योजना है. इसलिए कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के नाम पर हिंदूओं की संख्या बढाने की योजना पर काम चल रहा है. इसलिए अभी वहां पर नए-नए हिंदूवादी संगठनों को बनाकर अनंतनाग यात्रा जैसे कार्यक्रम आयोजित करवाना शुरु कर दिये हैं.

हिंदू फासीवाद का खतरा केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं है. बल्कि असली खतरा शोसक-शासक वर्गों के खिलाफ, विदेशी व बहुराष्ट्रीय कंपनियों, उनकी बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के खिलाफ चल रहे तमाम जन अंदोलनों के लिए है. क्योंकि हिंदूत्व का एजेंडा केवल हिंदू राष्ट्र की स्थापना मात्र नहीं है. इसका असली मकसद देश के दलाल पूंजीपतियों-साम्राज्यवादियों व बड़े-बड़े जमींदारों की लूट को जारी रखना है. इसलिए आज तमाम साम्राज्यवादी देश नरेंद्र मोदी की तारीफों के पूल बांध रहे हैं. वहीं नरेंद्र मोदी सरकार बड़ी-बड़ी कंपनियों से समझौते कर रही है. अमेरीकी साम्राज्यवाद जो कल तक नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं देता था वह आज खुद चल कर उसके पास आ रहा है. क्योंकि अमेरीकी साम्राज्यवाद के हित यहां जुड़े हुए हैं. भारत की विशाल जनता व विशाल बाजार को लूटने के एड़ी-चोटी का जोर लगाए हुए है. देश में दमन बढ़ाने के लिए सेना के बजट में बड़ी बढ़ोतरी करते हुए उसे दो लाख नब्बे हजार करोड़ तक पहुंचा दिया है. वहीं तुरंत २१ हजार करोड़ के हथियार खरीदने की भी मंजूरी दी गयी है. पुलिस व अर्ध सैनिक बलों के आधुनिकरण के नाम पर कई हजार करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है. इसलिए आज तमाम प्रगतिशील, जनवादी, धार्मिक एकता की समर्थक, क्रांतिकारी ताकतों को एकजुट होकर लड़ने की जरुरत है. आज जरुरत है हिंदू फासीवादी खतरे के खिलाफ व्यापक संयुक्त मोर्चा बनाया जाये. धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने, उनके खिलाफ होने वाले दंगों से बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जाये. जन आंदोलनों के दमन के खिलाफ दमन विरोधी मोर्चा बनाया जाये. इस प्रकार हम अपने देश को दंगो व दमन की आग में डूबने से बचा सकते हैं. ✯

'जनसंग्राम' अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, डाउनलोड करने के लिए लॉगऑन करें :-

www.bannedthought.net/jansangram

इसके अलावा डीके एसजेडसी द्वारा प्रकाशित 'प्रभात', शहीदों की जीवनियों सहित पार्टी के अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों, पुस्तिकाओं, पर्चे, पोस्टरों को भी यहां से डाऊनलोड किया जा सकता है.

पाठकों से अपील

'जनसंग्राम' आपकी पत्रिका है, तमाम पाठक साथियों से अपील है कि पत्रिका के लिए आपके इलाके में जनता पर होने वाले दमन, प्रतिरोध, पीएलजीए के दुश्मनों पर हमलों, लुटेरी सरकारी नीतियों व विस्थापन के खिलाफ, जल-जंगल-जमीन के लिए उठने वाले आंदोलनों पर नियमित रिपोर्टस भेजें. पत्रिका पर अपनी सलाह, सुझाव व आलोचना भेजें!

संपादक मंडल - 'जनसंग्राम'

आखिरी पेज से जारी...

उसने सीआरसी, भाकपा माले जिसका नेतृत्व लिक्वाडेटनिस्ट के. वेनू और रेड फ्लैग के अवसरवादी केएन रामचंद्रन संसोधनवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी. और इस प्रकार इस प्रक्रिया का अंत हमारी दो पार्टियों - भाकपा माओवादी और भाकपा (एम-एल) नक्सलबाड़ी की एकता के रुप में हुआ है. इस प्रकार हमारी पार्टी और शक्तिशाली बनकर उभरी है. इस एकता ने निशन्देह इस को प्रमाणित कर दिया है कि - उत्पीड़ित जनता को शासक वर्गों व साम्राज्यवाद के खिलाफ दीर्घकालिन जनयुध्द में संगठित किया जा सकता और मालेमा व पार्टी की क्रांतिकारी लाईन का अमल करते हुए, संसोधनवाद व लिक्वाडेटीनिस्ट के खिलाफ संघर्ष करते हुए तमाम सच्ची माओवादी ताकतों को एक पार्टी में एकजुट किया जा सकता है, फिर भी इसके लिए शायद लंबा समय लग जाये. हमारी पार्टी इसके लिए गंभीर प्रयास जारी रखेगी कि अलग-अलग माले ग्रुपों में काम कर रही सच्ची क्रांतिकारी ताकतों को एकजुट किया जाये.

यह एकता भाकपा (माओवादी) को भारतीय क्रांति के हिरावल के तौर पर अपनी भूमिका को अच्छे से निभाने के लिए उसकी ताकत व क्षमता में इजाफा करेगी. दशकों के कठिन संघर्ष में हमारी पार्टी ने हजारों महान कम्युनिस्ट नेताओं के, लाल योध्दाओं के, उत्पीड़ित जनता के बलिदानों के दम पर भारत में जनयुध्द को खड़ा किया है, मध्य व पूर्वी भारत में उसे इस स्तर पर पहुंच दिया है जहां गुरिल्ला आधार है, क्रांतिकारी जन कमेटियों के रूप में लाल राजनीतिक सत्ता है, पीएलजीए व जन मिलिशिया इसकी रक्षा करती है. यह उपलब्धी घोर दमन अभियानों, और अभी जारी जनता पर युध्द - आपरेशन ग्रीनहंट के खिलाफ लड़ कर प्राप्त की है. आपरेशन ग्रीनहंट के तहत दसियों हजार जनता पर बर्बर हमले शासकों ने किये हैं, हत्याएं, बलात्कार, घरों को जलाना और फसलों को बर्बाद करना, जबरदस्ती विस्थापित करना और बहुत सारे पाशविक तरीके शोसक-शासकों ने अपनाए हैं. अब भारतीय राज्य सक्रियता के साथ हवाई हमले व स्थलीय हमले करने के लिए उसकी थल सेना व हवाई सेना के साथ अभ्यास कर रहा है. लेकिन इन खून हमलों के बावजूद दीर्घकालिन जनयुध्द लहरो की तरह आगे बढ़ रहा है. पश्चिम घाट के दक्षिणी हिस्से में हमारी पार्टी का अभी-अभी हुआ विस्तार इस बात का गवाह है कि क्रांति की ज्वालाएं तब तक शांत नहीं होंगी जब तक दक्षिण एशिया में साम्राज्यवाद के स्तंभ भारतीय राज्य को ध्वस्त न कर दिया जाये.

जब साम्राज्यवादी व उसके नौकर शासक वर्ग पूरी दुनिया में अभूतपूर्व संकट में फंस चुके हैं. पूरी दुनिया की परिस्थिति साम्राज्यवादी दुनिया में वर्ग संघर्षों, जनयुध्दों के अनुकूल हैं, जो माओवादी, साम्राज्यवाद विरोधी, व उत्पीड़ित देशों की अन्य ताकतों द्वारा चलाए जा रहे हैं. भारत में, एक तरफ भारतीय शासक वर्गों मध्य व पूर्वी भारत में उसके 4 लाख पाशविक बलों को तैनात कर दिया है. वहां पर वर्ग संघर्ष तीखे क्रांतिकारी गृहयुध्द की स्टेज में चला गया है, क्रांतिकारी विकल्प के तौर पर उभर रहा है, वहां पर व्यापक उत्पीड़ित जनता क्रांति से प्रभावित होकर पीएलजीए को मजबूत कर रही है और नये जनवादी राज्य की नींव रख रही है. दूसरी तरफ पश्चिम घाटों को सैनिक छावनी में बदली किया जा रहा है ताकि क्रांतिकारी सशस्त्र संघर्ष को पूरी तरह खत्म किया जा सके. शासक जनविरोधी भूमंडलीयकरण की नीतियों को लागू कर रहे हैं जिस कारण से मजदूरों, किसानों, आदिवासियों, दलितों, महिलाओं व अन्य उत्पीड़ित जनता के जुझरु, लड़ाकू संघर्ष दिन ब दिन बढ़ रहे हैं. इस स्थिति का उपयोग करके पार्टी क्रांतिकारी आंइदोलन को नई उंचाईयों पर ले जा सकती है व अपने अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकती है. इसके लिए लाखों लाख जनता को गोलबंद करना होगा, गुरिल्ला युध्द का विस्तार करना होगा और दुश्मन से मिल रही चुनौतियों का मुकाबला क्रांतिकारी आंदोलन को करना होगा.

अंत हमें हमारी पार्टी तमाम शहीदों के बलिदानों को याद करते हुए शपथ लेती है कि उनके खून से सने लाल झंडे को झुकने नहीं दिया जायेगा और इस एकता को क्रांति का शक्तिशाली हथियार बनाया जायेगा.

केंद्रीय कमेटी द्वारा जारी अंग्रेजी स्टेटमेंट पर आधारित रिपोर्ट.और जानकारी के लिए अंग्रेसी स्टेटमेंट देखें

www.bannedthought.net/cpi(maoist) 140501-CC-MergerDeclaration-Eng

देश से विदेशी-बहुर्राष्ट्रीय कंपनियों को मार भागओ!

सामंतवाद के खिलाफ 'जमीन जोतने वालों को' के नारे पर वर्ग संघर्ष तेज करो!

जनता को उजाड़ने वाली दलाल पूंजीपतियों की कंपनियों को मार भगाओ!

भाकपा (माओवादी) और भाकपा (एम-एल) नक्सलबाड़ी के विलय की घोषणा

माओवादी पार्टियों के विलय को ऊंचा उठाओ!..

21 सितंबर 2004 के दिन एक ऐसी खबर आई थी जिसने पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की माओवादी क्रांतिकारी ताकतों, उत्पीड़ित जनता के दिलों में खुशियों की लहर दौड़ा दी थी और शासकों के दिलों में हड़कंप मचा दिया था. उस खबर को सब जानते हैं, वह थी भाकपा (माले) (पीपूल्सवार) व माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया (एमसीसीआई) का विलय. उसके दस साल बाद फिर एक ऐसी ही खबर आई है जिसने पूरी क्रांतिकारी पांतों में खुशियों का संचार कर दिया है. यह खबर है कि भाकपा (माओवादी) और भाकपा (माले) नक्सलबाड़ी ने अपने विलय की घोषणा कर दी है. यह विलय 1 मई अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा दिवस के मौके पर हुआ. यह जानकारी अपनी-अपनी पार्टियों के प्रवक्ता कामरेड अभय व कामरेड क्रांतिप्रिया ने प्रैस विज्ञप्ति के जरिये दी. इस प्रैस विज्ञप्ति पर भाकपा (माओवादी) के महासचिव कामरेड गणपति व भाकपा (माले) नक्सलबाड़ी के सचिव कामरेड अजीत के हस्ताक्षर थे. स्टेटमेंट में लिखा है कि -

विश्व सर्वहारा के महान अंतर्राष्ट्रीय दिवस - मई दिवस के मौके पर, हम भारत के माओवादी, एक बड़ी जिम्मेदारी के एहसास व दृढ़ता के साथ भाकपा (माओवादी) और भाकपा (माले) नक्सलबाड़ी एक पार्टी के तौर पर विलय होने की घोषणा करते हैं, अब इसे भाकपा (माओवादी) के रुप में जाना जाये.

निश्चय ही इस एकता से भारतीय सर्वहारा वर्ग के हिरावल की ताकत बढ़ी है. भारतीय क्रांति और विश्व सर्वहारा क्रांति के लिए यह एकता और ताकत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी.

माओवादी आंदोलन 1967 के महान नक्सलबाड़ी विद्रोह से अभी तक जारी है. यह आंदोलन कामरेड चारुमजूमदार व कन्हाई चटर्जी की प्रेरणा व नेतृत्व से उभरा था, जो हमारी पार्टी के संस्थापक हैं. हजारों क्रांतिकारी नेताओं, कार्यकर्ताओं व जनता ने अपने जीवन का बलिदान देकर क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाया है और एक शक्तिशाली पार्टी का निर्माण किया है.

1970 के सेटबैक (पिछे हट) और कामरेड चारु मजूमदार की शहादत के बाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारी ताकतें अलग-अलग गुटों में बंट गयी थी. सच्ची क्रांतिकारियों ने अपने-अपने इलाकों में आंदोलन को खड़ा करने की कोशिशें की और साथ में एक पार्टी के तौर पर एकजुट होने की भी गंभीर कोशिशें की. चार दशकों की जद्दोजहद के बाद दो मुख्यधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी भाकपा (माले) (पीपूल्सवार) और एमसीसीआई का विलय होकर 21 सितंबर 2004 को भाकपा (माओवादी) का जन्म हुआ. दूसरी तरफ उसी समय नक्सलबाड़ी पार्टी ने भी सभी सच्ची माओवादी ताकतों से एकता के लिए गंभीर प्रयास जारी रखे.

शेष पीछले पेज पर जारी....